चौथी दुनिया

हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार

दिल्ली रविवार 6 सितंबर 2009

मूल्य 20 रुपये

भीतर

4 कभी हां, कभी ना

13 बलूचिस्तान के विद्रोही

14 ऊर्जा सुरक्षित करना मुख्य एजेंडा : पेट्रोलियम सचिव

भाजपा का बचना ज़रूरी है

मनीष कुमार

भारतीय जनता पार्टी शिमला में चिंतन बैठक के बाद पहले से ज़्यादा चिंतित, भ्रमित, असंगठित, दिशाहीन और बिखड़ी हुई नज़र आ रही है. चिंतन बैठक की आग से तप कर निकलने के बजाय पार्टी अब अपनी छवि को लेकर चिंतित है. विचारधारा को लेकर भ्रमित है, संगठन में सुधार कैसे हो, उसपर दिशाहीनता की स्थिति है, पार्टी के टूटने का ख़तरा है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि चिंतन बैठक में जिस तरह से नेताओं ने अपनी बातें कही, उससे यही कहा जा सकता है पार्टी पूरी तरह बिखरी हुई नज़र आ रही है. जिन्ना के बारे में जो बातें आडवाणी ने कहीं, वही बातें जसवंत सिंह ने अपने किताब में लिखी. दोनों ने एक ही जैसा काम किया लेकिन फर्क इतना है कि आज आडवाणी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और जसवंत सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया. हालांकि भाजपा के कई नेता, कुछ दबे और कुछ खुले स्वर में अब यह कहने लगे हैं कि यह सब आडवाणी जी और उनकी मंडली की वजह से हो रहा है. पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से यह साफ हो गया है कि पार्टी चंद नेताओं की जागीर बन गई है. ऐसे माहौल में पढ़े-लिखे, सौम्य, सीधे-सादे, अविवादित और शालीन किस्म के नेताओं को पार्टी में घुटन होने लगी है. हैरानी की बात है कि आडवाणी एंड कंपनी यह सुनने को भी तैयार नहीं है कि पार्टी में कुछ गड़बड़ी है. जो भी पार्टी की बीमारी की बारे में कहता है, पार्टी उसे ही बीमार बताती है और अनुशासन का डंडा दिखा कर उन्हें बेइज़्ज़त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती. लगता है कि पार्टी में हिटलर और स्तालिन किस्म के लोगों का राज है. प्रजातांत्रिक मूल्यों को मानना तो दूर भाजपा में आजकल फासीवाद का बोलबाला है.

हैरानी की बात यह है कि कल तक जो पार्टी के हर निर्णय में शामिल होते थे, बड़े बड़े फ़ैसलों में जिनकी राय ली जाती थी, जो चुनाव की रणनीति तय करते थे, वही लोग आज भारतीय जनता पार्टी को घटिया, खंडित, कठोर, तानाशाह और पूरी तरह अपनी विचारधारा के ही ख़िलाफ़ खड़ी पार्टी बता रहे हैं. कार्यकर्ताओं को अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा? समर्थकों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर उन्होंने ग़लती की है. भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह समझना मुश्किल हो गया है कि पार्टी को किस बीमारी ने अपनी चपेट में लिया है. दरअसल, भाजपा एक पुरानी बीमारी से पीड़ित है. यह पार्टी भस्मासुर पैदा करती है. इस पार्टी की चाल, चरित्र और चिंतन में ही ऐसा कुछ है कि जो भी सक्रिय होता है, पार्टी के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसी के हाथ-पैर काट दिए जाते हैं. उसे ही दरकिनार कर दिया जाता है. अटल और आडवाणी के दौर में कई नेता आए और गए, लेकिन इन दोनों को छोड़कर कोई दूसरा इस पार्टी को नेतृत्व देने में असफल रहा. अब ज़माना बदल गया है, लेकिन भाजपा की यह परंपरा जारी है. भाजपा की दूसरी पंक्ति के नेता पहली पंक्ति में आने को बेकरार है, इसलिए भाजपा में हर नेता, दूसरे नेता से प्रतिस्पर्धा कर रहा है. भाजपा के अंदर ऐसी लड़ाई चल रही है जिसमें हर कोई हर किसी के निशाने पर है. भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भाजपा की विचारधारा और आधुनिक भारत की सोच में विरोधाभास है साथ ही, पार्टी के संगठन और इसकी राजनीति में भी विरोधाभास है.

जसवंत सिंह और सुधींद्र के जाने के बाद पार्टी ने जो तर्क दिए, वे तो ज़ाहिर तौर पर शर्मनाक हैं. सुधींद्र ने जब इस्तीफा दिया तो, टेलीविजन चैनलों पर ख़बर चल रही थी कि भाजपा-सूत्रों ने कहा कि सुधींद्र तो भाजपा के सदस्य ही नहीं है. उनका तो भाजपा से कोई लेना-देना ही नहीं है.

यहां हमें यह कहना ही पड़ेगा कि भाजपा अजीबोगरीब पार्टी है. अगर वह भाजपा के सदस्य ही नहीं थे, तो आम चुनाव के दौरान भाजपा के वार रूम का संचालन कैसे कर रहे थे? वह कैसे चुनाव के दौरान भाजपा की रणनीति संबंधी बैठकों में निर्णायक भूमिका निभा रहे थे? जसवंत सिंह ने जब आडवाणी एंड कंपनी पर सवाल उठाए, तो पार्टी की तरफ़ से यह स्टोरी प्लांट की गई कि संसद में जसवंत सिंह का कमरा जा रहा है, इसलिए परेशान हो रहे हैं. अरुण शौरी ने राजनाथ सिंह और अरुण जेटली पर पार्टी को एक कटी पतंग बनाने का आरोप लगाया, तो अक्सर टेलीविजन पर नज़र आने वाले एक भाजपा नेता ने कहा कि राज्यसभा से उनकी विदाई के दिन क़रीब हैं, इसलिए वह पार्टी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं. इस तरह की दलील देकर भाजपा के नेता स्वयं कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी की छवि ख़राब करते हैं. भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की यह आदत बन चुकी है कि जब भी पार्टी के अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो वह अपने प्रभाव के ज़रिए मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट करवाते हैं. ग़ौर करने वाली बात यह है कि जिन नेताओं ने पार्टी के मंच पर आवाज़ उठाई, उन्हें सज़ा मिली. जो लोग अख़बार और ख़बरिया चैनलों में ख़बर प्लांट करते रहे, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई.

भाजपा ने अपनी करतूतों से भारतीय राजनीति को 30 साल पीछे धकेल दिया है. राजनीति शास्त्र की किताबों में 80 के दशक तक की भारतीय राजनीति को एक पार्टी के प्रभुत्व (वन पार्टी डोमिनेन्स) से व्याख्यायित किया जाता था. यह सच है कि देश की जनता दो-दलीय व्यवस्था चाहती है. पिछले कुछ दिनों से भाजपा में जो हो रहा है, उससे तो यह तय लगता है कि भविष्य में भारतीय राजनीति में दो-दलीय व्यवस्था होगी तो ज़रूर. बस, दूसरी पार्टी भाजपा नहीं, कोई और होगी. तीसरे और चौथे मोर्चे को कमर कस कर मैदान में उतरना होगा, ताकि देश में प्रजातंत्र का विकास हो सके.इन मोर्चों की समस्या यह है कि ये मोर्चे सिर्फ चुनाव के दौरान बनते हैं और नतीजे आने के बाद फिर से बिखर जाते हैं. इनमें सामंजस्य बिठाना बहुत ही कठिन है, इसलिए ही ये दल एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल सबित हुए हैं. भारत में प्रजातांत्रिक विकास के लिये यह ज़रूरी है कि भाजपा बची रहे. भाजपा को अगर बचना है तो इसके लिए भाजपा को कई पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा. नए विचार, नए तरीक़े को अपनाना होगा. भाजपा को बचने के लिए ऐसी विचारधारा को अपनाना होगा जो सभी धर्मों, समुदाय और जातियों को समाहित कर सके. वर्तमान नेताओं को स्वार्थ और आपसी स्पर्धा से ऊपर उठकर एकता बहाल करने और एक-दूसरे के विचारों को सम्मान देने की ज़रूरत है. संगठन में बदलाव लाना होगा, ताकि कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा जा सके, उनके मनोबल को ऊंचा रखा जा सके. संगठन में प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है. भाजपा को ख़ुद को बचाने के लिए एयरकंडीशन में बैठकर मीडिया के ज़रिए राजनीति करने वालों से बचना होगा. युवाओं, किसानों, मजदूरों और जनता के बीच काम करने वाले नेताओं को पार्टी में नेतृत्व देने की ज़रूरत है. छात्र राजनीति से युवा कार्यकर्ताओं को भाजपा में जगह देनी होगी. इक्कीसवीं सदी के भारत के लिए भाजपा का एजेंडा क्या है इस पर देश की जनता को साफ-साफ बताना होगा. भाजपा को उस सांप्रदायिक एजेंडे को छोड़ना होगा, जिसकी वज़ह से दूसरी पार्टियां समर्थन देने से मना करती हैं. अगर भाजपा ख़ुद को बदलने के लिए तैयार है, तो आने वाले समय में भाजपा फिर से खड़ी हो सकती है, अन्यथा धीरे-धीरे वे राज्य भी हाथ से निकल जाएंगे जहां इस वक़्त भाजपा की सरकार है. कमज़ोर भाजपा की वजह से देश का प्रजातांत्रिक विकास रुकेगा और देश में फिर से वन पार्टी डोमिनेन्स का दौर चल पड़ेगा जो देश में प्रजातंत्र के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है.

manish@chauthiduniya.com

भाजपा से वरिष्ठ नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है. कुछ को निकाला जा रहा है. कुछ पार्टी के अंदर घुटन महसूस करने की वज़ह से पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं. आने वाले दिनों में कुछ और नेता आडवाणी एंड कंपनी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले हैं. जब से यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और अरुण शौरी ने चुनाव में हार के लिए ज़िम्मेदार कौन का सवाल उठाया है, तब से पार्टी अंतहीन खेमेबाज़ी में फंस गई. कौन, किसे, कहां और कब निशाने पर ले लेगा यह किसी को पता नहीं. जिन्हें यह षड्यंत्रकारी राजनीति पसंद है वे पार्टी में मौजूद हैं और जिन्हें यह वातावरण पसंद नहीं है वे एक-एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर निष्क्रिय हो गए हैं.

भाजपा का डिज़ायनर हिंदुत्व

भाजपा का हिंदुत्व कहां है और कैसा है? हिंदुत्व तो कहता है- एकम सत् विप्राः बहुधा वदन्ति. मतलब यह कि सत्य तो एक है, लेकिन हर विद्वान इसकी व्याख्या अपने हिसाब से करता है. ऐसा करने के लिए वह स्वतंत्र भी है. असली हिंदुत्व अलग-अलग विचारों को समाहित करना है. उस पर विचार करना है. असली हिंदुत्व तो परमसत्ता, ईश्वर और वेदों पर सवाल उठाने वाले को भी बराबर की जगह देने और पूजने तक की परंपरा में विश्वास करता है. असली हिंदुत्व कहता है- आ नो भद्रा, रितवो यन्तु विश्वतः.. (लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम ऑल द वेक ऑफ लाइफ) मतलब यह, कि अच्छे विचार हरेक दिशा से आएं और हम उनका स्वागत करें. भाजपा कहती है कि उनका हिंदुत्व इंक्लुसिव (समावेशी) है. शायद भाजपा का समावेशी हिंदुत्व सिर्फ प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों को जवाब देने के लिए एक बहानेबाज़ी का औज़ार है. जो पार्टी अपने ही अंदर की आवाज़ को खारिज़ कर दे. बिना किताब पढ़े और उसका विश्लेषण किए उसे पार्टी से निष्कासित कर दे तो यही कहा जा सकता है भाजपा का हिंदुत्व नक़ली है. पार्टी जब अपने ही नेता के मतभेद को पचा नहीं सकती है, तो दूसरी विचारधारा को किस तरह से समाहित करेगी? जसवंत सिंह की जिन्ना पर किताब आई, तो भाजपा के नेता नाराज़ हो गए. यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि किताब में क्या लिखा है, किसी ने किताब भी नहीं पढ़ी और जसवंत को पार्टी से निष्कासित कर दिया. अरुण शौरी ने भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाए तो वह भी निशाने पर आ गए. भाजपा नेतृत्व ने पिछले कुछ सालों में यह तय कर दिया है जो भी आडवाणी एंड कंपनी पर सवाल उठाएगा पार्टी से उसे बाहर कर दिया जाएगा. नरेंद्र मोदी से जैसी अपेक्षा रहती है उन्होंने वही काम किया. जसवंत सिंह की किताब को गुजरात में प्रतिबंधित कर दिया. भाजपा शासित राज्य में भी किताब को बैन किया जाएगा तो किसी को ताज्जुब नहीं होनी चाहिए. वैसे भी संघ परिवार और भाजपा की किताबों से पुरानी दुश्मनी है. किताबों से संघ परिवार का रिश्ता सिर्फ प्रतिबंध करने और जलाने का है. यह परिवार ऐसा

(शेष पृष्ठ 2 पर)

चिंतन बैठक ने भाजपा की चिंता बढ़ाई

भाजपा पाताल लोक की ओर अग्रसर है. इसे कैसे बचाया जाए. चुनाव में हार के क्या कारण थे, पार्टी को फिर से कैसे मज़बूत किया जाए, विचारधारा को लेकर बनी भ्रामक स्थिति और इस तरह के तमाम सवालात को लेकर चिंतन बैठक बुलाई गई. लेकिन भाजपा ने सच का सामना करने से इनकार कर दिया. चिंतन बैठक ख़त्म हो गई, लेकिन देश भर के कार्यकर्ताओं और चिंतन बैठक में हिस्सा न लेने वाले भाजपा नेताओं को अब यह कभी पता नहीं चल पाएगा कि चुनाव में हार के कारण क्या थे? चिंतन बैठक की शुरुआत जसवंत सिंह के निष्कासन से हुई और समापन शर्मनाक रहा. तीन दिन के गहन चिंतन के बाद राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज ने मीडिया को जो कुछ बताया, वह हास्यास्पद है. उन्होंने जो कहा, उससे तो यही लगता है कि चिंतन बैठक में न तो भविष्य की रणनीति बनी, न ग़लतियों पर विचार किया गया. अब पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते राजनाथ सिंह ही बता सकते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह क्यों घोषणा की थी कि हार की वजहों का पोस्ट मार्टम चिंतन बैठक में किया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी के नेता न जाने किस युग में जी रहे हैं. शायद उन्हें लगता है कि जनता सिर्फ़ प्रेस कांफ्रेंस की बातों को ही सच मानती हैं, बाक़ी सब झूठ. हक़ीक़त यह है कि भाजपा के जो लोग चिंतन बैठक में मौजूद थे, शायद उन्हें यह पता न हो, मीटिंग की हर मिनट की ख़बर बाहर आ रही थी.

चिंतन बैठक के समापन के बाद सबसे पहला बयान था कि चिंतन बैठक में तय हुआ है कि आडवाणी पांच साल तक नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे. इस बयान से सवाल यह उठता है कि यह बात तो चिंतन बैठक के पहले ही आडवाणी ने ख़ुद ही यह ऐलान कर दिया था, तो चिंतन बैठक में इसकी चर्चा का मतलब क्या है. क्या सचमुच आडवाणी के नेतृत्व को लेकर चिंतन बैठक में बातचीत हुई? क्या अभी भी पार्टी में आडवाणी के नाम को लेकर विरोध है. पार्टी ने इस बैठक में तय किए गए

(शेष पृष्ठ 2 पर)

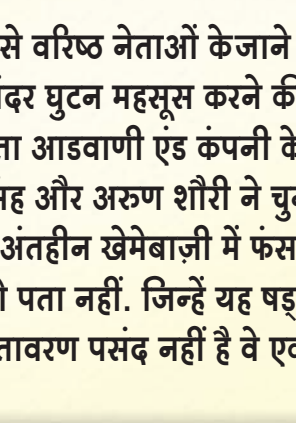

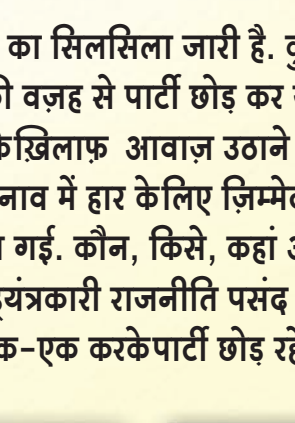

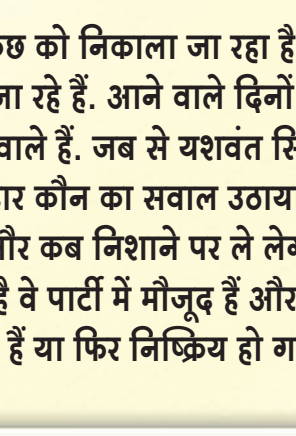

सभी फोटो- *प्रभात पाण्डेय*

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

माया के ताबड़तोड़ फ़ैसले

कुछ समय की शांति के बाद, एक बार फिर उत्तरप्रदेश के बाबू, मुख्यमंत्री मायावती के निशाने पर हैं. नोएडा भूमि आवंटन घोटाले में कथित तौर पर शामिल चार आईएएस अधिकारियों समेत कुल सोलह बाबुओं को उन्होंने निलंबित कर दिया है. यह घोटाला मुलायम सिंह के कार्यकाल में हुआ था, जिसमें पूर्व नोएडा चेयरमैन राकेश बहादुर को मुख्य अभियुक्त बनाया था. इसमें शामिल अन्य अधिकारियों में सेवानिवृत हो चुके तत्कालीन मेरठ प्रभागीय आयुक्त देवदत्त, नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव सरन, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी के. रविन्द्र नायक और उप कार्यकारी अधिकारी सी.पी.सिंह भी हैं. राज्य पुलिस में शीर्ष-स्तर पर भी काफी बदलाव किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने अपराध और क़ानून-व्यवस्था से जुड़े दो अतिरिक्त महानिदेशकों (एडीजी) की बहाली की है. इसके अलावा व्यापार-कर आयुक्त अनिल संत को मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव जे. एन. चैंबर की जगह लाया गया है. अब बहनजी का अगला क़दम क्या होगा, इसे लेकर उत्तरप्रदेश के बाबुओं में चिंता का सबब बना हुआ है.

उपयुक्त पद के हक़दार

अर्जुन सिंह से अपने तल्ख संबंधों के बाद लगता है, अब सैम पेत्रोदा के लिए अब राहत वाले दिन आने वाले हैं. ख़बर है कि उनको राष्ट्रीय सूचना राजमार्ग प्राधिकरण (एनआईएचए) का कार्यभार सौंपा जा सकता है. हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है. वैसे पेत्रोदा को ही नई(?) सरकार के लिए ई-गतिविधियों, जैसे ई-गवर्नेंस, ई-लर्निंग, ई-हेल्थ जैसे कार्यकर्मों की ज़िम्मेदारी मिलने की पूरी उम्मीद है. इसके पहले राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष के तौर पर पेत्रोदा की केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण समेत कई मुद्दों पर अर्जुन सिंह से मतभेद जगज़ाहिर थे. वह सारी बातें अब अतीत का हिस्सा बन चुकी हैं.

टेलिकॉम और आई.टी. क्षेत्र से तालमेल बिठाने को इच्छुक पेत्रोदा को भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन डाटाबेस अथॉरिटी के मुखिया नंदन निलकेणी की तरह कैबिनेट-स्तर का दर्जा हासिल होगा.

साउथ ब्लॉक

अंजुम ए ज़ैदी

निदेशक का कार्यभार संभालेंगे पद्मवीर

पद्मवीर सिंह मध्य प्रदेश काडर के 1977 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उनकी नियुक्ति मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के निदेशक के पद पर हुई है. वह रुद्र गंगाधरण का स्थान लेंगे. वर्तमान में सिंह अकादमी के पर्सनेल एंड ट्रैनिंग विभाग के विशेष निदेशक हैं.

रुद्र गंगाधरण चले पशु पालन विभाग

केरल काडर के 1975 बैच के आईएएस अधिकारी रुद्र गंगाधरण (लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के निदेशक) की नियुक्ति गोकुल राम की जगह पशु पालन विभाग में सचिव के तौर पर हुई है. वर्तमान में कृषि सचिव नंदकुमार ही पशुपालन विभाग के सचिव का कार्यभार देख रहे हैं.

बेविस ए चौतिन्हो को नया कार्यभार

बेविस ए चौतिन्हो कर्नाटक काडर के 1977 बैच के अधिकारी हैं. उन्हें नया कार्यभार दिया गया है. चौतिन्हो की नियुक्ति विदेश मंत्रालय के अंतर्गत इंटरस्टेट काउंसिल विभाग में अतिरिक्त सचिव के तौर पर हुई है. वर्तमान में वह कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि और सहकारिता विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं.

कांग्रेसी, वामपंथी शैली में रंगी भाजपा

भाजपा पर कांग्रेस और वामपंथियों की विचारधारा और सांगठनिक कार्यशैली हावी हो चुकी है. भाजपा के हाल के बयानों पर ग़ौर करें तो पार्टी अब हाईकमान, पार्टी लाइन, डेविएशन्स आदि-आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करती नजर आ रही है. वैचारिक पवित्रता का पाठ तो कम्युनिस्ट पार्टी में पढ़ाया जाता है. उनकी विचारधारा स्पष्ट है. पार्टी के नेता हों या कार्यकर्ता, सभी को पता होता है कि पार्टी की लाइन क्या है? वामपंथियों की भांति भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह पिछले कुछ दिनों से विचारधारा की पवित्रता की बात कर रहे हैं. इसी वजह से जसवंत सिंह को पार्टी से निष्कासित किया गया. लेकिन आडवाणी ने भी इसी लक्ष्मण रेखा को पार किया था, तब सब चुप रहे. यह भी कम्युनिस्ट पार्टियों जैसा ही कुछ है कि पोलित ब्यूरो का फ़ैसला अंतिम

और सर्वमान्य फ़ैसला होता है. इससे कोई दरकार नहीं कि फ़ैसला कितना सही है या कितना ग़लत. भाजपा का संसदीय बोर्ड भी पोलित ब्यूरो की तरह काम कर रहा है. आडवाणी जी को जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष चुना गया वह भी अजीबोगरीब है. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. आडवाणी जी को पार्लियामेंटरी बोर्ड ने न सिर्फ़ नेता प्रतिपक्ष चुना बल्कि उन्हें यह अधिकार भी दे दिया कि वह लोकसभा के उप-नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता चुन सकते हैं. न किसी सांसद को पूछा गया, न ही पार्टी में कोई बैठक हुई. जब पत्रकारों ने इस बात पर पार्टी से सफ़ाई मांगी तो अरुण जेटली का तर्क यह था कि पार्लियामेंटरी बोर्ड के पास कोई भी निर्णय लेने का अधिकार है. जसवंत सिंह के निष्कासन पर जेटली से पूछा गया कि बिना किताब पढ़े, बिना कारण बताओ नोटिस दिए और जसवंत सिंह को सफ़ाई देने का मौका दिए बगैर उन्हें कैसे निकाल दिया गया. तब भी उनका जवाब यही था कि बोर्ड कुछ भी कर सकता है.

अजीब सी बात है जिस बात को लेकर भाजपा अब तक कांग्रेस को कोसती आई है. वही सब बातें वह खुद दोहरा रही है. हाल में ही जब उत्तराखंड में खंडूरी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो बताया गया कि यह हाईकमान का फ़ैसला है. भाजपा में न जाने कब से हाईकमान का जन्म हो गया. कौन है यह हाईकमान? हो सकता है कि संघ के रूप में पहले से ही भाजपा में हाईकमान मौजूद था, लेकिन किसी को बताया न गया हो.

पिछले 25 सालों में भाजपा ने कई उतार चढ़ाव देखे. छोटी सी पार्टी से ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बन कर भी उभरी थी. अब यह पार्टी जिस राह पर चल पड़ी है वो विभाजन की तरफ जाता है. भाजपा की कार्यशैली बदली गई है. भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह बताते गर्व नहीं होता कि वो भाजपा के समर्थक हैं. वामपंथ और कांग्रेस की कार्यशैली अपना कर भाजपा अपनी साख खो रही है.

मनीष कुमार

manish@chauthiduniya.com

भाजपा का डिजायनर हिंदुत्व

पृष्ठ 1 का शेष

है, जहां पढ़े लिखों को तुच्छ निगाहों से देखा जाता है. किताब पढ़ने वाले लोगों को कामचोर और बकवास करने वाला बताया जाता है. मेरी बातचीत संघ के बहुत ही बड़े अधिकारी से हुई. बातचीत केदौरान उन्होंने हेडगेवार के जीवन की एक कहानी सुनाई. घटना नागपुर में संघ मुख्यालय की है. एक स्वयंसेवक किताब पढ़ रहा था. हेडगेवार ने उसे बुलाया और पूछा क्या कर रहे हो? उसने भोलेपन से जवाब दिया कि अमुक किताब पढ़ रहा हूं. उस स्वयंसेवक को लगा कि डॉक्टर साहब को किताब पढ़ना पसंद आएगा, उसकी छवि सुधरेगी लेकिन हेडगेवार नाराज़ हो गए और गुस्से से उसकी हाथ से किताब छीना और भट्टी में फेंक दी. स्वयंसेवक का दिमाग चक्कर खाने लगा कि किताब पढ़ना कैसे गुनाह हो गया? हेडगेवार ने उससे कहा, किताबों से दूर रहो, इससे दिमाग प्रदूषित होता है. स्वयंसेवक का असली काम संगठन बनाना है, शाखा लगाना है, किताब पढ़ कर विलासिता करना नहीं. संघ की सोच में जब किताब पढ़ना ही गुनाह है, तो जसवंत सिंह ने किताब ही लिख डाली. ऐसे में भला उन्हें कौन पार्टी में रहने देगा. हालांकि अपने निष्कासन केबाद जसवंत सिंह ने जिस सौम्यता से दुनिया का सामना किया उसके सामने भाजपा बहुत ही छोटी नजर आई. इस शर्मनाक फ़ैसले को सही बताने वाले प्रवक्ता दया के पात्र नज़र आए.

चिंतन बैठक ने भाजपा की चिंता बढ़ाई

पृष्ठ 1 का शेष

मुख्य बिंदुओं को मीडिया के सामने रखा. ये मुख्य बिंदु वही घिसी-पिटी बातें हैं जो राजनाथ सिंह और दूसरे प्रवक्ता चुनाव में हारने के बाद से दुहराते आए हैं. पहली बात यह कि पार्टी अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एकात्म मानववाद की विचारधारा पर अटल है. दूसरी यह कि पार्टी नए इलाक़ों में अपने सामाजिक आधार को बढ़ाएगी. महिलाओं, युवाओं और किसानों को पार्टी में आगे लाया जाएगा. एनडीए को मज़बूत किया जाएगा. राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि भाजपा केंद्र में एक ज़िम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगी और भाजपा शासित राज्यों की सरकार एक रोल मॉडल सरकार की तरह काम करेगी. साथ ही चिंतन बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता एक साधारण जीवन शैली व्यतित करेगें. भाजपा के प्रवक्ताओं के बयान से पता यही लगा कि चुनाव में हार की वजहों पर कोई बहस नहीं हुई. अगर चिंतन बैठक में इन बातों पर चर्चा हुई तो यह सवाल उठता है कि क्या भाजपा ने विचारधारा को छोड़ दिया था? क्या भाजपा अपना सामाजिक आधार बचाने और नए लोगों को पार्टी में आगे लाने में विफल रही? क्या भाजपा अब तक गैर ज़िम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही थी? अगर नहीं तो इन पर चर्चा होने की वज़ह क्या है? अगर इन विषयों पर चर्चा नहीं हुई तो क्या भाजपा ने चिंतकों ने प्रेस कांफ्रेंस के ड्राफ्ट को तैयार करने में तीन दिन लगा दिए. हक़ीक़त यह है कि भाजपा के चिंतन बैठक में चिंतन कम और सिर-फुटौव्वल ज़्यादा हुई. गुटबंदी का आलम यह था कि कोई गुट झुकने को

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

तैयार नहीं था. इसकी शुरुआत ही ऐसी हुई कि भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया. किताब का बहाना बना कर जसवंत सिंह को जिस तरह से निष्कासित किया गया उसी से भाजपा की पोल खुल गई कि विरोध में उठे हर स्वर को बंद कर दिया जाएगा.

चुनाव में हार के लिए जिसने भी आडवाणी गुट की भूमिका पर सवाल उठाए उसे योजनाबद्ध तरीक़े से चिंतन बैठक से बाहर कर दिया गया, लेकिन हार के कारणों का पता लगाने के लिए बनाई गई बाल आप्टे कमिटी ने चिंतन बैठक में जो रिपोर्ट में पेश की, उसमें उन्हीं कारणों का ज़िक्र किया जिन्हें जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उठाया था. पार्टी केपास सच का सामना करने की ताकत नहीं रही इसलिए भाजपा ने रिपोर्ट को मानने से इंकार कर दिया.

सूत्रों केमुताबिक चिंतन बैठक में बाल आप्टे केरिपोर्ट पेश करते ही हंगामा हो गया. अरुण जेटली, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू जैसे आडवाणी गुट केनेताओं ने रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया. चिंतन करने आए नेता बेकाबू हो गए और बहस छिड़ गई. आडवाणी जी बेबस बैठे रहे. ठीक उसी तरह, जब जिन्ना और पटेल केबहाने जसवंत सिंह को पार्टी से निष्कासित करने का फ़ैसला लिया गया. यह आरोप लगा कि रिपोर्ट मीडिया में कैसे लीक हो गई. चिंतन बैठक केदौरान ही भाजपा की आंतरिक रिपोर्ट टीवी चैनलों पर क्यों और कैसे दिखाई गई? भाजपा के प्रवक्ताओं ने मीडिया को बताया कि आंतरिक रिपोर्ट नाम की कोई चीज़ अस्तित्व में ही नहीं है, लेकिन इन प्रवक्ताओं ने नहीं बताया कि फिर बाल आप्टे इतने दिनों से क्या कर रहे थे? राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद राजनाथ ने यह क्यों कहा था कि राज्यों से रिपोर्ट आने के बाद पार्टी यह तय करेगी कि हार की वजह क्या है? असलियत यह है कि राज्य इकाइयों ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी. बाल आप्टे, चंदन मित्रा और मुरलीधर राव ने पूरी रिपोर्ट भी तैयार की. इसमें यह कहा गया कि हार केलिए ग़लत प्रबंधन, ग़लत उम्मीदवार, ग़लत नारे और ग़लत नेतृत्व ज़िम्मेदार है. मतलब यह कि पार्टी इकाइयों ने हार केलिए आडवाणी एंड कंपनी को ज़िम्मेदार माना. यहां पर यह भी समझना ज़रूरी है कि इस कमिटी केदो लोग बाल आप्टे और मुरलीधर राव का संबंध आरएसएस से ज़्यादा और भाजपा से कम है. शायद, भाजपा की आंतरिक रिपोर्ट संघ केविचारों को सामने रखती है. यही वजह है कि चिंतन बैठक केतीसरे दिन पार्टी ने प्रेस कांफ्रेंस में पहला संदेश यह दिया कि आडवाणी नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे. मतलब यह कि आडवाणी गुट ने यह साफ कर दिया कि उन्हें अब संघ की कोई ज़रूरत नहीं है. इसका नतीजा यह है कि अरुण शौरी ने आडवाणी एंड कंपनी केख़िलाफ़ हमला बोला, तो यह कहना नहीं भूले कि संघ ही इस कटी पतंग (यानी भाजपा) को थाम सकता है.

चौथी दुनिया
हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार

आर एन आई रजि.न.45843/86

वर्ष 23 अंक 25, 31 अगस्त-6 सितंबर 2009

प्रधान संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड केलिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन
चौधरी बिल्डिंग
कनाट प्लेस
नई दिल्ली 110001

फोन न.
संपादकीय +91 011 47149999
विज्ञापन +91 011 47149916
प्रसार +91 011 47149905
फैक्स न. +91 011 47149906

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनर्प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

राह भटक गया नक्सलवाद

रूबी अरुण

अपनी लड़ाई को जनांदोलन का रूप देने के लिए नक्सलियों ने यह तय किया था कि संगठन में महिलाओं की 40 फ़ीसदी भागीदारी रहेगी. इस पर अमल भी किया गया. जोशो–ख़रोश से महिलाएं शामिल भी हुईं. पर सामाजिक लड़ाई में सहभागी बनाने के बजाय उनकी इज़्ज़त से ही खेल शुरू हो गया. अब इस ख़ूनी आंदोलन में शरीक महिला नक्सली संगठन छोड़ कर भाग रही हैं, या फिर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दे रही हैं. समाज को बदल देने का सपना अब उनकी आंखों में नहीं पलता.

नक्सलवादी संगठन की सदस्य रह चुकी 29 साल की गीता दिल्ली के जंतर–मंतर के पास की एक दुकान पर बरतन धोने का काम करती है. गीता को सिफलिस है. झारखंड के दुमका की रहने वाली गीता भी सामंतवादियों से बदला लेने का सपना संजोए इस क्रांति में शामिल हुई थी. वह बताती है कि संगठन में रहते हुए उसके सपने तो सच नहीं हुए, अलबत्ता संगठन के कमांडर सहित अन्य सदस्यों ने अपनी हवस पूरी करने की ख़ातिर उसका इतना यौन उत्पीड़न किया कि वह सिफलिस की शिकार बन गई. आखिरकार एक दिन वह छिपते–छुपाते अपने एक साथी की मदद से भाग कर दिल्ली आ गई. बंदूक के दम पर दुनिया को बदलने का सपना ग़ायब हो चुका है. बची है तो बस दो वक़्त की रोटी की फ़िक्र. राजनांदगांव की रहने वाली 17 साल की ललिता एड्स की शिकार है. रांची के एक सरकारी अस्पताल में पिछले चार महीने से वह आधी बेहोशी में विक्षिप्त सी पड़ी है. उसकी देखभाल करने के नाम पर उसकी मां गोदावरी तो है पर लाचारी,ग़रीबी और उपेक्षा ने उसे भी जर्जर बना दिया है. दरअसल, ललिता की यह दिल दहला देने वाली हालत रक्त क्रांति के सेक्स क्रांति में तब्दील हो जाने का नतीजा है. ललिता देवकी दलम नाम के नक्सली संगठन की सदस्य थी. छत्तीसगढ़ के नक्सल कमांडर बुधु बेतलू की विधवा सोनू गावड़े की ज़िंदगी भी नरक बन चुकी है. दलम कमांडर बुधु की मौत के बाद संगठन के सदस्यों ने 24 साल की सोनू गावड़े के साथ महीनों दुष्कर्म किया. आख़िरकार गावड़े ने ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया. गावड़े ने पुलिस को बताया कि नक्सली संगठन में एक–एक महिला के साथ पांच–छह पुरुष ज़बरदस्ती करते हैं. इंकार करने पर उनके साथ जानवरों सरीखा व्यवहार होता है. नक्सली संगठनों की महिला कार्यकर्ताओं का संगठन के पुरुष सदस्यों द्वारा बर्बर तरीक़े से शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है. यौन प्रताड़ना से कहीं वे गर्भवती न हो जाएं इसकी ख़ातिर जबरन उनकी नसबंदी करा दी जाती है. यही नहीं, गांव गांव में फैले उनके एजेंट लंबी–चौड़ी कद काठी की लड़कियों की तलाश कर उन्हें बहला फुसला कर या फिर ज़बरन संगठन में शामिल कर लेते हैं. यह दौर सालों से जारी है. अकेली ललिता ही इस भयानक यंत्रणा की शिकार नहीं है. उसके जैसी सैकड़ों ललिताएं हैं जिन्होंने भूख और ग़रीबी से लोहा लेने और बंदूक की ज़ोर पर शोषक दुनिया को बदलने का सपना लिए रक्त क्रांति की दुनिया में प्रवेश किया. उन्हें लगा कि अपने विद्रोही तेवरों से वे दुनिया का रुख़ मोड़ देंगी. हालांकि, संगठन में शामिल होने के बाद उनकी ज़िंदगी का ही रुख़ बदल गया.

असुरक्षित और असामान्य सेक्स की वज़ह से नक्सलियों में एचआईवी वायरस तेज़ी से पैर पसार रहा है. इसकी वज़ह से कई नक्सलियों की मौतें भी हुई हैं. जंगलों में छुपने और भागते फिरने से नक्सलियों का इलाज भी नहीं हो पाता. फलतः वे इस भयावह बीमारी का प्रसार करने का ज़रिया बन जाते हैं. गढचिरौली के एसपी रह चुके राजेश प्रधान बताते हैं कि उनके सामने कई महिला गुरिल्लाओं ने इसीलिए आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि वे संगठन में अपने साथ हो रहे यौन उत्पीड़न से तंग आ चुकी थीं. संगठन में उनके साथ बंदूक की नोक पर बलात्कार किया जाता था.

चंपा, बबीता, आरती, शांति और संगीता पीडब्लूजी और एमसीसी की सदस्याएं हैं. बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश–इन चार राज्यों की पुलिस इनके ख़ूनी कारनामों से भय खाती थी. पर इनके साथ भी संगठन में जिस कदर यौनाचार होता था, वह दिल को दहलाने वाला है. उत्तर प्रदेश, बिहार–झारखंड सब जोनल कमेटी में फ़िलहाल 750 से ज़्यादा महिला सदस्य हैं. लगभग, सबकी व्यथा एक जैसी ही है. इसी साल फरवरी में एक ख़बर अख़बार की सुर्ख़ियां बनी थी. जिसमें बबीता और चंपा नाम की महिला काडरों के नाम का ज़िक्र था.

चंपा ने जब अपने साथियों को इंकार करना शुरू किया तो उसकी बेरहमी से पिटाई की गई. जबकि बबीता ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. उस वक़्त वह गर्भवती थी. जेल में ही उसने बच्चे को जन्म दिया. नक्सलियों के कुकर्मों से वो इतनी आजिज़ आ चुकी थी कि उसने अपने नवजात बच्चे को जेल के शौचालय में मिट्टी के घड़े में बंद कर मार डाला.

नक्सलवादी आंदोलन के नाम पर हर नाजायज़ व ग़ैर–क़ानूनी काम कर रहे हैं. नक्सलवादी आंदोलन के जनक कानू सान्याल नक्सलियों के इस नैतिक पतन और हवस को क्रांति कतई नहीं मानते . वे साफ कहते हैं कि आंदोलन अपना रास्ता भटक चुका है. कानू सान्याल नक्सलियों के इस पतन से बेहद दुखी हैं. उन्होंने इस बाबत कुछ नक्सली नेताओं से बात भी की है. उसके बाद इस सिलसिले में कुछ नए क़ानून भी बनाए गए हैं. ताकि महिला नक्सलियों का शोषण न हो सके. इस कड़ाई के बावजूद महिला नक्सलियों पर अपने ही साथियों का क़हर जारी है.

संगठन में शोषित, सरकार के लिए मुसीबत

शोषित और प्रताड़ित होने के बावजूद ये महिला नक्सली देश और सरकार के लिए खतरा बनी हुई हैं. नक्सली हमला हो या पुलिस से मुठभेड़. ये पुरूषों के मुक़ाबले ज़्यादा उग्रता और तीव्रता से टूट पड़ती हैं. नक्सली संगठन भी इनका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं. महिला नक्सलियों को आतंकवादियों की तर्ज़ पर ट्रेनिंग दी जा रही है. रॉ से मिली जानकारी के मुताबिक देश भर से सैन्य कद–काठी की चुनिंदा आदिवासी युवतियों को आंध्र प्रदेश के जंगलों में अत्याधुनिक हथियार चलाने और पुलिस से मुक़ाबला करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इन्हें छापामार युद्ध प्रणाली में भी पारंगत किया जा रहा है. उड़ीसा के दक्षिण–पश्चिम क्षेत्र के डीआईजी संजीव पांडा ने बताया कि प्रशिक्षण पाने वाली महिला नक्सलियों को दो समूहों में बांटा गया है. पहला समूह ख़ुफ़िया जानकारी जुटाता है जबकि दूसरा हमले करता है. ट्रेनिंग पाने वाली महिला माओवादी अपने पुरूष समकक्षों से ज़्यादा ख़तरनाक और कुशल हैं. मुश्किल तो यह है कि इन महिला माआवादियों की शिनाख्त में भी परेशानी होती है. पुरूषों की तुलना में ये संगठन के प्रति ज़्यादा वफ़ादार होती हैं. इसके अलावा ये पुरुषों की तुलना में लोगों से ज़्यादा आसानी से घुलमिल जाती हैं. सूचनाएं निकाल लेती हैं. हथियारों और अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ धड़ल्ले से एक जगह से दूसरी जगह आ–जा सकती हैं. लिहाज़ा नक्सलवादी संगठन नक्सली हमलों में भी इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. पिछले दिनों झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में जितनी भी नक्सली वारदातें हुई हैं, उनमें महिला नक्सलियों ने बढ़–चढ़ कर भागीदारी की है. छत्तीसगढ़ में नक्सल मामलों के डीआईजी पवन देव ने बताया कि पुरूष नक्सलियों की अपेक्षा महिला नक्सलियों से जूझना पुलिस बलों के लिए के लिए ज़्यादा चुनौती भरा है, क्योंकि ये बेहद आसानी से भीड़ में घुलमिल जाती हैं. बस्तर, दंतेवाड़ा, रायगढ़ ज़िले में इनका ज़्यादा बोलबाला है. पुलिस से बचने और सुरक्षित ठिकाने की गरज़ से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित जंगलों में इनका बड़ा ठिकाना है.

महिला बटालियन करेगी महिला नक्सलियों का सफाया

महिला नक्सलियों के ख़ात्मे के लिए महिला बटालियन और एटीएस यानी आतंकनिरोधी दस्ता मिल कर काम करेंगे. नक्सल ऑपरेशन में इनका काम अचूक हो, इसकी ख़ातिर इन्हें अम्लेश्वर महादेव घाट के कमांडो ट्रेनिंग और जंगल वार में प्रशिक्षित किया जाएगा. बुलेटप्रूफ जैकेट और सैटेलाइट फोन के साथ इन्हें हाईटेक किया जा रहा है. ऊंची जगहों पर सुरक्षा बलों का आपसी संपर्क टूट जाता है. जिसकी वजह से वे ज़रूरत के वक़्त अपने अन्य साथियों को मदद के लिए नहीं बुला पाते और नक्सलियों के हाथों अपनी जान गंवा बैठते हैं. सैटेलाइट फोन से उन्हें अपने साथियों के संपर्क में लगातार रहने में मदद मिलेगी. मुठभेड़ के दौरान घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों पर नक्सलियों के आक्रमण से वे किस तरह ख़ुद को सुरक्षित रखें, इसकी विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है. नक्सली आमतौर पर सुरक्षाबलों को चारों ओर से घेर कर गोलीबारी शुरू कर देते हैं. इससे सुरक्षाबलों में भगदड़ मच जाती है.

छत्तीसगढ़ में महिला नक्सलियों की भारी संख्या को देखते हुए महिला बटालियन को ख़ास तौर पर तैयार किया जा रहा है ताकि वे महिला नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें. जंगलों और पहाड़ियों पर सबसे ज़्यादा परेशानी सुरक्षा बलों को तब होती है जब वे मुठभेड़ के दौरान छुपने की सही पोजीशन नहीं बना पाते और नक्सलियों की गोलीबारी का शिकार हो जाते हैं. झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाक़ों में इस तरह की दुश्वारियां नहीं आती पर छत्तीसगढ़ में जवानों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इस बात को ध्यान में रख कर भी मुठभेड़ के गुर सिखाए जा रहे हैं.

महिला बटालियन को गुरिल्ला युद्ध के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है. फ़िलहाल इस ट्रेनिंग में चार सौ महिलाओं को शामिल किया गया है. आने वाले दिनों में इनकी संख्या में इज़ाफ़ा किया जाएगा. गृह मंत्री पी चिदंबरम ने इस योजना की रूप रेखा ख़ुद तैयार की है. वे लगातार इस मसले पर नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श कर रणनीति तैयार कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृहमंत्री पी चिदंबरम का भी मानना है कि नक्सलवाद हमारे देश में आतंकवाद से बड़ा मसला है. इसलिए इसका ख़ात्मा हर हाल में ज़रूरी है. इसमें अब सरकार कोई चूक नहीं करना चाहती.

मानव रहित विमान का इस्तेमाल करेगी सेना

नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने के लिए केंद्र सरकार अब सेना के मानवरहित विमानों का इस्तेमाल करेगी. सैन्य कार्रवाई से नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है. देश के भीतर हवाई ताक़त इस्तेमाल करने और नक्सलियों तथा उग्रवादियों की धर पकड़ करने से पूरा परिदृश्य ही बदलने लगा है. नक्सलियों के ख़िलाफ़ केंद्र सरकार का यह आक्रामक अभियान पूरी तरह से सैन्य अभियान है.

यह अभियान बेहतर ख़ुफिया जानकारी पर आधारित है. जिसके लिए पहली बार सेना के मध्य कमान ने नक्सलियों की गतिविधियों का पूरी सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया है. लोकसभा चुनावों के दरम्यान सेना ने मणिपुर में उग्रवादियों के एक शिविर पर मानवरहित विमान से हमला कर 11 उग्रवादियों को मार गिराया था. अब केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि नक्सल प्रभावित आठ राज्यों में वह इसी तरीक़े का इस्तेमाल करेगी. ख़ासकर दुर्गम ऊंची पहाड़ियों और बेहद घने जंगलों में. बिहार, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की गतिविधियों की टोह लेने के लिए भी हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है. लोकसभा चुनाव के दौरान भी वायु सेना के 27 हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई थी, जिसकी वजह से मतदान सुरक्षित तरीक़े से हो सका था. पिछले साल उड़ीसा में हुए एक बड़े नक्सली हमले में भी वायुसेना ने दो हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया था.

अब सरकार उसी योजना को बड़ा रूप दे रही है, ताकि नक्सलियों का पूरी तरह सफाया हो सके और कम से कम सुरक्षाबल हताहत हों . वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल फली होमी मेजर ने भी माओवादियों और उग्रवादियों से निपटने में वायुसेना का सक्रिय सहयोग देने की बाबत नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पूरा सहयोग देने की बात कही है. जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर हिस्से के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से भी सरकार ऐसे ही निपटेगी. हालांकि भौगोलिक तौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की स्थिति अलग है. नई रणनीति के तहत कुल 9000 जवानों को चुना गया है. इसके अलावा पारा मिलिट्री फोर्स की 24 अतिरिक्त बटालियनों को भी अलग से रखा गया है. बिहार में इस काम में सैप के जवानों को भी लगाया गया है.

कैबिनेट सचिव इस समस्या पर 12 सचिवों के साथ एक कमेटी बना का इस पूरी योजना को अंतिम रूप देने में लगे हैं. नक्सलियों के ख़िलाफ़ यह पूरा अभियान राज्यों और सैन्य बलों के पूरे तालमेल के साथ चलाया जाएगा ताकि चूक की कोई गुंजाइश न रहे. इस पूरे अभियान का नेतृत्व नवगठित शीर्ष कोबरा बल यानी कमांडो बटालियन फार रिसाल्यूट एक्शन करेगा. हालांकि विनायक सेन सरीखे समाजसेवी सरकार द्वारा की जा रही सैन्य कार्रवाई को आदिवासी समाज के लिए हितकर नहीं मानते.वे इसका यह कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि इससे लाखों आदिवासियों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी लेकिन सरकार अब इस पर नरम रूख़ कतई अपनाना नहीं चाहती.

नक्सली संगठनों की महिला कार्यकर्ताओं का संगठन के पुरूष सदस्यों द्वारा बर्बर तरीके से शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है. यौन प्रताड़ना से कहीं वे गर्भवती न हो जाएं इसकी ख़ातिर जबरन उनकी नसबंदी करा दी जाती है. यही नहीं, गांव गांव में फैले उनके एजेंट लंबी–चौड़ी कद काठी की लड़कियों की तलाश कर उन्हें बहला फुसला कर या फिर जबरन संगठन में शामिल कर लेते हैं. यह दौर सालों से जारी है. अकेली ललिता ही इस भयानक यंत्रणा की शिकार नहीं है. उसके जैसी सैकड़ों ललिताएं हैं जिन्होंने भूख और ग़रीबी से लोहा लेने और बंदूक की ज़ोर पर शोषक दुनिया को बदलने का सपना लिए रक्त क्रांति की दुनिया में प्रवेश किया.

ruby@chauthiduniya.com

माया की कभी हां, कभी ना

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर कभी हां कभी ना के नकारात्मक दौर से गुज़र रही है. दलितों के घरों में राहुल गांधी और सोनिया की दस्तक से बसपाई तिलिस्म टूट गया है. बौखलाई बसपा सुप्रीमो एक बार फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई है. इसमें एक क़दम आगे दो क़दम पीछे की रणनीति अपनायी जा रही है. प्रदेश विधानसभा के चार सीटों पर हुए उपचुनाव में तीन पर विजय हासिल करने से ख़ुश मायावती 2012 में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति में लग गई हैं. प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में यह सवाल बेहद आम है कि क्या बसपा अपने दबदबे को क़ायम रख सकेगी? वज़ह साफ है. पिछले ढाई वर्षों के शासनकाल में जो क़दम प्रदेश सरकार ने विकास के नाम पर उठाए हैं, उससे लोगों को निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा है. सवाल यह है कि आखिर आम जनता के लिये ढेर सारी कल्याणकारी योजनाएं क्यों नहीं लाई जा रहीं है? प्रदेश का युवा वर्ग बेरोज़गारी की वज़ह से जिस तरह परेशान है, इसके लिए क्या किया जा रहा है? प्रदेश में अपराध का ग्राफ क्यों नीचे नहीं जा रहा है?

तमाम विभागों में लूट का जो माहौल है, इसकी बानगी प्रदेश के मुख्यालय लखनऊ में देखने को मिली. राजधानी के इमराई नर्सिंग होम में बलरामपुर अस्पताल तथा डफरिन अस्पताल के लाखों रुपए की क़ीमती दवा बरामद की गई. जब राजधानी में ही मरीजों की दवा नर्सिंग होमों में जा रही तो दूर-सुदूर क्षेत्रों का हाल क्या होगा.

ग़रीब तबके की तारणहार साबित हुई नरेगा प्रदेश में पूरी तरह बेमानी साबित हो रही है. पिछले वर्ष सरकार नरेगा के लिए आवंटित धन का बीस प्रतिशत ख़र्च कर पाई. उत्तर प्रदेश सरकार इस वर्ष तो और भी पीछे है. नरेगा से कांग्रेस के बड़े जनाधार से

चिंतित प्रदेश सरकार के अधिकारी नरेगा को लागू करने में रुचि नहीं ले रहे हैं, बल्कि गांव-गांव के सरकारी स्कूलों पर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां लिखने की एक नई रणनीति बनाई गई है. इस रणनीति में कहीं केंद्रीय योजनाओं की लीपापोती कर उसी पर प्रदेश सरकार की योजनाएं लिखने की तैयारी है. क्या उत्तर प्रदेश, केंद्र और प्रदेश सरकार की आपसी जंग का शिकार होने वाला है. दिल्ली में मायावती ने प्रधानमंत्री से भेंट कर एक बार फिर सूखे से निपटने के लिए पैकेज की मांग की है.

माया सरकार के ठेके की खेती से चल कर एसईजेड, पुलिस भर्ती घोटाला, ताज एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्प्रेस-वे, सूचना के अधिकार क़ानून में छेड़छाड़ से लेकर ज़िलों में योजना के संबंध में कभी जिलाधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराना तो कभी प्रमुख सचिव के स्तर पर समीक्षा जैसे मामलों से लगने लगा है कि सरकार अपनी नीति और रीति पर क़ायम नहीं रहती है. समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी चुटकी लेते हुए कहते हैं कि प्रदेश सरकार का हाल अजीब है. जो आदमी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का घर जलाने का दोषी है. उसे इस सरकार में स्पेशल सुरक्षा के काबिल समझा जाता है और मंत्री पद देकर सम्मानित किया जाता है. आम जनता इस समय सूखे व महंगाई से त्रस्त है, इसके लिए कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है. हालांकि मुख्यमंत्री ने कुछ फ़ैसले लेकर सबकुछ दुरुस्त करने का संकेत दिया है.

पिछले दिनों सुश्री मायावती ने शासन स्तर पर विभागों की समीक्षा के लिए एक सितंबर से लागू होने वाली नई व्यवस्था की जानकारी देते हुए कहा कि आधे विभागों के प्रमुख सचिवों और सचिवों की समीक्षा बैठक हर माह की 15 तारीख को होगी. बाक़ी विभागों की समीक्षा अगले दिन 16 तारीख को की जाएगी. कमियां पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री अपने कार्यालय के अधिकारियों को ज़मीनी सच्चाई जानने के लिए आकस्मिक जांच के लिए भजेंगी और ख़ुद भी वह बिना बताए किसी भी ज़िले में जा सकती हैं.

मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों की शिकायतों की जांच करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि समीक्षा के लिए बनाई गई सेक्टर प्रभारियों की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है.

मीडिया में छप रही ख़बरों को ग़लत साबित करने की कोशिश में जुटी बसपा सुप्रीमो का उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से 20-20 मैच शुरू हो गया है. इसका परिणाम क्या होगा, यह तो आने वाला वक़्त ही बताएगा लेकिन 19 वर्षों से वनवास भोग रही कांग्रेस को अपना खोया हुआ जनाधार पाने का मौका मिला है. कांग्रेस इसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती है. राजनीति पर विकास की जीत के नाम पर कांग्रेस और बसपा की जंग अमेठी और रायबरेली से निकलकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक फैल चुकी है. प्रदेश में बसपा की गहरी हो चुकी जड़ों को खोदने के लिए राहुल गांधी का फॉर्मूला कारगर साबित हुआ है. दलितों के घरों में दस्तक और युवाओं को साथ लेकर बसपा की सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को लोकसभा चुनाव में मात दे चुके हैं. कांग्रेस के युवराज के क़दम रोकने के लिए बसपा ने भी कुछ सुविधाएं देकर लोगों को लुभाने की कोशिश की है. इनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को 5 लाख रुपए के सरकारी कार्यो में ठेकेदारी का अवसर प्रदान करने से लेकर इनकी योजनाओं का

फोटो- *प्रभात पाण्डेय*

औद्योगिक विकास के सब्ज़बाग

माया सरकार ने एक बार फिर जनता को सब्ज़बाग दिखाए हैं, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि जैसे प्रदेश में औद्योगिक निवेश की बारिश होने वाली है. प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक विकास के लिए औद्योगिक, सेवा क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने का फ़ैसला किया गया है. वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के लिए 50,882 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, इसके तहत शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, लोक निर्माण, पर्यटन, आवास, ऊर्जा व सिंचाई जैसे क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय किए गए हैं. इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से विभिन्न विभागों को आदेश भी दे दिए गए हैं.

इस मकसद से अवस्थापना एवं औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत लघु उद्योग (सूचना प्रौद्योगिकी और खादी एवं ग्रामोद्योग को जोड़कर), नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपीडा, भदोही आद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा), सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा), गोरखपुर औद्योगिक विकास (गीडा), लखनऊ औद्योगिक विकास प्राकिरण (लीडा) जैसी संस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है. वहीं सेवा क्षेत्र के तहत बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवहन, लोक निर्माण, उड्डयन, पर्यटन एवं संस्कृति, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास, ऊर्जा और सिंचाई विभागों को शामिल किया गया है.

वर्तमान वित्तीय वर्ष में लघु उद्योगों(सूचना प्रौद्योगिकी तथा खादी एवं ग्रामोद्योग को जोड़कर) के लिए 2500 करोड़ रुपए , नोएडा के लिए 1000 करोड़ रुपए, ग्रेटर नोएडा के लिए 4000 करोड़ रुपए, यूपीडा के लिए 3000 करोड़ रुपए, यमुना एक्सप्रेस-वे के लिए 2000 करोड़ रुपए, वीडा के लिए सात करोड़ रुपए, सीडा के लिए 36 करोड़ रुपए, गीडा के लिए 139 करोड़ रुपए, यूपीएसआईडीसी के लिए 1000 करोड़ रुपए, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च व प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा विभागों में प्रत्येक के लिए 2500 करोड़ रुपए, चिकित्सा शिक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 2000 करोड़ रुपए, परिवहन के लिए 2400 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग लिए 1000 करोड़ रुपए, पर्यटन एवं संस्कृति के लिए 500 करोड़ रुपए, आवास एवं शहरी नियोजन के लिए 10000 करोड़ रुपए, नगर विकास के लिए 5000 करोड़ रुपए, ऊर्जा के लिए 4300 करोड़ रुपए, और सिंचाई विभाग के लिए 1000 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया है. निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने की ज़िम्मेदारी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को सौंपी गई है.

पिछले दो दशकों में तमाम कताई मिलें या तो बंद हो चुकी हैं या बंदी की कग़ार पर हैं. पूर्वांचल का हथकरघा उद्योग तबाह हो चुका है. हर उद्योग बिजली की कमी, क़ानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव, बेमेल श्रम क़ानून और बुनियादी सुविधाओं के अभाव का दंश झेल रहा है. प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त कहते हैं कि प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहित किए जाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा प्रदेश के निर्यातकों के हित में एक्सपोर्ट फ्रेट सहायता, विपणन विकास सहायता, निर्यात पुरस्कार योजना एवं गोल्डन व सिल्वर कार्ड आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु फ्रेट सब्सिडी रूपये 1000 से बढ़ा कर रूपये 5000 प्रति कंटेनर कर दी गई है, साथ ही मासिक पत्रिका यूपी एक्सपोर्ट भी प्रकाशित की जा रही है. प्रदेश में निर्यात को और अधिक प्रोत्साहित किये जाने हेतु नोएडा, मुरादाबाद, कानपुर एवं भदोही में विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की स्थापना की जा रही है. इसके अतिरिक्त हस्तशिल्प निर्यात संबर्द्धन द्वारा ग्रेटर नोएडा में हस्तशिल्प निर्यात के प्रोत्साहन हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है तथा नोएडा में ही एक मल्टीप्रोडक्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना पर कार्रवाई प्रस्तावित है.

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों तथा संस्थाओं द्वारा प्रदेश में औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है.

बहुत मुश्किलें है इस राह में

उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के साथ नीति और नियम बदलने की परंपरा रही है. इसके कारण निवेश का माहौल संशय का शिकार होता रहा है. नोएडा में अनिल अंबानी ग्रुप के प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को मायावती सरकार द्वारा रद्द करने के फ़ैसले के साथ सौ करोड़ से ज़्यादा निवेश पर सब्सिडी नहीं देने तथा निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने पर ही छूट का ऐलान जैसे फ़ैसले निवेश के क्षेत्र में बड़ी बाधाओं के रूप में देखे जा रहे है.

विकास के लिए विदेश यात्राएं

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रदेश के नौकरशाहों और राजनेताओं ने देश-दुनिया की जितनी सैर कर डाली है, उतनी शायद किसी राज्य में नहीं की गई होगी. ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा, ब्राजील, नार्वे और स्वीडन जैसे विकसित देशों के अलावा अफ्रीकी देशों तक की यात्राएं की गई हैं. मुलायम सिंह और मायावती के शासन काल में सर्वाधिक यात्राएं हुई. रामप्रकाश गुप्त और राजनाथ सिंह के ज़माने में भी विदेश यात्रा करने वालों की कमी नहीं रही. मायावती ने जब दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला तो पूंजी निवेश कराने जापान और कोरिया की यात्रा पर गई. तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने दो दर्जन आईएएस अधिकारियों के साथ 24 यूरोपीय एवं अमेरिकी देशों का दो सप्ताह तक दौरा किया. हां, उसका नतीजा किसी से छिपा नहीं है.

क्या कहता है सर्वेक्षण

विश्व की प्रमुख सलाहकार फर्म डेलाइट टाश ने जो सर्वेक्षण किया है उससे तो यही लगता है कि अभी उत्तर प्रदेश में विकास की कवायद में प्रदेश की सात प्रमुख औद्योगिक जगहों-गाजियाबाद, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मुरादाबाद तथा वाराणसी के उद्यमियों को ही शामिल किया गया है. सर्वेक्षण में किसी भी प्रदेश में उद्योगों और निवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक औद्योगिक वातावरण को बताया गया है. हालांकि, प्रदेश के क़रीब 63 प्रतिशत उद्यमियों का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा उन्हें व्यवसाय में किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिलता. सबसे चौंकाने वाला जो तथ्य सामने आया है, वह राज्य की क़ानून एवं व्यवस्था है. सबसे अधिक 41 प्रतिशत उद्यमियों ने माना है कि प्रदेश की बदतर क़ानून एवं व्यवस्था इन्हें निवेश करने से रोकती है. इसके साथ ही आधारभूत ढांचा (32 प्रतिशत) और स्थानीय प्रशासन (12 प्रतिशत) भी सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कारकों में हैं. इससे जो स6बसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है, वह यह है कि उद्यमी प्रदेश में किसी भी तरह के निवेश के लिए प्रोत्साहन कर छूट और स्थानीय बाजार आदि से अधिक प्रशासन और आधारभूत ढांचे को महत्व देते हैं. 62 प्रतिशत उद्यमी बिजली को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हुए इसमें सुधार चाहते हैं. उद्यमी मानते हैं कि व्यापार कर विभाग इनके धंधे को सबसे अधिक प्रभावित करता है और प्रदेश के 25 प्रतिशत उद्यमी ही मानते हैं कि व्यापार कर विभाग संतोषजनक काम कर रहा है, 38 प्रतिशत इसके कामकाज को बेकार और 37 प्रतिशत असंतोषजनक मानते हैं. सरकारी विभागों में श्रम विभाग के कामकाज को सबसे ख़राब माना गया तथा उत्पाद शुल्क विभाग के कामकाज को सर्वोत्तम माना गया है. 51 प्रतिशत उद्यमी श्रम विभाग के कामकाज को बेकार मानते हैं, जबकि उत्पाद शुल्क विभाग को नाकारा मानने वाले उद्यमी केवल 10 प्रतिशत हैं. 74 प्रतिशत उद्यमी मानते हैं कि वैसे तो इंस्पेक्टर राज काग़ज़ों पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन व्यावहारिकता में यह अभी भी विद्यमान है. यह सर्वेक्षण भारतीय उद्योग परिसंघ ने करवाया है.

उद्योग के लिए प्राप्त सहमति-पत्र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की चौथी बार शपथ लेने के साथ मायावती ने गंगा एक्सप्रेस-वे की घोषणा के साथ 16 हज़ार करोड़ के निजी निवेश को अमंत्रित किया. पूर्ववर्ती मुलायम सिंह यादव सरकार में सर्वाधिक 40,725 करोड़ रुपए के सहमति-पत्र प्राप्त हुए हैं. ये इच्छा-पत्र अगस्त 2003 से सितंबर 2005 के बीच मिले हैं. इससे पहले मायावती के शासन काल में मई 2007 से अगस्त 2003 के बीच 2,103 करोड़, राजनाथ सिंह के समय में अक्टूबर 2000 से मार्च 2002 के बीच 3,282 करोड़, राम प्रकाश गुप्ता के समय में नवंबर 1999 से अक्टूबर 2000 के बीच 5,294 करोड़ और कल्याण सिंह के ज़माने में 9,524 करोड़ के इच्छा पत्र प्राप्त हुए थे. मुलायम सिंह सरकार को छोड़कर किसी भी सरकार में दस प्रतिशत इच्छा-पत्रों के मुताबिक़ उद्योग नहीं लग सके.

फूड प्रॉसेसिंग उद्योग की अपार संभावना है

उत्तर प्रदेश को निवेश बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ क़ानून व्यवस्था और विद्युत आपूर्ति को पहले पायदान पर रखना होगा तभी प्रदेश में नए उद्यमी आगे आएंगे. खनिज संपदा के दोहन और अन्वेषण के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, उनके अनुसार निवेश हो जाए तो उत्तर प्रदेश को देश का नंबर एक होने में देर नहीं लगेगी. अभी पिछले दिनों एक आर्थिक पत्रिका ने उत्तर प्रदेश को बीसवां नंबर दिया है, लेकिन पहला नंबर पाना ही होगा. यहाँ औद्योगिक जगत के लिए बिजली अत्यंत महत्वपूर्ण है. विद्युत की कमी से उद्यमी सफल नहीं हो पा रहे हैं. सरकार फ़ूड प्रॉसेसिंग नीति डेवलप करे, कृषि आधारित भूमि का सर्वे करे, ज़िले को आधार मानकर तय करे कि किस ज़िले में कौन-कौन सी फसलें और फल उत्पाद अधिक मात्रा में पैदा होते हैं, उसी स्थान पर प्रॉसेसिंग यूनिट स्थापित करने के अवसर सुलभ कराए तथा यह भी तय करे कि जो नीति बने, वह दीर्घ काल के लिए रहे. केंद्र सरकार बदलती रही है, मगर नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता है. लोकशाही में सरकार बदलती ही रहेगी. यह लोकतंत्र का तक़ाजा है और जनता के हित में है, लेकिन आर्थिक उत्थान के लिए सरकारों को स्थायित्व लाना होगा. जादुई चिराग के बल पर निवेश नहीं बढ़ता है.

माया नए तरीक़े से रखेंगी नज़र

राज्य सरकार इस बात का पूरा हिसाब लेगी कि सरकारी योजनाओं का कितना पैसा अनुसूचित जाति व जनजाति के हिस्से में ख़र्च हो रहा है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसके लिए मंडलायुक्तों व विभागीय प्रमुख सचिवों के लिए ख़ास प्रोफार्मा तैयार किया जा रहा है, जिसमें हर महीने ये सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी. पहली सितंबर से जो नई समीक्षा प्रणाली लागू होने जा रही है, इसमें एससी-एसटी से संबंधित योजनाओं तथा दूसरी योजनाओं में इन वर्गो के कल्याण पर ख़र्च होने वाले धन की समीक्षा पर विशेष ज़ोर रहेगा. दरअसल, राज्य सरकार इस बात से चिंतित है कि तमाम प्रयासों के बावजूद प्रदेश में ग़रीबों, ख़ासकर एससी-एसटी की आर्थिक स्थिति में अपेक्षानुसार सुधार नहीं हो रहा है. प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन और लागू करना प्रमुख है. हालांकि नरेगा की पूरी तरह से विफलता ने सरकारी मशीनरी की कलई खोल दी है. सपा के विधानमंडल दल के नेता शिवपाल सिंह यादव की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, वह कहते हैं- *माया सरकार को जनता के दुख-दर्द से कुछ भी लेना देना नही है. वह तो जनता के पैसे के बल पर दिल्ली की कुर्सी पर क़ाबिज़ होने की जुगत लगा रही थी लेकिन दिल्ली तो नहीं मिली, अब लखनऊ भी हाथ से जाएगा.*

feedback@chauthiduniya.com

अरूणाचल प्रदेश में मच सकती है तबाही

दिनकर कुमार

सुवनशिरि नदी के पानी से पनबिजली पैदा करने के लिए अरूणाचल प्रदेश के गेरूकामुख में 446 फीट ऊंचे बांध का निर्माण कार्य शुरू किया गया है. बांध के निर्माण के दौरान नदी के पानी की निकासी के लिए नदी के पूर्वी किनारे की तरफ़ पांच सुरंगों का निर्माण किया जाएगा. यह इलाक़ा असम में पड़ता है. पश्चिमी किनारे में निर्माणाधीन संयत्र में आठ टर्बाइन जेनेरेटर लगाए जाएंगे. हर जेनेरेटर की 250 मेगावाट का उत्पादन करेगा. एक तरफ़ तो केंद्र सरकार का यह तर्क है कि अरूणाचल प्रदेश और देश के आर्थिक विकास के लिए सुवनशिरि पनबिजली परियोजना ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ़ सुवनशिरि की घाटी, असम के उत्तरी लखीमपुर और माजुली के निवासियों की सुरक्षा और जीवित रहने के अधिकार का सवाल है.

सुवनशिरि की तरह अरूणाचल प्रदेश में हिमालय से उतरने वाली रंगा नदी में बांध बनाकर 405 मेगावाट के पनबिजली संयत्र की स्थापना की गई है. सुवनशिरि के मुक़ाबले रंगा नदी छोटी है, लेकिन इस छोटी नदी पर बांध बनने के चलते ही जून 2008 में असम के उत्तरी लखीमपुर ज़िले में तक़रीबन तीन लाख लोगों को बाढ़ की तबाही का सामना करना पड़ा. बारिश के मौसम में रंगा नदी में बहकर आने वाले पानी की मात्रा सुवनशिरि के पानी की मात्रा की तुलना में बेहद कम होती है. सुवनशिरि में प्रति सेकेंड 18,800 घनमीटर पानी बहकर आता है, जबकि रंगा नदी में प्रति सेकेंड 1529 घनमीटर पानी ही बहकर आता है. रंगा नदी पर बनाए गए 203 फीट ऊंचे बांध के ऊपर 57 फीट की ऊंचाई वाले पांच गेट बने हैं. सामान्य परिस्थितियों में रंगा नदी के पानी को इन दरवाज़ों के भीतर जलाशयों में ही रखा जाता है, लेकिन जब बाढ़ के समय पानी का स्तर 566 मीटर से ऊपर चला जाता है, तब गेट अपने आप खुल जाते हैं और सारा पानी बांध के ऊपर से बहकर आ जाता है. नदी में बाढ़ कभी दिन में आती है तो कभी रात में. इस तरह अतिरिक्त पानी निकलने से निचले इलाक़े में स्वाभाविक रूप से तबाही मच जाती है, लेकिन नीपको ने बाढ़ पीड़ितों को मुआवज़ा देने का कोई प्रावधान नहीं बनाया है.

सुवनशिरि पर बन रहे बांध को लेकर पर्यावरणविद आशंकित हैं. उनका कहना है कि इस नदी का चालीस फ़ीसदी हिस्सा चीन में है. बाढ़ के समय सुरक्षा के हिसाब से यह बात ख़तरनाक साबित हो सकती है. एक उदाहरण से इस बात की गंभीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. 11 जून 2000 को अरूणाचल प्रदेश के अपर सियांग और ईस्ट सियांग ज़िले में सियांग नदी में अचानक बाढ़ आ गई. एक सौ फीट ऊंची पानी की धारा ने चारों तरफ़ तबाही मचा दी. उस समय अरूणाचल प्रदेश या उत्तरी तिब्बत में बारिश भी नहीं हुई थी.

सुवनशिरि पर बन रहे बांध को लेकर पर्यावरणविद आशंकित हैं. उनका कहना है कि इस नदी का चालीस फ़ीसदी हिस्सा चीन में है. बाढ़ के समय सुरक्षा के हिसाब से यह बात ख़तरनाक साबित हो सकती है. एक उदाहरण से इस बात की गंभीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. 11 जून 2000 को अरूणाचल प्रदेश के अपर सियांग और ईस्ट सियांग ज़िले में सियांग नदी में अचानक बाढ़ आ गई. एक सौ फीट ऊंची पानी की धारा ने चारों तरफ़ तबाही मचा दी.

उस समय अरूणाचल प्रदेश या उत्तरी तिब्बत में बारिश भी नहीं हुई थी. फिर भी लोगों के घर, पेड़-पौधे उजड़ गए. सामरिक रूप से महत्वपूर्ण तीन पुल भी बह गए. 36 व्यक्तियों की डूबने से मौत हो गई. सरकार ने इस अप्रत्याशित बाढ़ के कारण का पता लगाने का ज़िम्मा इसरो को सौंपा. सेटेलाइट की मदद से इसरो ने पता लगाया कि चीन में सियांग नदी पर एक बांध टूट गया था, हालांकि चीन ने इस ख़बर का खंडन किया. हालांकि, जानकारों के मुताबिक अरूणाचल प्रदेश पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए चीन ने जानबूझ कर एक बांध तोड़ दिया था. अगर चीन सुवनशिरि के बांध के साथ भी इसी तरह खिलवाड़ करेगा तो उसका ख़ामियाज़ा अरूणाचल प्रदेश और असम की आम जनता को भुगतना पड़ सकता है.

सुवनगिरी नदी

जानकार अरूणाचल प्रदेश के प्राकृतिक परिवेश को अस्थिर (अनस्टेबल) का दर्जा देते हैं. उनका कहना है कि यह क्षेत्र भूकंप के लिहाज़ से बहुत संवेदनशील है. ऐसी हालत में पर्यावरण और भौगोलिक संतुलन में मामूली परिवर्तन करने से भयंकर नतीजे सामने आ सकते हैं. इसीलिए पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों से मिट्टी काटने, नदी के पानी को बांध बनाकर रोकने, पानी में रेत और पत्थर जमा करने, भूमिगत जल-स्तर से छेड़छाड़ करने और जंगलों को काटने के काम में सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

अरूणाचल प्रदेश के इलाक़े में हिमालय की भौगोलिक बनावट असाधारण है. 7756 मीटर ऊंचे नामचा-वारवा नामक पहाड़ को हिमालय के मध्य में स्थित गांठ माना जाता है, जहां हिमालय से मुड़ता है.

नामचा-वारवा पहाड़ हर साल तीन से पांच मिलीमीटर ऊंचा होता जा रहा है. इसके साथ ही हिमालय की चोटियों की ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है. इस बदलाव के साथ ही भू-स्खलन की रफ़्तार भी तेज़ हो गई है. भू-स्खलन के चलते रेत बहकर नदियों में जमा होती है, जो नदियों की जल-वहन क्षमता घटाती है और बाढ़ के ख़तरे को और बढ़ा देती है.

इस बात के कई उदाहरण हैं कि जब नदी के सीने पर ऊंचे बांध बनाए जाते हैं तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगता है. साथ ही सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याएं भी पैदा होती हैं. जानकार मानते हैं कि अरूणाचल प्रदेश में ऊंचे बांधों का निर्माण करना तबाही को निमंत्रण देना है. उनका कहना है कि छोटे-छोटे बिजली संयत्र बनाकर बिजली की ज़रूरत पूरी की जा सकती है और तबाही से भी बचा जा सकता है.

केंद्र सरकार ने बड़े बांधों के निर्माण के संदर्भ में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू कर रखा है. इस अधिनियम के तहत पनबिजली परियोजना को मंज़ूरी देने से पहले पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है. परियोजना को मंज़ूरी देने से पहले सरकार की तरफ से इसी रिपोर्ट के आधार पर जन सुनवाई आयोजित की जाती है. सुवनशिरि बांध संबंधी रिपोर्ट तैयार करने का काम ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने वेपकोस नामक प्रतिष्ठान को सौंपा था, जिसने एक साल बाद रिपोर्ट तैयार कर जमा कर दी थी.

हालांकि, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किस आधार पर किया गया, इसकी जानकारी लोगों को नहीं दी गई. दिसंबर 2002 में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसका विरोध कई जन संगठन कर रहे हैं. उनका आरोप है कि जन सुनवाई के नाम पर महज़ नाटक किया गया और आम जनता के विरोध को दर्ज़ नहीं किया गया. कई जन संगठन बांध के विरोध में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर इस विरोध का कोई प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

मणिसेना आयोग से बिदकी भाजपा और एएसडीसी

राजनीति दलों और राजनेताओं के साथ उग्रवादी संगठनों की सांठगांठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है. असम में पिछले दो दशकों से जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें राजनीतिक दलों और उग्रवादी संगठनों पर एक-दूसरे की सहायता करने के आरोप लगते रहे हैं. असम के उत्तर कछार पर्वतीय ज़िले में उग्रवादी संगठन डीएचडी के ज्वेल गुट और नूनीसा गुट ने हत्या, अपहरण, धनउगाही आदि हिंसक गतिविधियां चलाकर जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर रखा है और ज़िले में क़ानून व्यवस्था की स्थिति शोचनीय बनी हुई है. मीडिया में मामला उछलने के बाद असम की तरुण गोगोई सरकार ने उत्तर कछार स्वशासी ज़िला परिषद और उग्रवादी संगठनों के बीच सांठगांठ के आरोप की जांच करने के लिए मणिसेना आयोग का गठन किया था. आयोग ने जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली है और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर कछार स्वशासी ज़िला परिषद की तरफ़ से उग्रवादी संगठनों को दो करोड़ रुपये दिए गए थे. स्वशासी परिषद में एएसडीसी और भाजपा गठबंधन का शासन था, जिसने विकास मद में आवंटित रक़म में से दो करोड़ रुपए डीएचडी (जे) उर्फ़ ब्लैक विडो नामक उग्रवादी संगठन को दिए थे. रिपोर्ट सौंपने के बाद एएसडीसी ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर सफाई दी है कि उग्रवादी संगठन को धन देने का आरोप मनगढ़ंत और बेबुनियाद है और असम की कांग्रेस सरकार के इशारे पर आयोग ने उसे फंसाने की कोशिश की है. एएसडीसी के नेता प्रकांत वारीसा ने कहा कि उनके दल का डीएचडी (जे) के उग्रवादियों से कोई संबंध नहीं है और राजनीतिक साज़िश के तहत आयोग ने ऐसी रिपोर्ट बनाई है. आरोप को साबित करने के लिए आयोग के पास किसी तरह का प्रमाण नहीं है. एएसडीसी नेताओं का तर्क है कि जब भी उत्तर कछार स्वशासी ज़िला परिषद में ग़ैर-कांग्रेसी सरकार बनती है, तब कांग्रेस इसी तरह की जांच थोपकर ग़ैर-कांग्रेसी सरकार को जनता के बीच बदनाम करने की चाल चलती है. जबकि कांग्रेस के शासन काल में परिषद में होने वाले भ्रष्टाचार, उग्रवादियों के साथ सांठगांठ आदि मामलों की कभी जांच नहीं करवाई जाती. एएसडीसी ने आरोप लगाया है कि असम के पूर्व राज्यपाल अजय सिंह ने कोयला माफिया आर एस गांधी का एक करोड़ रुपए का बिल पास करने के लिए स्वशासी परिषद पर दबाव डाला था. एएसडीसी ने राज्यपाल की बात मानने से इंकार कर दिया और इसी बात को लेकर राज्यपाल स्वशासी परिषद से नाराज़ हो गए. एएसडीसी के इस आरोप से राज्य के संवैधानिक पद के शीर्ष पर बैठने वाले महामहिम की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है. एक कुख्यात कोयला माफिया को धन दिलाने के लिए राज्यपाल का दबाव डालना लोकतांत्रिक सरकार के लिए शर्मनाक बात हो सकती है.

डीएचडी (जे) का मुखिया ज्वेल गारलोसा

सेवानिवृत न्यायाधीश मणिसेना सिंह की अध्यक्षता वाले आयोग की रिपोर्ट ने भाजपा को भी परेशान कर दिया है. असम प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता चरण डेका ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार के चलते ही देश में उग्रवादी संगठनों का जन्म हुआ है.

सेवानिवृत न्यायाधीश मणिसेना सिंह की अध्यक्षता वाले आयोग की रिपोर्ट ने भाजपा को भी परेशान कर दिया है. असम प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता चरण डेका ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार के चलते ही देश में उग्रवादी संगठनों का जन्म हुआ है. उन्होंने कहा कि उग्रवादियों की सहायता से ही कांग्रेस चुनावी राजनीति करती रही है. उन्होंने आयोग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताया. भाजपा का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है. जिसे कांग्रेस के इशारे पर भाजपा और एएसडीसी गठबंधन को बदनाम करने के लिए तैयार किया गया है. भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ख़ुद 2001 से उग्रवादियों की मदद लेकर सत्ता में बनी हुई है. भाजपा ख़ुद को उग्रवाद विरोधी पार्टी मानती है और उसने स्पष्ट किया है कि उत्तर कछार में उसने उग्रवादियों के साथ किसी तरह की सांठगांठ नहीं की. दूसरी तरफ एएसडीसी ने मांग की है कि असम में 1990 से अब तक राजनीतिक दलों और उग्रवादी संगठनों के बीच रिश्ते की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. मणिसेना आयोग की रिपोर्ट को भाजपा और एएसडीसी ने सिरे से नकार दिया है. आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में अनुमोदित नहीं किया गया है. हालांकि, इससे पहले भी दर्ज़नों मामलों की जांच अलग-अलग आयागों द्वारा करावाई जा चुकी है. अक्सर ऐसी जांचों का कोई कारगर नतीजा सामने नहीं आता है. जांच रिपोर्टों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर सत्ताधारी दल ऐसी रिपोर्टों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में करती है.

एक सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित आयोग की रिपोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर भाजपा और एएसडीसी बदनामी की कालिख से अपने आपको बचा नहीं सकती. असम में राजनेताओं और उग्रवादियों के बीच घनिष्ठता कोई नई बात नहीं है. आरोप मीडिया में समय-समय पर उछाले जाते रहे हैं, लेकिन पर्याप्त प्रमाण नहीं होने और सरकारों की निष्क्रियता के कारण इस तरह के रिश्तों की जांच ठीक से नहीं होती रही है. कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मामले में ख़ुद को पवित्र होने का दावा नहीं कर सकती. जनसेवा की जगह जनता के विकास के लिए आवंटित धन को लूटना ही जब राजनेताओं का एक मात्र उद्देश्य बन जाएगा, तब इसी तरह की सांठगांठ के ज़रिए विकास मद के धन की बंदर-बांट होती रहेगी.

इसमें कोई दो राय नहीं कि उग्रवाद एक ऐसा व्यापार बन गया है, जिससे उग्रवादी तो फ़ायदे में रहते हैं, साथ ही साथ पार्टियां भी उग्रवादियों को धन देकर उनका इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए निजी सेना के रूप में करती है.

दिनकर कुमार

feedback@chauthiduniya.com

एक साथ दो मोर्चों पर नहीं लड़ेगी सपा

अजय कुमार

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आग़ाज तो धमाकेदार हुआ, लेकिन आख़िरी दिन जब अधिवेशन अपने अंज़ाम पर पहुंचने वाला था तभी एक बुरी ख़बर ने अधिवेशन में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं का मूड बिगाड़ दिया. ख़बर ऐसी कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की दहाड़ धीमी पड़ गई, अन्य नेता आपस में कानाफूसी करने लगे. उत्तर प्रदेश की चार विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई, वह मलीहाबाद और विधूना की अपनी सीटें भी नहीं बचा सकी, जबकि इसकी प्रतिद्वंद्वी पार्टी बसपा ने तीन सीटें जीत कर इतिहास रच दिया.

21 अगस्त को वोटों की गिनती शुरू होते ही सपा के चोटी के नेता रुझान का पता करने में जुट गए, लेकिन मतदान स्थल से आ रही ख़बरों ने सबको मायूस कर दिया. मलीहाबाद और विधूना में सपा की हार इस लिए भी मायने रखती हैं, क्योंकि यहां से इसके विधायक बसपा में चले गए थे और हाथी के चुनाव चिह्न पर मैदान में उतरे थे, सपा ने दोनों को धोखेबाज़ करार देते हुए इन्हें सबक सिखाने का नारा दिया था. सपा की हार तो हुई ही, उसके लिए इससे भी दुखद यह भी रहा कि सपा चार में से दो सीटों (मलीहाबाद और मोरना) में तीसरे नंबर पर पहुंच गई, वहीं मुरादाबाद पश्चिम में तो इसे चौथे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा. सिर्फ़ विधूना में ही सपा की प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहीं. मुस्लिम वोट बैंक सपा से इस बार भी दूर जाता दिखाई दिया. मुलायम सिंह ने भी मौक़े की नज़ाकत समझने में देर नहीं लगाई. उन्होंने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बसपा सरकार ने उपचुनावों में वोट ख़रीदे हैं. ज़िलों के डीएम और पुलिस कप्तान ख़ुद बसपा की जीत सुनिश्चित कराने में लगे रहे.

मुलायम ने बसपा की सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए 19 से 23 जनवरी 2010 तक जेल भरो आंदोलन चलाने की घोषणा की तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने दो-टूक कह दिया कि हमारी जेलों में बहुत जगह है, हिम्मत हो तो भरकर दिखाएं. मायावती कहती हैं कि-जनता बसपा सरकार के साथ है. उपचुनाव के नतीज़े इस बात का सबूत हैं. इन नतीज़ों ने सपा और कांग्रेस दोनों के दुष्प्रचार की हवा निकाल दी है.

बहरहाल, सपा के आगरा अधिवेशन का निचोड़ निकाला जाए तो कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अपना विज़न बदलने वाली है. नए कलेवर में वह केंद्र की मनमोहन और उत्तर प्रदेश की माया सरकार, दोनों से ही दो-दो हाथ करती नजर आएगी. संकेत यह भी हैं कि धरती पुत्र मुलायम दोनों सरकारों के ख़िलाफ़ ज़मीनी लड़ाई लड़ने के लिए अब अपने संगी- साथियों पर कम विश्वास करेंगे और स्वयं मैदान में उतरेंगे. ज़रूरत पड़ी तो जेल भी जाएंगे और लाठियां भी खाएंगे. सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुलायम ने जो तेवर दिखाए इससे तो यही लगता है कि काफी समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति से अपने आप

फोटो-*सुनील मल्होत्रा*

केंद्र सरकार को समर्थन देने की अपनी मजबूरी से वह आगरा में भी पीछे नहीं हट पाए. आगरा में कई महत्वपूर्ण समाजवादी चेहरे नदारद रहे. इसमें कई मुस्लिम चेहरे भी थे जो कल्याण के कारण सपा का साथ छोड़ चुके थे. बदले-बदले माहौल में हुए अधिवेशन में भगवा से लाल हुए कल्याण पिछड़ों को एकजुट करने के लिए हुंकार भरते नज़र आये. महासचिव अमर सिंह ने सिंगापुर से टेप किया अपना भाषण भेज कर अधिवेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. मुलायम, अमर, कल्याण और अखिलेश यादव सभी के तेवरों में कांग्रेस और बसपा के लिए तल्खी दिखाई दी, वहीं परंपरागत रूप से सपा के निशाने पर रहने वाली भाजपा को इस लायक़ भी नहीं समझा गया कि इसके बारे में ज़्यादा माथापच्ची की जाती.

वैसे भाजपा के कमज़ोर होने का मलाल सपा से ज़्यादा शायद ही किसी को होगा, सपा प्रमुख जानते हैं कि भाजपा का हिंदुत्व समाजवादी पार्टी के लिए टॉनिक का काम करता था. भाजपा का हौआ दिखा कर सपा वर्षों से अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़े हुए है. भाजपा के कमजोर होते ही सपा को अपने इस परंपरागत वोट बैंक को बचाए रखने में एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाना पड़ रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

बदले-बदले कल्याण

राजनीति की लंबी पारी भगवा चोला ओढ़ कर खेलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के बागी नेता कल्याण सिंह जीवन संध्या में लाल हो गए. लंबे समय तक भाजपा के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक रहे कल्याण सपा अधिवेशन में भाजपा को कोसते समय यह भी भूल गए कि इनकी नीतियों पर चल कर ही भाजपा ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में डंका बजाया था. आज भले ही वह सपा में हों लेकिन वह अपने को उनसे अलग नहीं कर सकते हैं, जो आज हिंदू-मुसलमानों को लड़ाने वाला बता रहे हैं. इनकी यह मजबूरी ही है कि इन्हें बार-बार सफ़ाई देनी पड़ रही है कि अब वह सपाई हो गये हैं. कल्याण को आज भी सपाई पचा नहीं पा रहे हैं. यही वजह है कि भाजपा का यह बाग़ी नेता सपा के मंच पर विराजमान था, लेकिन सपा नेता और कार्यकर्ताओं में इनके प्रति कोई उत्साह नहीं था. सपा के अधिवेशन में बतौर विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में आये कल्याण की मंच पर इस समय एंट्री हुई जब पार्टी का झंडा फहरा कर सपाई पार्टी का गीत गा रहे थे. वह मंच पर एकदम सामने ठीक मुलायम के बगल में बैठ गये. सिर पर लाल टोपी शोभायमान थी. इनसे कुछ दूरी पर ही इनके पुत्र सपा के राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह बैठे थे. कल्याण बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप मंच पर आकर बैठ गए. न वह किसी से बोले न ही इनसे किसी ने बात करने की कोशिश की. कल्याण के लिए कोई नारा नहीं लगा. मौके की नजाकत भांप कर मुलायम को आगे आना पड़ा. उन्होंने उद्घाटन भाषण के बाद ख़ुद माइक पर नारा लगवाया- कल्याण सिंह ज़िंदाबाद. इसके बाद सपा की भीड़ की हिचक टूट गयी. नारा लगा -मुलायम-कल्याण जिंदाबाद. कल्याण को माला और मुकुट पहनाने वालों की होड़ लग गई. गदगद कल्याण ने हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन किया.

फोटो-*पीटीआई*

कांग्रेस पर क्या करें या न करें

तीन दिवसीय अधिवेशन के दौरान मुख्य रूप से जो बात उभर कर आई, उससे तो यही लगा कि केंद्र सरकार द्वारा उपेक्षा का दंश सपा के लिए असहनीय होता जा रहा है. उसे इस बात का काफी मलाल है कि छोटे-छोटे दल सत्ता की मलाई खा रहे हैं और बेचारी सपा हाथ पर हाथ धरे बैठी है. पार्टी के दो दर्जन सांसद हैं. लोकसभा में वह तीसरे नंबर का राजनैतिक दल है तो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल. इतना सब होने के बाद भी आज की तारीख में सपा की कोई हैसियत नहीं है. माया सरकार अगर सपा नेताओं का उत्पीड़न कर रही हैं यह बात समझ में आती है लेकिन केंद्र सरकार भी वैसी ही बेरुख़ी दिखाए तो सपाइयों का नाराज़ होना लाज़िमी है. ख़ासकर सूबे में बसपा सरकार से लड़ाई में केंद्र का साथ न मिलना सपा को काफी अखर रहा है. सपा को इस बात की तकलीफ है कि कांग्रेस माया की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इनका साथ देने के बजाय वर्ष 2012 में होने वाले विधान सभा चुनाव को अपना लक्ष्य बनाए हुए है.कांग्रेस के रुख़ को देख कर सपा को मलाल इस बात का भी होने लगा है कि क्यों उसने परमाणु करार के समय कांग्रेस गठबंधन सरकार का समर्थन किया. अगर उस समय चुनाव हो जाते तो हालात कुछ और होते. सपा के समर्थन को कांग्रेस इसकी मजबूरी बता कर चिढ़ा रही है. कांग्रेसी यह कहते हुए नहीं थकते कि सपा, सांप्रदायिक शक्तियों के ख़िलाफ़ केंद्र को समर्थन दे रही है. हाल में ही में कांग्रेस ने सपा और बसपा दोनों को एक समान बताकर, सपा के दर्द को और बढ़ा दिया.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सपा नेता त्रिलोक सिंह त्यागी ने तो यहां तक कह दिया कि ग़ाज़ियाबाद तक तो हम कांग्रेस को कोसेंगे, पर दिल्ली पहुंचते ही हम उसे दिए गए समर्थन की बात करेंगे, इससे तो कार्यकर्ताओं में दुविधा बढ़ेगी. यह बात मुलायम के नए मित्र और अधिवेशन में बतौर अतिथि मौजूद कल्याण को भी प्रभावित किए बिना नहीं रह सकी. सपा के एक अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी ने तो दो-टूक कह दिया कि राजनीति में दूसरों की बैसाखी के सहारे नहीं चला जा सकता है. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस को बुरी तरह से लपेटा. महंगाई, विदेश नीति, आंतरिक मोर्चे सभी पर कांग्रेस को विफल बताया. उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कटाक्ष किया. पिछली बार 90 दिन में महंगाई रोकने की बात कही गई थी, इस बार 100 दिन की प्राथमिकताएं घोषित की गई थीं. इन 100 दिनों में जनता की समस्याओं से निज़ात मिलना तो दूर मंहगाई के कारण समस्याएं और बढ़ गईं. सपा प्रमुख ने मुंबई की आतंकी घटना का ज़िक्र करते हुए केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर हमला किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो दल आंख दिखाते हैं कांग्रेस उनसे ही सीधी रहती है. इसलिए सपा भी कांग्रेस को इसी अंदाज़ में जवाब देगी. अमर के तेवर भी तीखे थे. उन्होंने कांग्रेस को धोखेबाज की संज्ञा दी. सपा के मंच पर मौजूद कल्याण सिंह भाजपा के बाग़ी नेता की छवि से उभरने का प्रयास करते दिखे. उन्होंने भाजपा को कोसने से ज़्यादा ध्यान कांग्रेस और बसपा को ललकारने में लगाया. कभी वह मुसलमानों को पुचकारते दिखे तो कभी तीनों दलों को ज़मींदोज करने का आह्वान करते नज़र आए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 54 पिछड़ी जातियां हैं. जिस दिन सब एक साथ हो जाएंगीं, कोई ताक़त सपा को जीतने से नहीं रोक पाएगी.

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अतीत की यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि पिछली बार जब आगरा में सपा का अधिवेशन हुआ था तब विधान सभा में सपा सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई थी. अब जबकि फिर यहां अधिवेशन हो रहा है तो उम्मीद की जा सकती है कि अगले विधानसभा चुनाव में आशातीत सफलता मिलेगी. अखिलेश ने राष्ट्रीय नेतृत्व को भरोसा दिलाया कि पार्टी और प्रदेश की भलाई के लिए जो भी निर्देश दिया जायेगा राज्य इकाई इससे पीछे नहीं हटेगी. अधिवेशन में एक राय से केंद्र की कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लेने का अधिकार मुलायम सिंह के ऊपर छोड़ दिया गया.

उत्तराखंड की शांत वादी में मचा भूचाल

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड की शांत वादियों में एक बार फिर तूफ़ान के आसार हैं. कोटाबाग के ब्लॉक प्रमुख बलवंत सिंह की थाने में हुई निर्मम हत्या के प्रकरण में सरकार की बेतरह किरकिरी हो रही है. सरकार एवं प्रशासन की असफलता का यह कांड एक नमूना बन चुका है. इसमें एक अपराधी ने जहां थाना परिषद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जन प्रतिनिधि को मौत के घाट सुला दिया, वहीं प्रशासनिक लापरवाही का यह शानदार नमूना रहा. जनता ने अपना आक्रोश एक दरोगा को मौत के घाट उतारकर और समूचे थाने को हथियारों और वाहनों को आग के हवाले करके अपना गुस्सा शांत किया. प्रदेश की निशंक सरकार की स्थिति बिल्कुल निरुपाय सी हो गई है. जनता का गुस्सा इतना अधिक भड़क चुका है कि सरेआम लोग सड़कों पर उतरकर प्रशासन के ख़िलाफ़ लामबंद हो रहे हैं.

कोटाबाग के ब्लॉक प्रमुख श्री बलवंत सिंह कन्याल की हत्या से आक्रोशित उनके समर्थकों ने घटना के एक दिन बाद रविवार को कालाढूंगी थाने पर हमला बोलकर एक दारोगा को पत्थरों से मार-मार कर मौत के घाट सुला दिया.

कोटाबाग के ब्लॉक प्रमुख श्री बलवंत सिंह कन्याल की हत्या से आक्रोशित उनके समर्थकों ने घटना के एक दिन बाद रविवार को कालाढूंगी थाने पर हमला बोलकर एक दारोगा को पत्थरों से मार-मार कर मौत के घाट सुला दिया. उसके बाद जनता ने लाखों रुपए मूल्य की सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया. आक्रोशित लोगों ने सरकारी असलहों को लूटने के साथ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया.

इन घटनाओं से दुखी शांतिप्रिय नागरिकों ने कहा कि सूबे में क़ानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है. इस प्रकरण ने सरकार के क़ानून-व्यवस्था से जुड़े तमाम दावे को तार-तार कर दिया है. जिस तरह बहुजन समाज पार्टी से जुड़े बाहुबली अपराधी ने सत्तारूढ़ दल भाजपा के ब्लॉक प्रमुख कन्याल को सरेआम थाना परिसर में मौत के घाट उतार दिया. इसी से अंदाज़ा लग जाता है कि प्रदेश में अपराधियों का मनोबल कितना ऊंचा है.

निशंक सरकार के सत्ता संभालते ही पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ को जान से मारने की धमकी एक भाजपा नेता ने ही दी थी. उस वक़्त सरकार इस अपराधी को बचाने का काम कर रही थी. उस मामले में कांग्रेस के सभी विपक्षी विधायकों सहित बसपा एवं अन्य विधायकों ने हर हाल में उस कथित अपराधी को तत्काल गिरफ़्तार करने के लिए सदन की कार्यवाही को भी बाधित किया. उस समय सरकार केवल लफ्फाजी कर रही थी और सूबे में रोजाना मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी देने वाला कथित अपराधी नायक बनकर घूमता था. इस तरह तमाशबीन बनने की सरकारी प्रवृत्ति ने आज अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा दिया है कि थाना परिसर में अब लाइसेंसी हथियार से जन-प्रतिनिधियों की हत्याएं हो रही है,

इस प्रकरण के बाद जिस तरह से सूबे की पुलिस निष्क्रिय दिखी, उससे पूरे प्रशासन की कलई खुल गई है. रणबीर हत्याकांड के बाद जिस तरह उत्तराखंड पुलिस पर उंगली उठी थी, उसी तरह इस घटना में भी क्योंकि अब चारों ओर यही सवाल उठ रहा है कि जब उत्तराखंड की पुलिस अपनी और अपने थाने की रक्षा नहीं कर सकती तो इससे आम आदमी रक्षा की उम्मीद कैसे करें? इस घटना में सरेआम जनप्रतिनिधि की हत्या के बावजूद भी पुलिस यह नहीं समझ पाई की उसके ख़िलाफ़ उठी आक्रोश की चिंगारी अब शोला बन चुकी है. पुलिस मुख्यालय को बख़ूबी पता था कि पुलिस परिसर में जनप्रतिनिधि की हत्या से भारी जनाक्रोश पैदा हो सकता है. इसके बावजूद राजधानी में बैठे पुलिस ने सुरक्षा के लिए एहतियाती क़दम नहीं उठाया. इस सवाल पर पुलिस के वरिष्ठ अफ़सर बगलें झांकते नज़र आए. यह स्पष्ट हो चुका है कि घटना के बाद थाना एवं पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए समय पर थानों पर फोर्स तैनात कर दी गई होती, तो निश्चित रूप से इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती. इस घटना में समाचार लिखने तक दर्जनों असलहों का कोई अता-पता नहीं लग सका है. साथ ही जनता ने जिस तरह खदेड़-खदेड़ कर पुलिसवालों को सरेआम पीटा है, उससे जन सामान्य आज भी सक्ते में है. घटनास्थल पर पहुंचे कुमाऊं मंडल के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कालाढूंगी थाने के निरीक्षण के बाद मारे गये पुलिस कर्मी एवं पीटे पुलिसकर्मियों से बस यही कहा कि आज का दिन पुलिस के लिए बेहद शर्मनाक है. अफरातफरी में मुख्यमंत्री को अपनी पुलिस को ही ज़िम्मेदार मानते हुए पूरे थाने को सस्पेंड करने के साथ मामले की न्यायिक जांच कराने की घोषणा करनी पड़ी. मुख्यमंत्री ने दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए लूटने वाले अराजक तत्वों के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई की भी मंशा रखते है. मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के निर्देश पर एडीजी-क़ानून व्यवस्था सत्यव्रत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. उत्तराखंड कांग्रेस समिति की प्रदेश अध्यक्ष एस पाल आर्या का मानना है कि प्रदेश में न जनता एवं जनप्रतिनिधि सुरक्षित है, न थाने में पुलिसकर्मी एवं सरकारी संपत्तियां सुरक्षित हैं. यह सब कुछ सरकार की असफलता का परिचायक है. नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत कहते हैं कि देव भूमि को कलंकित करने एवं अपराधियों के हवाले प्रदेश को सौंपने का काम भाजपा की सरकार ने किया है और इस घटना ने पूरे सरकार एवं प्रशासन के प्रति जनता का मोह भंग कर दिया है.

feedback@chauthiduniya.com

पोलियो के सफाए से अब भी एक क़दम दूर

पोलियो जैसी ख़तरनाक बीमारी से पीछा छुड़ाने की तमाम कोशिशों के बाद भी अभी काम पूरा नहीं हो पाया है. हालांकि सरकार और ग़ैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों का असर दिखने लगा है. कम से कम आंकड़ों के हिसाब से तो यही लगता है. भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्ल्यूएचओ) और रोटरी क्लब जैसे ग़ैर-सरकारी संगठनों ने मिलकर जो रिपोर्ट जारी की है, वह दावा करती है कि भारत में पोलियो उन्मूलन का काम 99 फ़ीसदी पूरा हो चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले आठ महीनों के भीतर पोलियो के 236 मामले सामने आए हैं. इनमें उत्तरप्रदेश में 181, बिहार में 49, 4 दिल्ली में और एक-एक मामला राजस्थान और उत्तराखंड का है. इनमें से 34 मामले ख़तरनाक पी1 टाईप पोलियो के हैं, हालांकि पिछले साल पी1 के 75 मामले सामने आए थे. कुल पोलियो मामलों की संख्या में भी इस साल काफी कमी आई है. भारत में पिछले साल 559 मामले सामने आए थे.

यह रिपोर्ट पोलियो के कहर से जूझ रहे भारतीय लोगों के लिए ख़ुशख़बरी है. जिस तरह से पोलियो के मामलों में कमी आई है, विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति पोलियो उन्मूलन के लिए सबसे सही है और अगर पोलियो के मामलों में इसी तरह से कमी आती रही तो भारत जल्द ही ख़ुद को पोलियो मुक़्त देशों की कतार में खड़ा कर सकेगा.

हालांकि इस रिपोर्ट से दोबारा यह सच्चाई सामने आती है कि पोलियो उन्मूलन कार्यक्रमों में अभी थोड़ी कमी रह रही है. रिपोर्ट में पोलियो के मामलों में सबसे आगे भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है. 181 मामलों के साथ उसने अपनी पुरानी जगह बरकरार रखी है. उत्तर प्रदेश शुरुआत से ही पोलियो के मामले में सबसे पिछड़े राज्यों में रहा है. हालांकि स्थिति सुधरी है, पिछले साल राज्य में तीन सौ से ज़्यादा मामले थे.

वैसे इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली ख़बर बिहार से है. पिछले आठ महीने में बिहार में पोलियो के 49 नए मामले सामने आए है. पोलियो उन्मूलन अभियान के बावजूद इतने मामलों का आना बिहार के लिए बुरी ख़बर है जबकि सरकारी दावा है कि इसके उन्मूलन के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन इस बार भी वह अपने पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश के बाद पोलियो प्रभावित राज्यों के मामले में फिर से दूसरे स्थान पर रहा. वैसे पोलियो के मामलों में भारी कमी तो आई है लेकिन चिंता की बात यह है कि ख़तरनाक पी1 पोलियो के मामले बढ़े हैं. जहां 2008 के 200 से अधिक मामलों से भारी कमी आई है वहीं पी1 मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं. यूनिसेफ अधिकारी के मुताबिक इन 49 मामलों में 16 पी1 वायरस से ग्रसित पाए गए जबकि शेष पी3 वायरस के. पिछली बार पी1 से ग्रसित लोगों के मामले बस 3 ही थे. पी1 वायरस के इतने शिकारों का मिलना चिंता की बात है.

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लगभग एक दशक पहले पोलियो टीकाकरण अभियान चलाने के बाद 2008 में पोलियो के सबसे अधिक 300 मामले दर्ज़ किए गए. जबकि साल 2006 में 61 और 2007 में 193 मामले सामने आए थे.

बाक़ी राज्यों में पोलियो उन्मूलन अभियान सफल दिख रहा है, वैसे छिटपुट मामले सामने आते रहे हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन और रोटरी इंटरनेशनल ने पोलियो उन्मूलन के मामले भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की है. पिछले दिनों केंद्र सरकार ने इस बीमारी के पूरे सफाए के लिए 32 करोड़ रूपये देने की घोषणा की है. वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने हाल में ही एक कैबिनेट कमिटी बैठक में कहा था कि लक्ष्य पोलियो के शून्य संक्रमण और अंतरराष्ट्रीय पोलियो मुक़्त सर्टिफिकेट पाने का है.

रिपोर्ट के इन आंकड़ों से सरकार और पोलियो उन्मूलन से जुड़ी संस्थाओं के लिए एक शाबासी है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है. जब तक पोलियो का एक भी मामला सामने आए, तब तक रुकना ख़तरनाक होगा.

भारत में पोलियो वायरस की राज्यवार स्थिति, 2009

राज्य	पी 1	पी 3	कुल
उत्तरप्रदेश	14	167	181
बिहार	16	33	49
दिल्ली	3	1	4
राजस्थान	1	0	1
उत्तराखंड	0	1	1
कुल	34	202	236

भारत में पोलियो वायरस की राज्यवार स्थिति, 2008

राज्य	पी 1	पी 3	कुल
बिहार	3	230	233
उत्तरप्रदेश	62	243	305
दिल्ली	4	1	5
महाराष्ट्र	0	2	2
हरियाणा	0	2	2
उड़ीसा	1	1	2
आंध्रप्रदेश	0	1	1
मध्यप्रदेश	0	1	1
राजस्थान	0	2	2
असम	1	0	1
पंजाब	2	0	2
पश्चिम बंगाल	1	1	2
उत्तराखंड	1	0	1
कुल	75	484	559

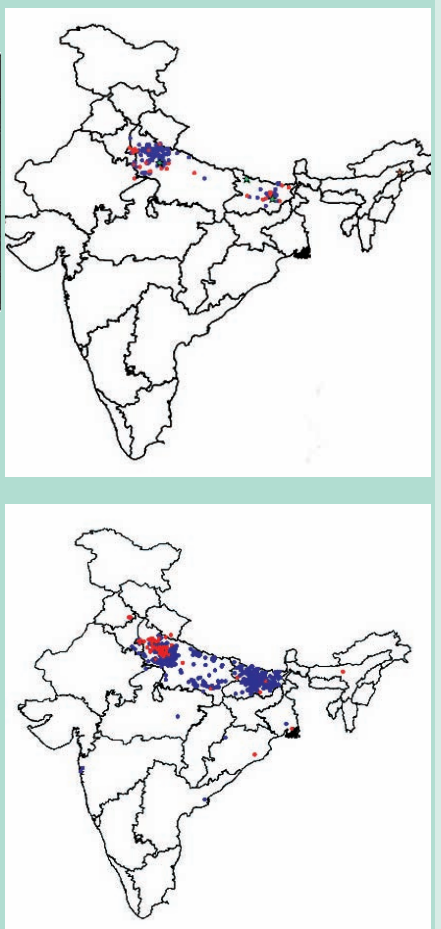

स्रोत: इंडियन नेशनल पोलियो प्लस कमिटी

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

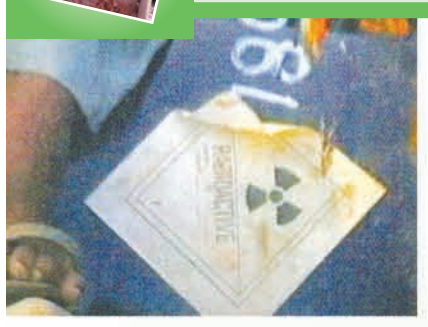

कहीं हो न जाए यूरेनियम पर भी नक्सली क़ब्ज़ा

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम ज़िले की सीमा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से लगती है. यह भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की राजधानी है. यहां यूरेनियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी खुदाई यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) करता है और उसे रिएक्टर्स के लिए परमाणु ईंधन में बदलता है. पूर्वी सिंहभूम नक्सलियों के मामले में भी काफी समृद्ध है, जो इलाक़े में सक्रिय हैं और यहां की खानों के बारे में जानते हैं. बेहद कम या नहीं के बराबर सुरक्षा में ही यूरेनियम के अयस्क या संशोधित येलोकेक को नक्सलियों से बचाया जाता है. नक्सली इस इलाक़े में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहे हैं और स्थानीय अधिकारी स्वीकार करते हैं कि यह अब केवल समय की बात है कि नक्सली कब हमला करते हैं?

यहां के एसपी नवीन सिंह बताते हैं कि नक्सल जादूगोड़ा इलाक़े पर अपना क़ब्ज़ा जमाने के लिए पूरी ताक़त लगा रहे हैं. पहले ही उनका पोटका, डुमरिया, डलभूमगढ़ और घाटशिला पर मज़बूत प्रभाव देखा जाता है.

जादूगोड़ा ज़िला मुख्यालय जमशेदपुर से तक़रीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है. यह पूरा इलाक़ा भारत के लिए प्राकृतिक यूरेनियम का एकमात्र ठिकाना है. यहीं से देश के भारी पानी वाले परमाणु रिएक्टर के लिए माल की आपूर्ति होती है. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक भारत की वार्षिक ज़रूरत 300 टन येलोकेक की है, जिसमें से पूर्वी सिंहभूम से यूसीआईएल 220 टनों का उत्पादन करता है. इस इलाक़े में बृहत् स्तर पर काम को बढ़ाया जा रहा है, ताकि ज़रूरत के 300 टनों का उत्पादन किया जा सके.

यहां सात यूरेनियम खदानें और दो प्रोसेसिंग मिल. यूसीआईएल का मुख्य केंद्र खानों के हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता है और इसी में इलाक़े की सबसे पुरानी खान भी है. जादूगोड़ा से दो किलोमीटर की दूरी पर भटिन और 10 किलोमीटर की दूरी पर नरवापहाड़ खान हैं. वहीं तूरमडीह में खान के साथ-साथ एक प्रोसेसिंग मिल भी है, जो जादूगोड़ा से 20 किलोमीटर दूर है. मोहुलडीह और बांडुहुरंग की खानें तूरमडीह से पांच किलोमीटर की दूरी पर है. बगजाता की खान जादूगोड़ा से 30 किलोमीटर दूरी पर है.

इस संवाददाता ने उसी रास्ते से यात्रा की, जिससे यूरेनियम अयस्क जादूगोड़ा और तूरमडीह की प्रोसेसिंग इकाइयों में जाती है. पूरे रास्ते पर पुलिसवालों की ग़ैर-मौजूदगी चौंकानेवाली और ख़तरनाक लगती है. हमें एक अकेली पुलिस पिकेट या पोस्ट नहीं दिखी. नरवाहपुर से जादूगोड़ा जाते हुए झरिया में एक बड़ा सा गोदाम हमें दिखा, जहां कि गोला-बारूद जमा किए जाते हैं, पर यहां भी सुरक्षा न के बराबर थी. कोई गार्ड ऐसा नहीं था, जो अपने नाम पर खरा उतरे. यह तथाकथित प्रतिबंधित इलाक़ा एक छोटी सी पहाड़ी पर है, जो घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा है. इसकी सुरक्षा का ज़िम्मा केवल चार पुलिसवालों पर है और यहां दो बंकर हैं. यहां निगरानी के लिए बनाया गया टावर बिना किसी सुरक्षाकर्मी के ही दिखा. हम उसी जगह अलग दिनों में कई बार गया, लेकिन हमेशा ही वह टावर बिना किसी गार्ड के ही दिखा. इस रास्ते का इस्तेमाल वे सारे ट्रक करते हैं, जिनमें नरवाहपुर और भटिन से निकाला यूरेनियम अयस्क जादूगोड़ा के यूसीआईएल मिल में लाया जाता है. ज़ाहिर तौर पर यह खानों को मिल से जोड़ने का तगड़ा ज़रिया है.

नक्सलियों द्वारा हड़ताल का आह्वान भी इस इलाक़े के लिए अब नई बात नहीं रही. साथ ही, पुलिस मुठभेड़ और गोलीबारी की घटनाएं भी बढ़ी हैं. हमें कई ट्रकों को जला देने की भी सूचना मिली. एक पुलिसवाला अपना नाम न बताने की शर्त पर बताता है कि इस ज़िले में हमेशा से नक्सलवाद एक समस्या रहा है, लेकिन वे इस शहर में अपना पांव नहीं जमा पाए थे. अब हालात बदल गए हैं. लोगों में जिस तरह की अफ़रातफरी फैली हुई है, उस का कुछ आधार तो है ही. हम सभी जानते हैं कि अगर नक्सली अपना कहर बरपाना चाहें, तो वे उसमें सक्षम हैं.

जादूगोड़ा से बगजाता की ख़ान तक पहुंचने में 30 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है. यह संकरी और धूल भरी सड़क गड्ढों और अंधे मोड़ों से भरी है. बगजाता से डुमरिया की दूरी सड़क मार्ग से 10 किलोमीटर की है. यह भी चारों तरफ़ से पहाड़ों से घिरा है और कथित तौर पर नक्सलियों के प्रभाव में है. एसपी नवीन कुमार बताते हैं कि पिछले साल उन्होंने डुमरिया में नक्सलियों का एक केंद्रीय कार्यालय ध्वस्त किया था. आठ नक्सली मारे गए थे और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया था. इसमें एके-47 भी मिले थे. बगजाता मोसाबानी पुलिस स्टेशन के तहत आता है और इसके प्रभारी रमेश कुमार सिंह ने हमें बताया कि जंगल के इलाके ही नक्सलियों के मूल ठिकाने हैं. वे यूरेनियम के खनन का विरोध करते हैं. हाल ही में नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति फिर से इस इलाक़े में जताई, जब उन्होंने कई तरह के पोस्टर इस इलाक़े में लगाए.

मोसबानी पुलिस स्टेशन बगजाता खान से 10 किलोमीटर दूर है और इसमें कुल मिलाकर 55 पुलिसवाले हैं. थाना प्रभारी सिंह बताते हैं कि पहाड़ों की शृंखला पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक फैली है. इसमें कई और ख़ान भी हैं. हम नक्सलियों की गतिविधि के बारे में जानते तो हैं, लेकिन लगातार उनकी देखरेख दरअसल, सचमुच असंभव है. यूसीआईएल और स्थानीय पुलिस दोनों ही इस तथ्य को स्वीकारते हैं कि बगजाता की खान को नक्सलियों से ख़तरा है, लेकिन हमें इस इलाक़े में पुलिसवालों की मौजूदगी बिल्कुल नहीं या बेहद कम नज़र आई. यह संवाददाता जंगल के रास्ते खनन वाले क्षेत्र में भी चला गया, लेकिन इसको एक बार भी किसी पुलिसवाले या गार्ड ने नहीं रोका.

बगजाता के बाद धान के खेतों से होकर अगर सफर करें तो डलबूनकंड प्रखंड आता है. वहां के गांववाले बुरी तरह डरे हुए हैं. एक गांववाले मंगल मुर्मु की हत्या कथित तौर पर विद्रोहियों ने कर दी थी. मंगल मज़दूरों के अधिकार के बारे में मुखर था. पुलिस ज़ोर देकर कहती है कि उसकी हत्या नक्सलियों ने की थी. यहां उसकी हत्या से सहमे आतंक और डर को हम हवाओं में सूंघ सकते हैं. यहां तक कि हमें गांववालों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा जब हमने मुर्मु के परिवार और पड़ोसियों से उसकी हत्या के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की.

तूरमडीह और जादूगोड़ा को जोड़ने वाली सड़क भी सुरक्षाविहीन है. तूरमडीह में प्रोसेसिंग मिल की स्थापना 2006 में हुई थी, ताकि यहां बंडुहुरांग की खुली और मोहलडीह व तूरमडीह की भूमिगत खदानों से मिले यूरेनियम अयस्क का इस्तेमाल किया जा सके.

यूरेनियम अयस्क के मिल में प्रोसेसिंग से येलोकेक बना लिया जाता है, जिसे बाद में हैदराबाद के परमाणु ईंधन कांप्लेक्स में भेज दिया जाता है. येलोकेक में 80 फ़ीसदी यूरेनियम ऑक्साइड होता है और इससे परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल के लिए फ्यूल रॉड बनाया जाता है. यूसीआईएल यहां से जो भी येलोकेक हैदराबाद भेजता है, उसकी सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान करते हैं. सूत्रों ने बताय कि ये ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग 33 से होकर झारखंड-उड़ीसा सीमा तक जाते हैं. इसके बाद ये कुछ किलोमीटर के लिए एनएच-छह से होकर गुज़रते हैं. आख़िर में विजयवाड़ा से होकर हैदराबाद तक ये ट्रक एनएच-नौ से जाते हैं. यहां बताना ज़रूरी है कि एनएच 33 नक्सलियों के लिहाज़ से काफी मुफ़ीद जगह है.

यूसीआईएल के प्रवक्ता पी बी दुबे हालांकि हमें बताते हैं कि कंपनी यहां 40 वर्षों से काम कर रही है और इतने दिनों में एक भी घटना नहीं हुई है. वह यह भी बताते हैं कि उनके पास सुरक्षा प्रबंध हैं, लेकिन उसकी पूरी सूचना वह नहीं दे सकते. जब एसपी नवीन कुमार से सुरक्षा को लेकर हमने सवाल किए तो उनके भी कुछ इसी तरह के विचार हमें सुनने को मिले. उन्होंने भी कहा कि यह वर्षों से चला आ रहा है और अभी हाल-फ़िलहाल में नक्सलियों से कोई बड़ा ख़तरा पेश आने की आशंका नहीं है.

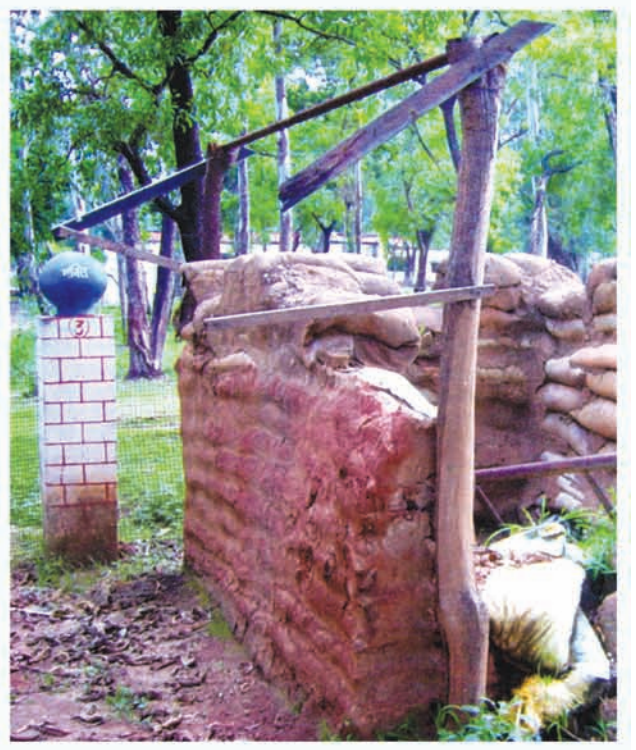

जादूगोड़ा ज़िला मुख्यालय जमशेदपुर से तक़रीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है. यह पूरा इलाक़ा भारत के लिए प्राकृतिक यूरेनियम का एकमात्र ठिकाना है. यहीं से देश के भारी पानी वाले परमाणु रिएक्टर के लिए माल की आपूर्ति होती है. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक भारत की वार्षिक ज़रूरत 300 टन येलोकेक की है, जिसमें से पूर्वी सिंहभूम से यूसीआईएल 220 टनों का उत्पादन करता है. इस इलाक़े में बृहत् स्तर पर काम को बढ़ाया जा रहा है, ताकि ज़रूरत के 300 टनों का उत्पादन किया जा सके.

जादूगोड़ा ज़िला (2008)

नक्सल हिंसा की घटनाएं	35
बारुदी सुरंग	15
ज़ब्त किए गए विस्फोटक	500
ज़ब्त असलहे	109

2003 में आंध्र के नालगोंडा ज़िले के पेदागट्टू में नक्सलियों ने एटॉमिक मिनरल डायरेक्ट्रेट ऑफ एक्प्लोरेशन एंड रिसर्च के 25 अधिकारियों को अगवा कर लिया था और उनके उपकरणों को आग लगा दी थी. इसके बावजूद ज़िला प्रशासन और यूसीआईएल को उम्मीद है कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी.

2008 में बिहार पुलिस ने दो लोगों को यूरेनियम अयस्क ले जाते हुए पकड़ा था, जिसकी क़ीमत लगभग 23 करोड़ रुपए की थी.

हमने बिहार के सुपौल ज़िले के तत्कालीन एसपी श्याम कुमार से बात की. उनका कहना था कि यूरेनियम नेपाल के रास्ते पर था. वह कहां से आया था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. सुरक्षा विश्लेषकों को हालांकि इस मामले में शायद ही संदेह था कि यूरेनियम पूर्वी सिंहभूम से आया था. वजह साफ है. वही इलाक़ा भारत में यूरेनियम का एकमात्र स्रोत है.

ख़ुफ़िया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख अजीत डोवाल ने कहा कि नक्सली आसानी से अपना ध्यान यूरेनियम के अवैध व्यापार पर लगा सकते हैं, ताकि उनको फंड की कमी न हो. वह यह भी बताते हैं कि इस यूरेनियम का अंतिम उपभोक्ता देश के लिए ख़तरा भी पैदा कर सकता है. इन सबके बावजूद यह मामला एक साल के बाद भी किसी तरफ़ नहीं पहुंचा है.

भारत सरकार का टालमटोल वाला रवैया बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, क्योंकि इन जगहों पर सुरक्षा की व्यवस्था तो दिखती ही नहीं. पिछले साल ही, डुगरिडी गांव के पास एक पाइपलाइन फट गई थी, जिससे होकर रेडियोएक्टिव कचरा जाता है. गांव के सरपंच मसंग सोरेन ने हमें बताया कि यूसीआईएल का कोई भी अधिकारी मौक़े पर नहीं आया. खेतों में यूरेनियम का कचरा फैल गया जो ज़ाहिर तौर पर बेहद ख़तरनाक है. धान के बिचड़े पहले पीले और फिर लाल होकर मर गए पर कोई नहीं आया. पिछले तीन महीने से गांव में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं फैली हुई हैं. हालांकि यूसीआईएल के प्रवक्ता दुबे का कहना है कि मामले को बढ़ा-चढ़ा कर बताया जा रहा है. यूरेनियम ख़तरनाक होता है, लेकिन यहां के यूरेनियम की गुणवत्ता कम है, इसलिए यह किसी भी और धातु की तरह ही अच्छी या बुरी है. इससे रेडियोएक्टिविटी का ख़तरा नहीं है.

डुमरिडी गांव के तरह की ही एक घटना तूरमडीह में भी हुई, जब यहां का डैम भी भारी बारिश से उफन गया और पानी खेतों और गांवों में आ गया. यहां के सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन सामंत बताते हैं कि सुरक्षा नियमों के तहत किसी भी टेलिंग डैम (जहां कचरा संशोधन के लिए जमा हो) के आसपास आबादी नहीं होनी चाहिए. यहां जादूगोड़ा और तूरमडीह में इन डैम के पास ही काफी आबादी बसी हुई है. गांववालों की बारहां पुनर्वास की अपील भी यूसीआईएल ने ठुकरा दी. 2008 में ही आंध्रप्रदेश में रेडियोएक्टिव उत्सर्जन होते-होते बच गया था. येलोकेक ले जा रहा एक ट्रक एनएच-पांच पर नरसन्नापेटा के पास पलट गया. सौभाग्य से, किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई. दुबे हमें बताते हैं कि जादूगोड़ा के पास ही परमाणु ऊर्जा प्लांट लगाने का विचार है, पर चूंकि यह लंबी प्रक्रिया है, इसलिए इसमें समय लगेगा.

नक्सलियों का ख़तरा तो सिर पर मौजूद है ही. कई पुलिस अधिकारी अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताते हैं कि नक्सल समस्या से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है. इस इलाक़े में अगर नक्सलियों का क़ब्ज़ा हो गया, तो वह पूरे देश को बंधक बना सकते हैं. हालांकि एसपी नवीन कुमार ऐसी शंकाओं को ख़ारिज करते हैं. उनका कहना है कि यह विचार बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया है. मज़ेदार बात तो यह कि केंद्रीय गृह मंत्रालय आज़ाद इलाक़ों और नक्सल कॉरीडोर के अस्तित्व से इंकार करता है. हाल ही में समाप्त हुए संसदीय सत्र में भी गृह राज्यमंत्री अजय माकन ने लिखित जवाब में ऐसे किसी भी कॉरीडोर से इंकार कर दिया. हालांकि इलाक़े में तैनात अधिकारी कहते हैं कि कई इलाक़े ऐसे हैं, जहां जाने की उनकी हिम्मत भी नहीं होती है.

एक पुख्ता नीति के अभाव और धरातल पर कमज़ोर सुरक्षा ने भारत के महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम पर एक बड़ा सा लाल प्रश्नवाचक चिह्न तो लगा ही दिया है.

अप्पू एस्थॉउस सुरेश

feedback@chauthiduniya.com

मुक्ति का मार्ग तलाशती बेड़नी

राई नृत्य कर दर्शकों का मनोरंजन करने वाली लोक नृत्यांगनाएं बेड़नी भाग्य को कोस रही हैं. हालात यहां तक बदतर हैं कि वे अपना शरीर बेचकर दो जून की रोटी जुटा रही हैं. गायन, वादन एवं नृत्य में अपना जीवन व्यतीत कर देने वाली जाति बेड़िया ने लोकनृत्य से शास्त्रीय नृत्य के मार्ग को देशी तरीक़े से पेश करने का रास्ता बनाया. लम्हा-लम्हा अपने अतीत के गौरवशाली वक़्त को भूलकर गर्त में गिरने को विवश राई नर्तकी की कहानी कभी हमें रुलाती है तो कभी करुणा के सागर में डुबो देती है. बुंदेलखंड के पठार वाले भू-भाग में रहने वाली बेड़िया जाति की ज़िंदगी पठार की तरह सख्त हो गई है.

बुंदेलखंड में प्राकृतिक कोप के कारण किसान दाने-दाने के लिए मोहताज हैं नर्तकी कलावती कहती हैं कि जब किसान ही भूखे हैं, तो शादी वगैरह में नृत्य के लिए कैसे बुलाएं? पेट की भूख के लिए शरीर की भूख मिटाने के अलावा कोई चारा नहीं है. ललितपुर जनपद के मंडावरा ब्लॉक मुख्यालय से सटे रनगांव में रहने वाली बेड़िया जाति की महिलाएं मनोरंजन के संसाधनों की बहुतायत तथा लोगों की बदलती पसंद के चलते हाल के वर्षों में जिस्मफरोशी के लिए विवश हुई हैं. आज की तारीख़ में रनगांव (ललितपुर) बिजावर (छतरपुर) पथरिया (सागर) आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में रहने वाली बेड़िया जाति पर दुखों का पहाड़ टूटा है. बेड़िया अपनी उत्पत्ति गंधर्व से मानती हैं. इस समाज की भी अजब गाथा है. यदि किसी बेड़नी का बाक़ायदा ब्याह हो जाए तो वह धंधा नहीं करती है. मांग, बिंदी व दूसरे सुहाग चिन्ह तो हरेक बेड़नी धारण करती है. ऐसा नहीं है कि यहां की महिलाएं इस गर्त से बाहर निकलना नहीं चाहती हैं, समाज का संकुचित नज़रिया और सरकार की नाकाफी कोशिशें इन्हें आगे नहीं आने दे रही है. बेड़नियों से शादी करने वालों को मिलने वाली सहूलियतें महज़ काग़ज़ों तक ही सीमित है.

ग्राम रनगांव की बेड़नी लीला ललितपुर जिला पंचायत की सदस्य तक चुनी गई है, लेकिन राजनैतिक अधिकार मिल जाने के बाद भी वह अपने समाज को देह बेचने के दलदल से मुक्त नहीं कर पाई है. इस गांव की पिरितिया बताती हैं कि कुछ वर्ष पूर्व पुलिस चौकी के सिपाही डंडे के ज़ोर पर हमारे घर की युवा लड़कियों को मुफ़्त में हमबिस्तर करने के लिए ले जाने लगे, तो हम लोगों ने विरोध किया तो परिवार जनों को तत्कालीन पुलिस के आला अधिकारियों की सहमति से गैंगस्टर जैसी धाराओं में जेल में ठूंसने के साथ ग्राम की महिलाओं, पुरुषों के साथ पुलिस ने जमकर मारपीट की, वहशी दरिंदों ने ख़ूब शारीरिक शोषण किया, पुलिस पर आक्रमण करने का झूठा मुक़दमा पंजीकृत करा दिया गया. ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं.

रजस्वला होते ही युवा बेड़नी की नथ-उतराई की रस्म का रिवाज है. इस रस्म के लिए दो हज़ार से पांच हज़ार रूपए तक का सौदा होता है. अपना दुखड़ा सुनाते हुए दुलारी बताती हैं कि सोलह साल की उम्र में 60 वर्ष के व्यक्ति ने दो हज़ार रुपए में मेरे साथ यह रस्म की थी.

इस रस्म को उत्सव के रूप में मनाया जाता है लेकिन इस उत्सव के साथ ही अंधेरे दिनों की शुरुआत होते ही रूह कांप उठती है. दुलारी कहती है कि एक दिन में पांच से दस पुरुषों को ख़ुश करने में अंग-अंग दुखने लगता है. समाज के चलन के आगे सारी ज़िंदगी दैहिक शोषण के जाल में मछली की तरह तड़पने के अलावा कुछ नहीं बच जाता है. मन, कामनाएं, सपने, सोच और सेक्स की आज़ादी समाप्त हो जाती है. चंद पैसों के कारण आयातित लोगों द्वारा शारीरिक शोषण गुलामों की तरह होता है. भय, भूख और परंपरा के नाम पर देह के दावानल से मुक्ति का मार्ग मौत आने तक अनवरत चलता रहता है.

राई: रात भर चलने वाला बुंदेली लोकनृत्य

बुंदेली लोकनृत्य राई में बेड़नियों (एक विषेश जाति की महिलाएं) द्वारा फुर्ती के साथ रेंगड़ी, झमका, दपु, ढोलकी, मृदंग , नगड़िया, झांझ और झींके जैसे वाद्ययंत्रों के समवेत तालों पर नृत्य किया जाता है. दीपावली के बाद प्रारंभ होकर आठ माह तक चलने वाला यह नृत्य रातों में होली के अवसर पर किया जाता है. राई नृत्य की समय सीमा तय नहीं है. नृत्यकारा की क्षमता ही पैमाना मात्र है कभी-कभी राई नृत्य 22-24 घंटे तक लगातार चलता है और शादी-विवाह की रस्म इसके बिना अधूरी मानी जाती है. लोग एक घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं. बीच में ग्राम्य नर्तकी ख्याल नामक गीत गाते हुए चक्राकार नाचती है और मयूर की भांति रह-रहकर अंगड़ाई लेती है. पुरुष ढोलकी बजाता है और यही ढोलकिया नर्तकी के साथ विषेश रंगत पैदा करता है. इस नृत्य में तकली की तरह घूमना, शरीर की लचक और हाथों का घुमाव प्रमुख है. राई नर्तकी के चेहरे पर घूंघट पड़ा रहता है. घूघंट के बीच लय-ताल बनाकर वह मस्ती के साथ नृत्य करती है. राई नृत्य प्रतिस्पर्धा गायक एवं नर्तकी के बीच होती है. चूड़ीदार पाजामे के ऊपर लंबा घाघरा, कंचुकी या ब्लाउज-साड़ी नर्तकी की पोशाक है. दो प्रतिद्वंदी फाग मंडलियों के बीच में नर्तकी फाग गाते हुए एक फड़ से दूसरे फड़ की ओर लगातार आती-जाती रहती है. इसके साथ गति से मशाल चलती है, ताकि नर्तकी के हाव-भावों को लोग देख सकें. राई नृत्य मणिपुरी में जैगोई नृत्य के भांगी, पारंग से काफी साम्य रखता है. डा. नर्मदा प्रसाद गुप्त का मत है कि बुंदेली में राई- दामोदर प्रचलित है जिसका अर्थ होता है कि राधाकृष्ण. इस प्रकार राई शब्द राधिका से आया है और राधिका के नृत्य से राई नृत्य बना जिसमें केवल राधा ही कृष्ण को रिझाने के लिए नृत्य करती हो. कालांतर में इस नृत्य में गाया जाने वाला गीत राई कहलाने लगा. मगर दूसरे विद्वान इसे विशुद्ध रूप से आदिवासी नृत्य मानते हैं. चूंकि यह नृत्य मशाल की रोशनी में होता था और मशाल को बुझने न देने के लिए इसमें राई डाली जाती थी, इसीलिए यह राई नृत्य कहलाया.

सुरेंद्र अग्निहोत्री

feedback@chauthiduniya.com

सच के लिए कितनों की बलि

और कितनों की मौत का इंतज़ार कर रही है सरकार

पिछले सप्ताह का एक आम दिन. ख़बरिया चैनलों पर तमाम ख़बरें. इन ख़बरों के बीच आई एक ख़बर. इस ख़बर ने सहसा ही सबका ध्यान खींच लिया. ख़बर मेरठ की थी. टीवी शो-सच का सामना-से जुड़ी. सच का सामना-से प्रेरित होकर एक पति ने अपनी पत्नी की गर्दन में ब्लेड ही मार दिया था. इरादा जान से मारने का था, लेकिन पत्नी आशा की किस्मत तेज़ थी, वह बच गई. बाद में पति राजेश गिरफ़्तार हो गया. गिरफ़्तारी के बाद उसने अपना गुनाह क़बूल कर लिया. उसे अपने किए पर ज़रा भी पछतावा नहीं था.

इस पूरी ख़ौफ़नाक घटना के पीछे की वजह सच जानने की सनक थी. राजेश पर यह सनक-सच का सामना-देखने के बाद सवार हुई. राजेश के साले का आरोप था कि जब से राजेश ने सच का सामना देखना शुरू किया, उसने अजीब हरक़तें शुरू कर दीं.

सच का यह खेल उसपर इस कदर हावी हो गया कि वह इसे अपनी ज़िंदगी में भी उतारने को तैयार हो गया. वारदात को राजेश ने पूरी प्लानिंग के साथ अंज़ाम दिया. वारदात के दिन वह अपनी पत्नी को घुमाने के लिए पास की नहर के पास ले गया. वहां ले जाकर उसने बड़े प्यार से आशा के सामने-सच का सामना-की तर्ज पर एक गेम खेलने का प्रस्ताव रखा, जिसमे राजेश-राजीव खंडेलवाल-की तरह सवाल पूछता और बीवी उन सवालों का सही-सही जवाब देती. बीवी ने पहले तो खेलने से इंकार कर दिया लेकिन राजेश के सिर पर सच की सनक सवार थी. उसे हर हाल में अपनी बीवी से सच जानना था. सो उसने मान मनोव्वल, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, बच्चों का वास्ता देकर अपनी बीवी को सवालों के कटघरे में खड़े होने के लिए तैयार कर ही लिया. उसने आशा को यक़ीन दिला कि सच कितना भी कड़वा हो, उनके रिश्तों पर इसका ज़रा भी असर नहीं पडेगा. पति की बातों पर यक़ीन करके आशा सवालों का जवाब देने को तैयार हो गई.

गेम शो की तरह राजेश ने शुरुआत हल्के सवालों से की लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था. सवाल कठिन होते गए. और आख़िरकार वह सवाल भी आ ही गया, जिसके लिए राजेश ने यह पूरी भूमिका तैयार की थी. राजेश ने आशा से पूछ लिया कि क्या उसके जिस्मानी ताल्लुकात उसके अलावा किसी और मर्द से रहे हैं? आशा इस सवाल को सुनकर अकचका गई. राजेश ने अपनी पत्नी आशा को फिर यक़ीन दिलाया कि इस सवाल का जवाब हां होने पर भी उनके रिश्तों पर इसका असर नहीं पड़ेगा. आशा ने न चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज़ खोल दिया. उसने मान लिया कि उसके संबंध किसी और से रहे हैं. राजेश को कुछ और भी जानना था. उसने पूछा कि उनके दोनों बच्चों का असली बाप कौन है. आशा ने राज़ तो खोल ही दिया था. उसने बता दिया कि एक का बाप वह नहीं है. यह जवाब सुनते ही राजेश आपे से बाहर हो गया. उसने फौरन एक ब्लेड निकाली और आशा के गर्दन पर वार करके उसे मरने के लिए छोड़कर चला आया. हालांकि इस बीच वहां कुछ लोगों ने आशा को देख लिया और उसे सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया.

कुछ ही दिनों के भीतर यह दूसरा मामला था जब सच की इस सनक की वजह से किसी की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ी हो. इस वारदात से क़रीब एक हफ़्ते पहले ग्रेटर नोएडा के रहने वाले एक युवक पर कुछ ऐसी ही सनक सवार हुई थी सच जानने की. गेम शो देखने के बाद उसने रात को अपनी पत्नी के साथ सच का सामना खेलने की जिद की. उसने भी वही दलीलें दी जो राजेश ने दी थी लेकिन जब उसकी पत्नी ने अपनी ज़िंदगी का सारा सच खोलकर रखा, तो सच का यह सदमा पति बर्दाश्त नहीं कर पाया और रात को फांसी लगाकर उसने ख़ुदकुशी कर ली. यह दो घटनाएं उन दर्शकों के साथ हुई, जो इस शो को देखते हैं. आप ज़रा सोचिए, जो इस शो में भाग लेते हैं, उनके साथ क्या होता होगा. अंदाज़ा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है. बड़ी हैरानी की बात है कि इसे लेकर तमाम विरोध के बावजूद सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है. सच का सामना को बंद करने की मांग संसद में भी उठ चुकी है, सरकार ने नोटिस भी जारी किया लेकिन इसके बाद क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता. शो का समय बदल दिया गया ताकि बच्चे उसे न देखें लेकिन टूटते रिश्तों के इस दौर में इस रिश्तातोड़ू शो के असर से परिवार को कैसे बचाया जाए, इसका इंतज़ाम अभी तक नहीं हुआ. सवाल है कि आख़िर कब जागेगी सरकार और समझेगी कि तमाम सनसनीखेज़ मसालेदार मनोरंजन से ज़्यादा क़ीमती किसी की जान होती है. यह हिंदुस्तान है. पांच हज़ार साल पुराना हिंदुस्तान. इतनी पुरानी सभ्यता दुनिया में कहीं और नहीं. वह भी इसलिए क्योंकि हमने अपनी सभ्यताओं और परंपराओं को अपने घर की चारदीवारी में, अपने परिवारों में संजोए रखा. अब ख़तरा उसी संस्कृति पर मंडरा रहा है. सच का सामना जैसे शो जिस परिपक्व मनोरंजन (अगर आप शो के नीचे चल रहे टिकर पर नज़र डालें तो यह कहता है कि शो के विषय परिपक्व हैं!) को परोस रहे हैं, क्या उस सच को बर्दाश्त करने की ताक़त क्या हममें है. इन घटनाओं से तो यही लगता है कि ऐसी परिपक्वता(?) हममें नहीं हैं. इस शो ने बच्चों पर ही नहीं वयस्कों पर भी असर डाला है. सिर्फ़ समय बदलने से यह बदला नहीं जा सकता. क्या सरकार कभी इस सच का सामना करेगी?

गेम शो की तरह राजेश ने शुरुआत हल्के सवालों से की लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था. सवाल कठिन होते गए. और आख़िरकार वह सवाल भी आ ही गया, जिसके लिए राजेश ने यह पूरी भूमिका तैयार की थी. राजेश ने आशा से पूछ लिया कि क्या उसके जिस्मानी ताल्लुकात उसके अलावा किसी और मर्द से रहे हैं? आशा इस सवाल को सुनकर अकचका गई. राजेश ने अपनी पत्नी आशा को फिर यक़ीन दिलाया कि इस सवाल का जवाब हां होने पर भी उनके रिश्तों पर इसका असर नहीं पड़ेगा. आशा ने न चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज़ खोल दिया.

रूपेश

feedback@chauthiduniya.com

शाहरुख़! कलाम साहब से कुछ तो सीखें

एम जे अकबर

कई मायनों में एक सितारा अच्छी तक़दीर का मालिक होता है. उदाहरण के तौर पर, एक रिपोर्टर को ख़बरें तलाशनी पड़ती हैं. एक सितारे को बस आईने में अपना अक्स ही देखना होता है. ऐसी आत्ममुग्धता को तो सनसनीखेज़ अनैतिकता और अनिर्णय की स्थिति की ही ज़रूरत होती है. आमतौर पर साधारण आदमी इस तरह के गुण से लैस नहीं होता. शायद उसकी आत्मग्लानि ही उसे व्यस्त रखती है.

ज़ाहिर तौर पर, एक सितारे में योग्यता होती है, लेकिन दिमाग़ भी आमतौर पर बिना शान चढ़ाए बेकार हो जाता है. अपनी छवि के साथ असंभव क़िस्म के प्यार में गिरने के लिए काफी साहस की ज़रूरत होती है. ज़ाहिर तौर पर यह बेहद तनावपूर्ण होता है, कि आप अपने हर क़दम को इस तरह की मिशनरी ज़ील से देखें और परखें.

हालांकि, यह भी सच है कि बदले में मिलने वाला इनाम पुरस्कार इस प्रयास को क़ाबिल-ए-मेहनत बना देता है. अब तो एक छोटी सी ख़रोंच भी समझी या चुराई जानकारी के बजाए ट्विटर-सितारेपन की चमकारी तकनीक-पर मिल जाती है. झूठे नायकों और झूठे श्रद्धालुओं को एक-दूसरे की ज़रूरत बिल्कुल उसी तरह होती है, जैसे मलेरिया के मरीज़ को कुनैन की. हवा में चलने के लिए बेहद आत्मविश्वासी क़दमों की ज़रूरत होती है. एक भी ग़लत विश्लेषण आपको सीधे ज़मीन पर ला सकता है.

शाहरुख़ ख़ान ने भारत सरकार के संसाधनों को इकट्ठा कर लिया, जब अमेरिकी कस्टम्स और सीमा सुरक्षा अधिकारियों ने शाहरुख़ ख़ान के साथ एक आम आदमी जैसा व्यवहार किया. हालांकि, शाहरुख़ की यह पहली अमेरिका यात्रा नहीं थी. इसलिए अधिकारियों द्वारा उनके अमेरिका आने की वाजिब वज़ह पूछने और पहली बार हिरासत में लिए जाने की कुछ वजहें तो ज़रूर रही होंगी.

शाहरुख़ ख़ान ने भारत सरकार के संसाधनों को इकट्ठा कर लिया, जब अमेरिकी कस्टम्स और सीमा सुरक्षा अधिकारियों ने शाहरुख़ ख़ान के साथ एक आम आदमी जैसा व्यवहार किया. हालांकि, शाहरुख़ की यह पहली अमेरिका यात्रा नहीं थी. इसलिए अधिकारियों द्वारा उनके अमेरिका आने की वाजिब वज़ह पूछने और पहली बार हिरासत में लिए जाने की कुछ वजहें तो ज़रूर रही होंगी. जैसा कि बाद में पता भी चला, अमेरिकी सरकार को शाहरुख़ के मेज़बानों के बारे में कुछ बेहद तार्किक सवाल पूछने थे.

पुरानी राजशाही अपने अपमान को राजद्रोह के तौर पर देखती थी, तो आधुनिक ज़माने के एक देवता के प्रति किए अपराध की सज़ा क्या हो सकती थी?

एक आसमानी जीनियस के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर केवल एक कैबिनेट मंत्री की प्रेस-कांफ्रेंस ही शायद काफ़ी नहीं थी, जो किसी शादी में नाचने के करोड़ों रूपए लेकर नाचता हो. कंटेंट के भूखे ख़बरिया चैनलों का पगलाना समझा जा सकता है, लेकिन हम अपनी कल्पना पर यहीं क्यों लगाम लगाएं? शायद भारत को वाशिंगटन से अपना राजदूत बुला लेना चाहिए और परमाणु करार को तब तक रद्द कर देना चाहिए, जब तक अमेरिका का गृहमंत्री (सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सेक्योरिटी) बर्ख़ास्त न कर दिया जाए.

यह सही है कि कोई भी नस्लीय भेदभाव पसंद नहीं करता, ख़ासकर तब, जब एक अदने से कंप्यूटर की वज़ह से सारा बखेड़ा हो रहा हो. इस कंप्यूटर ने न सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी की दशा-दिशा बदली है, बल्कि यह अब दुनिया भर में सताए जा रहे लोगों का वर्गविहीन समाज भी बना रहा है. यदि आज कार्ल मार्क्स होते तो पूंजीवाद के अपने इस साम्यवादी बच्चे से काफ़ी ख़ुश होते. शाहरुख़ को वैसे कंप्यूटर से कोई शिकायत नहीं है. वह सिर्फ़ कस्टम अधिकारी की ग़ैर-लचीले रुख से भन्नाए हुए थे. दरअसल, भारतीय हस्तियों ने अपने आसपास ख़ुद को ही समोहित करनेवाले अहं का ऐसा दायरा बना लिया है, कि वह इसे दी गई किसी भी तरह की चुनौती को समझ ही नहीं पाते.

हर सितारा मशहूर होता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि हर मशहूर शख़्स सितारा भी हो. दिल्ली में एक व्यवसायिक विमान में सफ़र के पहले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को भी अमेरिकी सुरक्षा ड्रिल का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस पर तूफ़ान नहीं मचाया. हालांकि, वह ऐसा कर सकते थे. जब वह राष्ट्रपति थे, तब भी दुनियावी सच्चाई से वाक़िफ़ थे. वह जानते हैं कि ज़िंदगी उलटफेर और अपूर्णताओं से भरी है. उन्होंने अपने कंधे उचकाए और चुपचाप विमान में सवार हो गए.

नस्लीय पहचान अमेरिका के लिए कोई नई नहीं है. हर भारतीय अख़बारों के वैवाहिक विज्ञापन भी नस्ल और जाति के सैकड़ों उदाहरण पेश करते हैं. अगर इस प्रतीक को और खींचें तो शायद मकानों के बंटवारे में भी अविज्ञापित सामाजिक बंटवारा स्पष्ट है. जो लोग आमतौर पर ख़ासे तार्किक होते हैं, वे भी किसी ऐसे पड़ोसी से छोटे या बड़े विवाद से बचना चाहते हैं, जो उनमें से एक नहीं है.

शाहरुख़ ख़ान ही वह शख़्स थे, जिन्होंने वक्तव्य दे दिया था, जब इमरान हाशमी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम होने की वजह से मुंबई में उन्हें मकान नहीं दिया गया. शाहरुख़ इस मसले पर चुप भी रह सकते थे, लेकिन चुप रहने से भला मिलता क्या? एक सितारा होने का क्या फ़ायदा, जब आप हरेक मौक़े पर अपना महत्व न साबित कर दें. सुपर सितारे ने हाशमी को बड़े बनने और रोना बंद करने की सलाह दी थी. शाहरुख़ ख़ुद ही यह बात क्यों भूल गए, जब शिकागो में उनके शाही जुलूस को थोड़ी देर के लिए रोका गया? इसके उलट वह इतना चिल्लाए कि दिल्ली तक वह आवाज़ गूंजने लगी.

जिन सितारों को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत है, उनको यह भी याद रखना चाहिए कि ड्रामे की सीमा समझना बेहद ज़रूरी है, ख़ासकर अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर रहे हों. अभिनय कुछ महानायकों के लिए एकमात्र वास्तविकता हो जाती है, और उनका दिमाग़ पटकथा को मूर्त रूप देने वाला प्रोडक्शन हाउस बनकर रह जाता है. चकाचौंध रोशनी उनको अहं के फिसलनदार रास्ते के प्रति अंधा भी तो बनाती है.

इसमें कोई शक नहीं कि इमरान हाशमी के ऊंचा उठने की खोज के मसले पर कई तरह के विचार हो सकते हैं. हरेक पक्ष अपने तर्क ज़ोर से न दे होश से रखेगा. हाशमी की हैसियत अभी अलग बंगला ख़रीदने की नहीं है, तो वह एक बेहतर फ्लैट का ही सपना देख सकते हैं. वह तो केवल एक घर की मांग कर रहे थे. शाहरुख़ तो पूरी दुनिया से मुआवज़ा मांग रहे थे. अंतर निश्चित तौर से मात्रा से कहीं अधिक का है.

feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

भाजपा की समझ से परे हैं बुनियादी सवाल

भाजपा की दिशाहीनता और भ्रम बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं. जसवंत सिंह हों या अरुण शौरी, ये सभी भाजपा में किसी वैचारिक धारा के मौजूद न होने के ही प्रतीक पुरुष हैं. यह साफ है कि भाजपा की राजनीति अपनी सुविधा के हिसाब से बदलती है, तभी तो इसका स्टैंड भी बदलता रहता है. भाजपा के टूटने के संकेत इसमें भी निहित हैं कि जो भी पार्टी अपना एक आर्थिक दर्शन लेकर नहीं चलती, उसे इसी तरह बिखरना होगा, उसके द्वंद्व इसी तरह सामने आएंगे.

आज सबसे ज़्यादा कांग्रेस ख़ुश होगी, क्योंकि साफ दिख रहा है कि संसद में विपक्ष है ही नहीं. उसके मज़बूत या कमज़ोर होने की बात तो दूसरी. वर्तमान लोकसभा का सबसे बड़ा विपक्षी दल अपने अंतर्विरोधों से ग्रस्त है, उससे उबर नहीं पा रहा है. भाजपा बिल्कुल उस नाव की तरह हो गई है, जिसके माझी के हाथों से पतवार छूट गई हो. जिसके नाविक दिशाहीन हो गए हों और जिसने ख़ुद को लहरों के हवाले कर दिया हो. मार्क्सवादी दल भी अपनी हार की वज़ह से सदमे में है. सपा और बसपा जैसे दल थक-हार कर कांग्रेस का समर्थन करने पर विवश ही हैं. इन सारी बातों से सबसे अधिक ख़ुश कौन सी पार्टी होगी? ज़ाहिर तौर पर कांग्रेस. वज़ह बिल्कुल साफ है. मौजूदा दौर में देश बिल्कुल विपक्षविहीन दिख रहा है. ऐसी हालत 1980 में भी आई थी, जब जनता पार्टी हार गई थी. उस वक़्त भी कांग्रेस को चुनौती देने, उसे घेरने और ज़रूरी मुद्दों पर उससे जवाबतलब करने वाली कोई पार्टी दिख नहीं रही थी. उसी वक़्त इंदिरा गांधी ने एक बेहद मशहूर बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि संसद में तो विपक्ष है ही नहीं. अभी तो विपक्ष जो है, वे अख़बार ही हैं, वही अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं.

1984 में राजीव गांधी की सरकार बनी. प्रचंड बहुमत के साथ. उनकी सरकार में भी विपक्ष की कोई ख़ास भूमिका नहीं थी. ख़ैर, उस वक़्त तो आंकड़े उनके साथ थे. आज के हालात पर ग़ौर कीजिए. वह भी कहीं से अलग नहीं दिखते. कांग्रेस के पास कुल मिलाकर लोकसभा के 206 सांसद हैं. भाजपा के पास 116. यह संख्या कोई कम नहीं होती. देश में मुद्दों की भी कमी नहीं है. ऐसा तो क़तई नहीं है कि सब कुछ ठीकठाक ही चल रहा है. पूरे देश में 100 से अधिक ज़िले सूखाग्रस्त हैं, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, नक्सली समस्या बढ़ती जा रही है और आतंकवाद एक भयावह ख़तरा बना ही हुआ है. भाजपा चाहती तो सत्तापक्ष को आसानी से घेर सकती थी, लेकिन जिनका ख़ुद का घर ही दुरुस्त नहीं, वे दूसरों को भला कुछ कहें भी तो कैसे? जो पार्टी ख़ुद को पार्टी विद अ डिफरेंस कहते नहीं थकती थी, वही पार्टी आज अ पार्टी विद डिफरेंसेज़ बन कर रह गई है. भाजपा की दिशाहीनता और भ्रम बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं. जसवंत सिंह हों या अरुण शौरी, ये सभी भाजपा में किसी वैचारिक धारा के मौजूद न होने के ही प्रतीक पुरुष हैं. यह साफ है कि भाजपा की राजनीति अपनी सुविधा के हिसाब से बदलती है, तभी तो इसका स्टैंड भी बदलता रहता है. भाजपा के टूटने के संकेत इसमें भी निहित हैं कि जो भी पार्टी अपना एक आर्थिक दर्शन लेकर नहीं चलती, उसे इसी तरह बिखरना होगा, उसके द्वंद्व इसी तरह सामने आएंगे.

दरअसल, आज की तारीख़ में भी जो लोग भारत-पाक विभाजन की समीक्षा में ही उलझे हुए हैं, वे आम लोगों का ध्यान बुनियादी समस्याओं से हटा रहे हैं. जनता की बुनियादी समस्या रोटी है, ज़मीन है, रोज़गार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सर पर एक छत होना है. विभाजन इतिहास बन चुका है.वह त्रासद था, लेकिन था सच. जो भी लोग उस त्रासदी को बार-बार भुनाना चाहते हैं, वे मूल समस्या से हमें भटकाते हैं. चाहे ऐसे लोग सीमा के इस पार हों या सीमा के उस पार.

भाजपा इस देश के ग़रीबों, मजलूमों और शोषितों के लिए कोई आर्थिक एजेंडा लेकर सामने नहीं आई. उसने ज़मीनी मसलों की जगह भावनात्मक मुद्दों को ही छेड़ा. नतीजा तो इसका यही होना था. भाजपा में घमासान. उसके अनुशासन का तार-तार होना. दरअसल, आज की तारीख़ में भी जो लोग भारत-पाक विभाजन की समीक्षा में ही उलझे हुए हैं, वे आम लोगों का ध्यान बुनियादी समस्याओं से हटा रहे हैं. जनता की बुनियादी समस्या रोटी है, ज़मीन है, रोज़गार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सर पर एक छत होना है. विभाजन इतिहास बन चुका है.वह त्रासद था, लेकिन था सच. जो भी लोग उस त्रासदी को बार-बार भुनाना चाहते हैं, वे मूल समस्या से हमें भटकाते हैं. चाहे ऐसे लोग सीमा के इस पार हों या सीमा के उस पार. यह जानना दिलचस्प होगा कि क्या उन लोगों ने (जो विभाजन के समीक्षक हैं) कभी भी बुनियादी समस्याओं के बारे में अपने कुछ विचार रखे हैं? कोई दस्तावेज पेश किया है? रोज़गार, ज़मीन, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या उन लोगों ने किसी वैकल्पिक दर्शन की स्थापना की, या कि केवल भावनात्मक और भड़काऊ मसलों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया? यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि जो लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं, वे भी दरअसल दोनों देशों की जनता को उसके बुनियादी मसलों से भटकाना चाहते हैं.

ज़रूरत तो इस बात की है कि भारत या पाकिस्तान में जो भी सोचने-समझने वाला तबका है, वह भारत-पाक की उन समान समस्याओं को रेखांकित करें, जिनको सुलझाए बिना दोनों ही देशों का अस्तित्व ही ख़तरे में पड़ जाएगा. ख़ासकर लोकशाही तो इन मसलों को सुलझाए बिना कभी भी फल-फूल नहीं सकती. दोनों देशों के धर्म अलग हो सकते हैं,लेकिन समस्याएं बिल्कुल एक ही हैं. दोनों देशों की ज़ड़ें भी एक हैं.

दोनों देश के समझदार लोग अगर मिलकर रणनीति बनाएं और अपने यहां की बदहाली और तंगहाली को दूर करने के लिए काम करें, तो कोई शक़ नहीं कि हमारी समस्याएं सुलझ न सकें.

संपादक

editor.chauthiduniya.com

मानवाधिकार और राष्ट्रों की संप्रभुता

रवि किशोर

आज मानवाधिकार और उनका पालन या उल्लंघन वैश्विक महत्ता रखता है और सभी देश इनकी अहमियत से वाक़िफ़ हैं. हालांकि समस्या तब होती है, जब वैश्विक मानवाधिकारों के पालन से किसी देश की संप्रभुता से टकराव की स्थिति पैदा होती है.

1940 तक मानवाधिकार राष्ट्रों के अधिकार-क्षेत्र में थे. राष्ट्र की संप्रभुता को अंतरराष्ट्रीय क़ानून में सर्वोच्च माना जाता था. संप्रभुता की सर्वोच्च शक्ति पर सवाल खड़े करने का कोई भी प्रयास दबाया जाता था.

1919 की वर्साय संधि में जर्मनी के कैसर विल्हेम द्वितीय सहित युद्ध के लिए ज़िम्मेदार सभी व्यक्तियों की जांच और सज़ा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल बनाने की बात थी लेकिन विजयी देशों ने इसे नहीं माना क्योंकि उन्हें इस तरह की किसी शक्ति का इस्तेमाल भविष्य में ख़ुद पर होने का डर था. इसी तरह आर्मीनिया में 1915 में हुए नरसंहारों के दोषियों को भी सज़ा नहीं दी जा सकी. पहले विश्व युद्ध में हुई इन ग़लतियों ने दूसरे विश्व युद्ध का रास्ता खोला. इससे सबक़ लेते हुए इसके बाद बड़े राज्याधिकारियों पर मुक़दमे के लिए अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनलों की व्यवस्था की गई.

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के आने से चीज़ें और बदलीं. धीरे-धीरे मानवाधिकार के ख़याल ने सुरक्षा परिषद के फ़ैसलों को दिशा दी. फिर भी संयुक्त राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी समस्या राष्ट्र की संप्रभुता और मानवाधिकारों का संतुलन बनाने की है. यह एक अहम और टेढ़ा सवाल है. हालांकि एक बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कभी-कभी संप्रभुता के नाम पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दख़ल न देने को सही नहीं ठहराया जा सकता, ऐसी परिस्थितियां युद्ध अपराध, नरसंहार, तानाशाही की अतिवादिता के रूप में सामने आती रही हैं. कई मामलों में यूएन ने हस्तक्षेप भी किया. विभिन्न मानवाधिकार सम्मेलनों में तय किए मानदंडों ने भी इस मामले में अहम भूमिका निभाई है. हालांकि इस तरह के हस्तक्षेप के कई आलोचक भी हैं, जिन्हें लगता है कि यह तरीक़ा अप्रभावी है और अंतरराष्ट्रीय क़ानून में सज़ा का कोई प्रावधान न होने की वजह से ऐसे अपराधों को रोक नहीं सकता. हालांकि ऐसे आलोचक दूसरे प्रावधान जैसे अंतरराष्ट्रीय दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों को भूल जाते हैं. इस बात से तो इंकार नहीं किया जा सकता कि अंतरराष्ट्रीय क़ानून ऐसे अपराधों को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं रहे हैं लेकिन यह भी मानना होगा कि इस मामले में काफी तरक़्क़ी हुई है. दक्षिण अफ्रीका में *अपार्थाइड* का ख़ात्मा सफलता का एक ऐसा ही उदाहरण है.

यहां मानवाधिकार के क्षेत्रीय सिस्टमों पर भी ध्यान देना होगा, ख़ासकर यूरोपियन यूनियन. यह वैश्विक न्यायक्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय क़ानून में व्यक्ति की बदलती भूमिका को समझने के लिए ज़रूरी है.

19वीं सदी में राज्य की संप्रभुता और घरेलू न्यायक्षेत्र के सिद्धांत सर्वोच्च थे. जिन्हें आज मानवाधिकार कहा जाता है वह उस समय राज्य के क्षेत्राधिकार में थे. इसमें अहम बदलाव 1919 में लीग ऑफ नेशंस(राष्ट्रसंघ) बनने से आया. वर्साय की संधि के 13वें भाग में राष्ट्रसंघ के साथ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन बनाने की बात भी थी. इस तरह राष्ट्रसंघ के बनने के साथ ही हम मानवाधिकारों और राज्य की संप्रभुता के लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सोच में बदलाव देखते हैं.

मानवाधिकारों के जुड़े क़ानून के विकास में दूसरे विश्व युद्ध का बड़ा प्रभाव रहा. यह युद्ध अबतक का सबसे भयावह और डरावना युद्ध था और अंतरराष्ट्रीय शांति और मानवाधिकार के लिए एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत सबको साफ दिखाई दी. इस युद्ध के दौरान लोगों ने जो क्रूरता देखी, उसने मानवाधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रतिबद्ध कर दिया.

यहां न्यूरेमबर्ग ट्रायल का उल्लेख ज़रूरी है. होलोकॉस्ट (नाजियों के द्वारा किए गए जुर्म) के मुजरिमों पर मुक़दमा चलाया गया. न्यूरेमबर्ग ट्रायल कई सिलसिलेवार मुक़दमे थे जो नाजी जर्मनी के अहम राजनीतिक, सैनिक और

आर्थिक नेताओं के ख़िलाफ़ चलाए गए थे. जर्मन शहर न्यूरेमबर्ग में हुए ये मुक़दमे 1945-1946 में पैलेस ऑफ जस्टिस में हुए थे. इस ट्रायल में बचाव पक्ष के वकीलों ने यह दलील दी कि अंतरराष्ट्रीय क़ानून संप्रभु राष्ट्रों के कार्यों से जुड़ा है, ऐसे में आरोपितों पर अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता. ऐतिहासिक राज्य-केंद्रित नीति को छोड़ते हुए जजों ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए इन व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय क़ानून की जद में करार दिया.

अब अगर कोई अकेला व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय क़ानून की जद में है तो फिर उसे उसी क़ानून के तहत सुरक्षा पाने का भी हक़ भी है. इस तरह व्यक्ति स्तर पर जवाबदेही का यह फ़ैसला अपने साथ ही मानवाधिकारों के प्रति अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना को भी जोड़े हुए है. इस तरह अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों के प्रति व्यक्ति की जवाबदेही उसे इनका संरक्षण का लाभुक भी बनाती हैं.

मानवाधिकार के सिद्धांत के विकास में न्यूरेमबर्ग एक अहम क़दम था. पहली बार व्यक्ति (इंडिविजुअल) के स्तर पर अधिकार और अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों के महत्व को माना गया. यह पहले की उस नीति से अलग था जिसमें लोगों को नहीं सिर्फ़ राज्यों को ही इन क़ानूनों के क्षेत्र में समझा जाता था.

राज्य संप्रभुता और मानवाधिकार के संबंधों का जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं, उसमें सबसे अहम संयुक्त राष्ट्र का गठन और उसके प्रयास थे. अंतरराष्ट्रीय क़ानून के दो मूल्यों- राज्य संप्रभुता के सम्मान के पुराने सिद्धांत और मानवाधिकार के सम्मान के नए सिद्धांत-को यूएन के चार्टर में एक साथ मिलाया गया. हालांकि यह मेल आसान नहीं रहा है और इसमें गतिरोध भी कम नहीं हैं.

यूएन चार्टर का अनुच्छेद 2(7) कहता है- इस चार्टर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यूएन को किसी राष्ट्र-राज्य के घरेलू मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिले या सदस्यों को ऐसे मामले, यूएन के सामने लाने को मजबूर करे. इस भाग को पढ़ने से यह साफ लगता है कि यूएन किसी के आंतरिक मामले में कोई दख़ल नहीं देना चाहता. अंतरराष्ट्रीय क़ानून का मूल यह है कि कोई भी राष्ट्र दूसरे के मामले में दख़ल नहीं देगा और यह अनुच्छेद 2(7) में भी झलकता है.

यूएन का एक अहम मक़सद मानवाधिकारों की सुरक्षा है. यह लोगों को मानव के तौर पर देखता है, किसी देश के नागरिक के तौर पर नहीं. मानवाधिकारों ने ही सुरक्षा परिषद की नीतियों की दिशा भी निर्धारित की है. हालांकि यह विकास आसान नहीं रहा है. कई दशकों तक परिषद कुछ ही घटनाओं में एकजुट होकर कोई प्रतिबंध लगा सकी. इनमें से एक अहम वाकया 1950 का है, जब परिषद ने देशों को हस्तक्षेप की इजाज़त दी और कोरियाई गणतंत्र (दक्षिण कोरिया) की संप्रभुता की रक्षा की. 1960 में परिषद ने कांगो की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां चल रहे एक घरेलू अलगाववादी संघर्ष के ख़िलाफ़ हस्तक्षेप किया.

मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए उठाए क़दमों में अहम उदाहरण दक्षिण रोडेशिया (जिंबाब्वे) और दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकारों के ख़िलाफ़ लगाए प्रतिबंध थे. ये कुछ उदाहरण जहां यूएन ने यह स्वीकार करते हुए कि मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा ज़रूरी है, अतिवादी शक्तियों के ख़िलाफ़ काम किया. अब सवाल यह उठता है कि यूएन के पास इनके ख़िलाफ़ काम करने के लिए क्या तरीक़े हैं और यह क्या क़दम उठा सकती है?

कई सम्मेलनों और चर्चाओं के माध्यम से मानवाधिकारों से जुड़े कई समझौते, संधियां और दिशानिर्देश उभर कर सामने आए हैं. जब कोई राज्य/राष्ट्र इन संधियों को मानता है तो वह इन अधिकारों के पालन के लिए क़ानूनी तौर पर बंध जाता है. हालांकि संधियों पर हस्ताक्षर तो पहला क़दम ही है, इसका यह मतलब नहीं कि मनवाधिकार ज़मीनी स्तर पर भी लागू हो रहे हैं. इसी वजह से सदस्य देशों को समय-समय पर अपने यहां मानवाधिकारों की स्थिति की रिपोर्ट भेजनी पड़ती है.

इसके अलावा ग़ैर-सरकारी संगठन भी भरोसेमंद और स्वतंत्र सूचना का ज़रिया हैं. कई संगठनों ने अपनी रिपोर्ट के ज़रिए संधियों पर नज़र रखने वाली यूएन संस्थाओं, जैसे, महिलाओं के ख़िलाफ़ भेदभाव उन्मूलन समिति, महिला-स्थिति आयोग, मानवाधिकार के उच्चायुक्त आदि को मानवाधिकारों की स्थिति पर ख़ास नज़र रखने को मजबूर किया है.

सबसे महत्वपूर्ण शक्ति अंतरराष्ट्रीय दबाव की है. अंतरराष्ट्रीय क़ानून में सबसे बड़ा डर वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा गंवाने का होता है.

कोई राज्य मानवाधिकारों की सुरक्षा के बिना पूर्ण संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता. मानवाधिकार और संप्रभुता की बराबर अहमियत से राज्यों पर दोतरफ़ा ज़िम्मेदारी पड़ जाती है-बाहर से अपनी संप्रभुता का सम्मान और आंतरिक तौर पर अपनी जनता का सम्मान और ख़ुशहाली बनाए रखना.

इस तरह से हम पाते हैं कि मानवाधिकार सिद्धांतों के विकास ने संप्रभुता के सिद्धांत पर बड़ा असर डाला है. जब कोई सरकार मानवाधिकारों की रक्षा में असफल रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसके लिए दखलअंदाज़ी कर सकता है. यह दखलअंदाज़ी संप्रभुता को खंडित करने के लिए नहीं बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि शासन का मतलब किसी भू-भाग का मालिक होना नहीं है, शासन के कुछ नियमों का पालन करना भी है. राज्य की संप्रभुता उसके नेताओं की नहीं उसके नागरिकों की संप्रभुता है. उम्मीद है कि यह मानव-आधारित सोच आने वाले वर्षों में और विकसित होगी और होलोकॉस्ट जैसी त्रासदी कभी दोहराई नहीं जाएगी.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं)

feedback@chauthiduniya.com

संपादक महोदय,

आपके अख़बार में हिन्दी अकादमी में संग्राम पढ़ा. अकादमी में हो रही राजनीति के संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता. बस, इतना कहना चाहता हूं कि अशोक चक्रधर को दिल्ली के बाहर की दुनिया भी जानती है. किसी हास्य कवि को विदूषक कहने वाला व्यक्ति ईर्ष्या-द्वेष से संचालित मानसिकता वाला ही होगा.

अशोक चक्रधर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, हाल में, संपन्न हुए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में सुनने का मौक़ा मिला. उन्होंने अपना व्याख्यान साहित्य की वैचारिकी : संदर्भ मुक्तिबोध विषय पर दिया. मुक्तिबोध जैसे कठिन कवि की वैचारिकी पर व्याख्यान देकर उन्होंने प्रतिभागियों को चकित कर दिया. राधाकृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक मुक्तिबोध की कविताई उनकी पुस्तक भी उनके साथ थी. प्रतिभागियों को कहीं से यह नहीं लगा कि वे एक गंभीर वक्ता नहीं हैं. बोलने की कला तो कोई उनसे सीखे.

धन्यवाद
विजय कुमार
दरभंगा

प्रिय संपादक जी,

आपके अख़बार में भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह के बारे में लिखा लेख *संघ, भाजपा, जिन्ना और जसवंत* पढ़ा. इस लेख ने सच्चाई को सामने ला दिया है. जसवंत सिंह द्वारा जिन्ना पर लिखी किताब को लेकर भाजपा के बीच हलचल मची हुई है. इस किताब को लेकर जसवंत भाजपा से निष्कासित भी किए गए. मेरा मानना है कि इस मामले से न तो देश का हित होगा और न ही जनता का. यह भाजपा और जसवंत के बीच का मामला है. मेरा कहने का मतलब यह है कि देश के सामने इससे भी बड़े कई मसले लंबित पड़े हैं. हमारे नेताओं और कर्णधारों को उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, न कि इस तरह के बेकार बवाल खड़े करने चाहिए. ज़मीनी मसले कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं.

आपका
बिजेंद्र कुमार धारीवाल
सरिसवपाही, समस्तीपुर

आख़िर जिन्ना के मायने क्या हैं?

आज जब हम फिर से पाकिस्तान को एक लोकतांत्रिक राज्य के तौर पर खड़ा करने की कोशिश में लगे हैं, ज़रूरत है कि हम जिन्ना को दोबारा समझें, उन्हें बंधक बनाने वालों से उन्हें बचाएं और लोकतंत्र, संविधान, अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष और राज्य से मज़हब के अलगाव जैसे विषयों पर उनके विचारों के आधार पर पाकिस्तान का भविष्य बनाएं.

भारत के पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा से निकाले गए नेता जसवंत सिंह की क़ायद-ए-आज़म पर लिखी किताब में पाकिस्तान के संस्थापक के पुनर्मूल्यांकन ने भारतीय राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. भाजपा के रुढ़िवादी नेताओं की नाराज़गी जसवंत सिंह द्वारा जिन्ना को एक सेकुलर नेता के रूप में पेश करने और उन्हें विभाजन का एकमात्र ज़िम्मेदार न ठहराने को लेकर है.

आख़िर क्यों इस तरह के किसी चित्रण पर भारत में कुछ बुद्धिजीवियों और रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं का ख़ून खौलने लगता है? जवाब बेहद आसान है, जिस तरह की ऐतिहासिक छवि जिन्ना को लेकर उन्होंने अपने जेहन में खींच रखी है, ऐसा कोई भी चित्रण उसमें फिट नहीं बैठता. इस मामले में आज़ादी के बाद से ही उन्होंने अपना दिमाग़ बंद कर रखा है. पाकिस्तान के बनने की जो कहानी उन्होंने अपनी कई पीढ़ियों को सिखाई है और जिसका वह पूरी दुनिया को यक़ीन दिलाना चाहते हैं, उसने जिन्ना और पाकिस्तान के बारे में उनके दिलो-दिमाग़ में एक इमेज बना दी है जिसे बदलना काफी मुश्किल है.

जसवंत आम राजनेताओं की तरह नहीं हैं. वह एक समझदार व्यक्ति और भारत के अतीत पर सोचने वाली शख़्सियत हैं. जब मैं मई 1984 में उनसे किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए मिला था तो वह मुझे ऐसे व्यक्ति लगे थे जो मुस्लिम आक्रमणों के बाद से भारत के इतिहास और इन आक्रमणों को पीछे की वजह और तरीक़े के बारे में जानने में काफी दिलचस्पी रखते थे. मेरे भारतीय दोस्तों ने कहा था कि मैं जसवंत सिंह को एक राजनीतिज्ञ नहीं एक बुद्धिजीवी के तौर पर देखूं, मुझे वह कई मामलों में बड़े रोचक लगे.

उनकी किताब-जो हमें अभी तक पाकिस्तान में नहीं मिली है और इसलिए पढ़ी नहीं गई है-उन बौद्धिक यात्राओं में से एक लगती है, जो जसवंत सिंह भारत के जटिल अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए कर रहे थे. जैसा कि रुढ़िवादी हिंदू सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की प्रतिक्रिया से समझ सकते हैं कि भारत में जिन्ना के बारे में लिखना आसान नहीं है. भारत में एक ऐसे व्यक्ति को जो अलग पाकिस्तान के विचार को अपनाने से पहले वर्षों भारत की आज़ादी के लिए लड़ता रहा, सीधे एक खलनायक बना दिया गया है.

आख़िर क्यों इस तरह के किसी चित्रण पर भारत में कुछ बुद्धिजीवियों और रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं का ख़ून खौलने लगता है? जवाब बेहद आसान है, जिस तरह की ऐतिहासिक छवि जिन्ना को लेकर उन्होंने अपने जेहन में खींच रखी है, ऐसा कोई भी चित्रण उसमें फिट नहीं बैठता.

इतिहास के बारे में तथ्यपरक बातें करने वाले- या जिन्होंने जिन्ना या विभाजन से पहले की घटनाओं के बारे में लिखा है,- यह बात मानते हैं कि जिन्ना भारत की आज़ादी को समर्पित आधुनिकतावादी मुसलमान थे. जब उन्होंने कांग्रेस की राजनीति को मुस्लिमों के राजनीतिक हितों के ख़िलाफ़ पाया तब उन्होंने एक अलग देश-पाकिस्तान-की मांग की.

जिन्ना ने कैबिनेट मिशन के अंत तक भारत के संघ के ढांचे के तहत काम करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने तीन मूल सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं किया-रियासतों को स्वशासन, विधानमंडलों में मुस्लिम आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी. बहुसंख्यकों के विजयी होने (कंकरेंट मेजॉरिटी) का सिद्धांत कोई नया नहीं था. अमेरिका में संख्या में कम दक्षिणी राज्यों ने इस सिद्धांत का इस्तेमाल अमेरिकी गणतंत्र के निर्माण में अपने हितों की सुरक्षा के लिए किया था. इसी तरह इतनी बड़ी जनसंख्या (उस समय क़रीब एक चौथाई भारतीय) वाले मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए एक-व्यक्ति-एक-मत के तर्क के अलावा भी उपाय ज़रूरी थे. कांग्रेस का बड़ा और प्रभावी धड़ा इसके लिए राज़ी नहीं था.

यह लेख उन स्थितियों या कारणों के बारे में नहीं है जिनकी वजह से पाकिस्तान का विचार मुसलमानों में लोकप्रिय हुआ और किस तरह मुस्लिमों के लिए एक अलग गृहराज्य की कोशिश पूरी हुई. यह जिन्ना के सिद्धांतों और विचारधारा के बारे में था. हालांकि, हम इतने विवादों के बीच से असली जिन्ना को तब तक नहीं पा सकते, जब तक हम इस बहस का हल नहीं निकाल लेते कि जिन्ना मुसलमानों के लिए एक देश बनाना चाहते थे या एक इस्लामिक राष्ट्र.

जिन्ना की मुसलमानों के लिए अलग घर की मांग का सबूत इस बात से मिलता है कि अहम धार्मिक-राजनीतिक दलों जैसे जमात-ए-इस्लामी और जमात-ए-उलेमा-ए-इस्लाम ने पाकिस्तान बनाने का विरोध किया था. ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक भौगोलिक मुस्लिम राष्ट्र के विचार को अपनाया नहीं था और दूसरे उन्हें लगता था कि सेकुलर जिन्ना और के शासन में बनने वाला कोई भी देश इस्लामिक नहीं होगा.

इस्लाम को राजनीति में घसीटने का प्रयास और ज़िया-उल-हक़ के राज्य-प्रायोजित इस्लामीकरण कार्यक्रम ने क़ायद की असली विचारधारा और राजनीतिक संघर्ष को तानाशाहों के बेपरवाह और ख़ुद के फ़ायदे की राजनीति के मलबे तले दफ़्न कर दिया. हमें उस जिन्ना को दोबारा ढूंढने की ज़रूरत है जिन्हें हमने सैनिक तानाशाही के धार्मिक और कट्टरवादी ताक़तों की सांठगांठ वाले काले दशकों में खो दिया.

पहले कांग्रेस और फिर मुस्लिम लीग में जिन्ना की राजनीति को ध्यान से देखने पर और राजनीति, संविधान, प्रतिनिधित्व और राज्य व सरकार से जुड़े दूसरे मुद्दों पर उनके विचारों पर नज़र डालने से यह साफ हो जाता है कि वह पूरी तरह से एक आधुनिकतावादी-तर्कवादी नेता थे.

उनकी सोच और विचारों को पाकिस्तान में भी उतने ही ग़लत तरीक़े से समझा और बताया गया है.

आख़िर जिन्ना की विचारधारा क्या थी?

मूलतः जिन्ना एक सेकुलर मुस्लिम थे. हालांकि ऐसा नहीं था कि वह धर्म को बेकार मानते थे लेकिन वह चाहते थे कि पाकिस्तान अपने अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच निष्पक्ष हो. यह पुनर्जागरण के उन विचारों में से है जिसने आधुनिक दुनिया में समाजों और राज्यों के बीच के आपसी संबंध के मायने बदले हैं.

क्या यह अजीब नहीं है कि पाकिस्तान का कट्टरवादी दक्षिणपंथी धड़ा और भारतीय संघ परिवार दोनों जिन्ना को ग़ैर-धर्मनिरपेक्ष साबित करने में लगे हैं. यह इतिहास का और ख़ासतौर पर जिन्ना का एक विकृत स्वरूप है जो संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के लिए पेश किया जा रहा है.

असली जिन्ना के साथ न तो हिंदुस्तानी हिंदू पार्टियां सहज महसूस करती हैं और न ही पाकिस्तानी मुस्लिम संगठन. पाकिस्तानी मुस्लिम संगठन जिन्ना को सेकुलर बताने के लिए जसवंत सिंह के साथ संघ परिवार से कोई इतर व्यवहार नहीं कर सकती हैं. हो सकता है वे उनके साथ कुछ आदर के साथ पेश आएं, लेकिन उसकी वजह अलग होगी.

आम पाकिस्तानियों के बीच धर्मनिरपेक्षता एक विवादास्पद विचार हो सकता है, जिनके लिए यह दर्शन और इसका महत्व उनकी समझ से काफी परे हैं. लेकिन तानाशाही और उसका समर्थन करने वाले राजनीतिक ताक़तों ने मुस्लिम लीग के नाम पर लोकतंत्र और संवैधानिक विचारों के साथ कैसा व्यवहार किया?

जिन्ना के बाद उनकी तस्वीर के नीचे बैठकर चार सेना प्रमुखों ने संविधान को निरस्त किया और लोकतांत्रिक सरकारों की विदाई ग़ैर-लोकतांत्रिक तरीक़े से की. हर घटनाक्रम में उनके साथ एक ख़ास राजनीतिक वर्ग का समर्थन रहा. तानाशाहों और उनके राजनीतिक सहयोगियों ने जो किया, जिन्ना और उनकी विरासत के लिए उससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता.

आज जब हम फिर से पाकिस्तान को एक लोकतांत्रिक राज्य के तौर पर खड़ा करने की कोशिश में लगे हैं, तो ज़रूरत है कि हम जिन्ना को दोबारा समझें और उन्हें बंधक बनाने वालों से उन्हें बचाएं और लोकतंत्र, संविधान, अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष और राज्य से धर्म के अलगाव जैसे विषयों पर उनके विचारों के आधार पर पाकिस्तान का भविष्य बनाएं. इसी में हमारा भविष्य है.

डॉ. आर.बी. रईस
पाकिस्तान से

feedback@chauthiduniya.com

ख़ुफ़िया एजेंसियों के सीक्रेट

सदी का सबसे बड़ा जुर्म!

इतिहास में कभी-कभार ऐसे मौके आते हैं कि जब एक अकेली घटना पूरे देश की सोच और उसके क़ानून को बदल कर रख देती है. इस बार एफबीआई की कहानी में बात एक ऐसी ही घटना की जिसने अमेरिकी सोच, अमेरिकी क़ानून और अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी की हैसियत को बदल दिया.

पावस नीर

मार्च 1, 1932. वक़्त-सुबह के क़रीब नौ बजे, जगह- हॉपवेल, न्यूजर्सी, अमेरिका में विश्वप्रसिद्ध उद्योगपति, एविएटर और सेलिब्रिटी चार्ल्स लिंडबर्ग का घर. चार्ल्स लिंडबर्ग के एक साल के बेटे चार्ल्स जूनियर की आया जब उसे ढूंढती हुई उसके कमरे में पहुंची तो बच्चा ग़ायब था. पूरे घर में खोजबीन के बाद भी वह तो नहीं मिला, हां, खिड़की पर रखा एक रैंसम नोट (फिरौती की मांग वाली चिट्ठी) ज़रूर मिला. इसमें बच्चे की वापसी के बदले 50 हज़ार अमेरिकी डॉलर की मांग रखी गई थी. इस बात के फैलते ही पूरे अमेरिका में सनसनी फैल गई. चार्ल्स लिंडबर्ग अमेरिका के सबसे चर्चित लोगों में थे. एक साल पहले जब उनका पहला बेटा चार्ल्स जूनियर पैदा हुआ था तो यह ख़बर अमेरिका की सबसे बड़ी ख़बर थी. अगले दिन भी अख़बारों की सुर्ख़ियों में चार्ल्स जूनियर ही था. एक अख़बार की सुर्ख़ी थी- सदी का सबसे बड़ा जुर्म!

यह सही भी था कि यह उस समय का सबसे बड़ा जुर्म था. यह, वह समय था जब अमेरिका में संगठित अपराध को एफबीआई (उस समय इसे ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते थे) ने पहला झटका दिया था और अल-कैपोने जैसे नामी अपराधी सलाखों के पीछे थे. कु-क्ल्क्स-क्लान और दूसरे आंतरिक उग्रवादी संगठनों पर एफबीआई का फंदा कस रहा था. अब देश के सबसे हाई-प्रोफाइल अपहरण के बाद एफबीआई को उम्मीद थी कि इस मामले को वही सुलझाएगी लेकिन उस समय अपहरण संघीय अपराधों में नहीं था.

स्थानीय पुलिस इसकी जांच में लगी थी और साथ ही कई और प्रसिद्ध और उत्साही क़िस्म के लोग भी लिंडबर्ग की मदद के लिए सामने आ गए थे. इनमें से ही एक थे-ब्रांक्स में रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक जॉन एफ कोंडोन. कोंडोन ने इस मामले में मदद करने की पेशकश की और किसी भी तरह की फिरौती में अपनी तरफ़ से हज़ार डॉलर और देने का वायदा किया. इसके बाद कोंडोन को अपहर्ताओं की ओर से एक चिट्ठी मिली, इसमें कोंडोन को मध्यस्थ बनाते हुए बातचीत आगे बढ़ाने की पेशकश की गई थी. साथ ही पुलिस को मामले में शामिल करने की वजह से फिरौती की रक़म बढ़ाकर एक लाख डॉलर कर दी गई. इसके बाद जेफसी (जॉन एफ कोंडोन) के नाम से एक चिट्ठी न्यूयार्क अमेरिकन अख़बार में छपी-इसमें लिखा था, पैसे तैयार हैं. इसके बाद जेफसी और किडनैपरों के बीच एक बैठक निश्चित की गई. इसमें उनकी मुलाक़ात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो ख़ुद को जॉन कहता था और पश्चिमोत्तर यूरोप का लगता था. उसने कोंडोन को विश्वास दिलाया कि बच्चा ज़िंदा है और पैसे मिलते ही वापस कर दिया जाएगा.

कुछ दिनों बाद सबूत के तौर पर बच्चे का बेबी-सूट भेजा गया और पैसे लेकर कहां आना है-इसकी जानकारी दी गई. जेफसी और लिंडनबर्ग इस पते को ढूंढते पूरे मैनहटन में घूमते रहे, हरेक पुरानी बताई जगह उन्हें नए पते पर पहुंचने के निर्देश मिलते रहे. आख़िरकार रेमंड्स सीमेंट्री नाम की कब्रगाह में जेफसी ने जॉन को 50 हज़ार डॉलर दिए और कहा कि वे इतने का ही इंतज़ाम कर सके. जॉन ने पैसे ले लिए और कहा कि बच्चा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मार्थाज विनयार्ड में खड़ी एक नाव नेली में है. लिंडबर्ग भी कुछ दूर से इस व्यक्ति को देख रहे थे. पुलिस को कुछ नहीं बताया गया था. बाद में जब मार्थाज विनयार्ड में नेली की खोज की गई तो ऐसी कोई नाव नहीं मिली. हताश हो चुके लिंडबर्ग ने ख़ुद अपना हवाई जहाज़ निकाला और उसे मार्थाज विनयार्ड के ऊपर उड़कर उस नाव को ढूंढने लगे. आख़िरकार कई घंटों बाद उन्होंने हार मान ली. 12 मई 1933 को एक ट्रक ड्राइवर ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया, उसे एक बच्चे का क्षत-विक्षत शव मिला था. पहचान के बाद यह साबित हो गया कि वह चार्ल्स जूनियर ही था. चार्ल्स जूनियर की लाश मिलते ही पूरे देश में तहलका मच गया. अपराधी को तुरंत पकड़ने के लिए पूरे देश में आवाज़ उठने लगी. सीनेट और कांग्रेस ने कुछ हफ़्तों के अंदर ही एक नया क़ानून बनाया. इस क़ानून से अब अपहरण के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना एक संघीय जुर्म बन गया. इस तरह अब यह गुनाह एफबीआई की जद में आ गया. एफबीआई के तत्कालीन निदेशक एडगर जे हूवर ने अब पूरी ताक़त लगा दी. हालांकि, एफबीआई के सामने भी कई समस्याएं थीं. ख़ुद को जॉन कहने वाले शख्स के बारे में उसे कोई ख़ास जानकारी नहीं थी. लिंडबर्ग और जेफसी के बयान के आधार पर जॉन का एक स्केच बनवाया गया. जिस सीढ़ी का इस्तेमाल अपहरण में हुआ था, उसकी फोरेंसिक जांच शुरू की गई, लेकिन एफबीआई को सबसे बड़ी उम्मीद उन नोटों और गोल्ड सर्टिफिकेट्स से थी जो फिरौती की रक़म में शामिल थे. फिरौती में दिए गए सारे नोटों और गोल्ड सर्टिफिकेट्स के नंबर नोट किए गए थे. एफबीआई ने देश भर के बैंकों में इन नंबर के नोटों की जांच शुरू कर दी. इसी बीच अमेरिका में एक नई नीति आई जिसमें गोल्ड सर्टिफिकेट्स का चलन बंद किया जाना था. सभी को 1 मई 1933 तक सारे गोल्ड सर्टिफिकेट लौटाने का समय मिला था. इसी दिन जमा किया गया एक सर्टिफिकेट एफबीआई को मिला, जो फिरौती का हिस्सा था लेकिन उसको जमा कराने वाली महिला या परिवार के सदस्यों के ख़िलाफ़ कोई मामला नहीं बनता था. अगले कई महीने न्यूयार्क पुलिस के जेम्स फिन और एफबीआई के एजेंट थॉमस किस्क इस तरह के नोटों और सर्टिफिकेट्स और नोटों पर नज़र रखे रहे. आख़िरकार एक दिन उन्हें एक सुराग़ मिल ही गया. सितंबर 1934 में उन्हें सूचना मिली कि एक गोल्ड सर्टिफिकेट मिला है जो फिरौती की रक़म का हिस्सा था. यह एक पेट्रोल पंप से आया था. संयोग की बात थी कि जिस पेट्रोल पंप कर्मचारी ने यह सर्टिफिकेट लिया था, उसने देने वाले की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था. उसका कहना था कि सर्टिफिकेट देने वाला बड़ा संदिग्ध लग रहा था और उसे डर था कि कहीं यह सर्टिफिकेट नक़ली तो नहीं, इसलिए उसने उसका नंबर नोट कर लिया.

फिन और किस्क ने जब उस नंबर की जांच की तो वह अप्रवासी जर्मन ब्रूनो हॉप्टमैन के नाम रजिस्टर्ड थी. ब्रूनो के 1279 ईस्ट 220 सेकेंड स्ट्रीट, ब्रांक्स के पते पर छापे के बाद उसकी गिरफ़्तारी में उसके पास से एक 20 डॉलर का गोल्ड सर्टिफिकेट मिला. उसके कमरे और गैरेज से बड़ी मात्रा में पैसे बरामद हुए. ब्रूनो का कहना था कि उसे यह पैसे उसके एक जर्मन दोस्त ने दिए थे. उधर यह बात भी सामने आ चुकी थी कि जर्मनी में उसके इस तथाकथित दोस्त की मौत हो चुकी थी. ब्रूनो का जर्मनी में भी आपराधिक रिकार्ड रहा था. उधर उसके घर से एक लकड़ी का टुकड़ा मिला, जिसकी जांच से यह साबित हुआ कि यह ठीक वैसी ही लकड़ी थी जिसका इस्तेमाल उस सीढ़ी में हुआ था. कोंडोन और लिंडबर्ग ने भी ब्रूनो की पहचान जॉन के रूप में की. 24 सितंबर 1934 को उसे फिरौती वसूलने और 26 सितंबर को एक मासूम की हत्या के जुर्म में ब्रूनो को अदालत के सामने पेश किया गया. अदालत में उसने ख़ुद को बेक़सूर बताया. 13 फरवरी 1935 को उसे मौत की सज़ा सुनाई गई. इस फ़ैसले का अमेरिका भर में स्वागत हुआ, लोगों ने इस फ़ैसले पर पुनर्विचार करने के लिए बनाई गई एक समिति की ख़ूब आलोचना की. लोग चार्ल्स जूनियर के हत्यारे को सज़ा मिलते देखना चाहते थे. इस समिति ने भी उन्हें निराश नहीं किया. 3 अप्रैल 1936 को ब्रूनो हॉप्टमैन को बिजली का करंट देकर मौत की सज़ा दे दी गई. आख़िरी समय तक वह ख़ुद को बेक़सूर बताता रहा, लेकिन अमेरिकी जनता के हिसाब से वही सदी के सबसे बड़े जुर्म का मुज़रिम था.

इस तरह अमेरिकी इतिहास के सबसे सनसनीख़ेज, रोचक और सबसे दुखद मामले का पटाक्षेप हुआ. एक बच्चे की मौत तो हुई, लेकिन एफबीआई ने ख़ुद को कसौटी पर खरा पाया.

pawas@chauthiduniya.com

1. अपहरणकर्ता जॉन का बनाया गया स्केच व ब्रूनो हॉप्टमैन की तस्वीर.
2. चार्ल्स लिंडबर्ग. 3. चार्ल्स जूनियर की गुमशुदगी का पोस्टर.
4. बातचीत में भूमिका निभाने वाले जॉन कोंडोन.

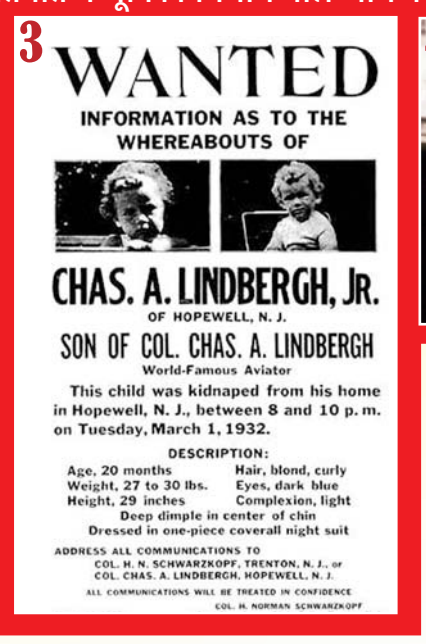

WANTED

INFORMATION AS TO THE WHEREABOUTS OF

CHAS. A. LINDBERGH, JR.

OF HOPEWELL, N. J.

SON OF COL. CHAS. A. LINDBERGH

World-Famous Aviator

This child was kidnaped from his home in Hopewell, N. J., between 8 and 10 p. m. on Tuesday, March 1, 1932.

DESCRIPTION:

Age, 20 months — Hair, blond, curly
Weight, 27 to 30 lbs. — Eyes, dark blue
Height, 29 inches — Complexion, light
Deep dimple in center of chin
Dressed in one-piece coverall night suit

ADDRESS ALL COMMUNICATIONS TO
COL. H. N. SCHWARZKOPF, TRENTON, N. J., or
COL. CHAS. A. LINDBERGH, HOPEWELL, N. J.

ALL COMMUNICATIONS WILL BE TREATED IN CONFIDENCE

COL. H. NORMAN SCHWARZKOPF

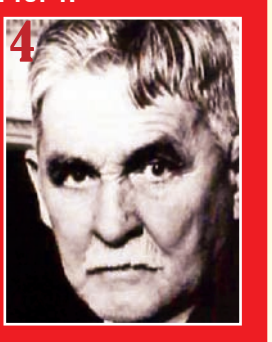

ज़रा हट के

करीवुर्स्ट : ज़ायका जर्मनी का

आपने ऐतिहासिक हस्तियों, स्थलों, वैज्ञानिक खोजों को म्यूज़ियम में जगह पाते देखा होगा, लेकिन कभी खाने के आइटम का म्यूज़ियम बनते नहीं सुना होगा. करीवुर्स्ट नाम का एक सस्ता लेकिन ज़ायकेदार खाना जर्मनी में इतना लोकप्रिय हो चुका है कि अब इसके लिए म्यूज़ियम तक खोल दिया गया है. इसके नाम पर टीशर्ट्स बिक रही हैं. इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लग सकता है कि आठ करोड़ की आबादी वाले जर्मनी में बीते साल अस्सी करोड़ करीवुर्स्ट बिके.

करीवुर्स्ट सुनने-देखने में किसी भारतीय व्यंजन सा लगता है. करी का मतलब है मसाला और वुर्स्ट का अर्थ है सूअर का मांस. इसे बनाने के लिए सबसे पहले सॉसेज़ को ग्रिल किया जाता है, फिर तलकर उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं. फिर टमाटर सॉस और मसाला भी मिलाया जाता है. करीवुर्स्ट में हल्दी, जीरे और धनिए वाला मसाला मिलाया जाता है. फिर इन्हें भारतीय स्टाइल में पके हुए मांस के टुकड़ों में मिलाया जाता है, लेकिन मसालों को मिलाकर भारतीय स्टाइल में तैयार किया जाने वाला करीवुर्स्ट भारतीय खाना कतई नहीं है, हां, इसका ज़ायका देसी ही लगता है.

जर्मनी के हर शहर के बाज़ारों में मिलने वाला करीवुर्स्ट ज़्यादा महंगा भी नहीं होता. जहां फास्ट-फूड के नाम पर दूसरी चीजें, जैसे बर्गर और डो-नट दो यूरो से ऊपर के ही मिलते हैं, ज़ायकेदार करीवुर्स्ट एक से दो यूरो के बीच में हर-जगह मिल जाता है.

जर्मनी के कई पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा शीर्ष नेता भी खुलेआम इसके प्रति अपनी दीवानगी ज़ाहिर कर चुके हैं. दरअसल यह करीवुर्स्ट का ही कमाल है कि 60 साल से जर्मनी उसके ज़ायके में बंधा हुआ है. जर्मनी की राजधानी बर्लिन की पचास लाख की आबादी तो बीते साल सात करोड़ करीवुर्स्ट खा गई.

1949 में पहली बार बर्लिन में करीवुर्स्ट बनाने वाली हैर्टा होएवर नामकी महिला को जर्मनी में कई लोग नेशनल हीरोइन तक कह चुके हैं. करीवुर्स्ट की बढ़ती दीवानगी के चलते ही बर्लिन में करीवुर्स्ट म्यूज़ियम खुल गया है. इस म्यूज़ियम को बनाने में 71 लाख डॉलर ख़र्च करने वाले मार्टिन लोएवर को लगता है कि करीवुर्स्ट का स्वाद और इसकी ख़ुशबू हर दिन साढ़े तीन लाख लोगों को खींच ही लाएगी.

ये इश्क नहीं आसां, अजी! कैंसर का ख़तरा है.

किसी शांत जगह पर आप अपने चाहनेवाले के साथ कैंडल-लाइट डिनर करें, इससे ज़्यादा रोमांटिक और क्या हो सकता है? मोमबत्ती की दूधिया रोशनी में शानदार भोजन और प्रिय का साथ भला किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन शोधकर्ताओं की माने तो ऐसे रोमांटिक कैंडल-लाइट डिनर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं. साउथ कैरोलाइना स्टेट यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने मोमबत्तियों से निकलने वाले धुएं का परीक्षण किया है. उन्होंने पाया कि पैराफ़ीन की मोमबत्तियों से निकलने वाले हानिकारक धुएं से फेफड़े के कैंसर और दमे जैसी बीमारियां हो सकती हैं. हालांकि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं. शोधकर्ताओं ने यह भी माना है कि मोमबत्ती से निकलने वाले धुएं का स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पड़ने में कई साल लग सकते हैं. विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि मोमबत्तियों के कभी-कभी इस्तेमाल से लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. मुख्य शोधकर्ता आमिद हमीदी का कहना है कि जो लोग पैराफ़ीन मोमबत्तियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ख़तरे के दायरे में हैं. वाशिंगटन स्थित अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के सामने पेश रिपोर्ट में बताया गया कि कभी-कभी मोमबत्तियों के इस्तेमाल से और उससे निकलने वाले धुएं से ज़्यादा असर नहीं होगा. यदि कोई व्यक्ति कई वर्षों तक हर रोज़ पैराफ़ीन मोमबत्तियां जलाता है, ख़ासकर ऐसे कमरे में जहां से हवा आने-जाने का रास्ता नहीं हो, तब समस्या हो सकती है. मोमबत्ती से निकलने वाले धुएं की जांच-पड़ताल के लिए शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में कई तरह की मोमबत्तियों को जलाया और उससे निकलने वाले पदार्थों को एकत्र किया. पैराफ़ीन-आधारित मोमबत्तियों से निकलने वाले धुएं के परीक्षण से पता चला कि मोमबत्ती के जलने से इतनी गर्मी नहीं पैदा होती जिससे पैराफ़ीन में पाए जाने वाले हानिकारक पदार्थ जैसे टॉल्युइन और बेंज़ीन पूरी तरह से जल पाएं. यही पदार्थ इन बीमारियों की वजह बनते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि मधुमक्खी के छत्ते से निकले मोम या सॉया से बनने वाली मोमबत्तियां जब जलती हैं तो उनसे इतनी ज़्यादा मात्रा में रसायन नहीं निकलते. कैंडल-लाइट डिनर के शौक़ीनों को वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि ऐसी ही मोमबत्तियों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि इश्क़ भी चलता रहे और ज़िंदगी भी.

मरकर मिलिए मर्लिन मनरो से

इसमें कोई शक़ नहीं कि प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री मर्लिन मनरो का एक पल का साथ भी लोगों को स्वर्ग में होने का अहसास दिलाता था. ज़रा सोचिए 36-वर्षीय ख़ूबसूरत मनरो के बगल में हमेशा के लिए लेटे रहने का अनुभव कैसा होगा. इसके लिए बस आपको अपनी जान देनी होगी और ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा ख़रीदना होगा, और यह मौक़ा आपको दे रही हैं अमेरिका के लॉस-एंजल्स शहर की एक विधवा जिन्होंने मनरो की कब्र के ठीक ऊपर बने अपने पति के कब्र की नीलामी के लिए विज्ञापन दिया है. लॉस एंजल्स टाइम्स अख़बार के अनुसार नीलामी वेबसाइट ई-बे पर जारी इस विज्ञापन में कहा गया है: मर्लिन मनरो के ठीक ऊपर अनंतकाल गुज़ारिए.

जब मनरो ज़िंदा थीं तो राष्ट्रपति से लेकर राजनेताओं और अभिनेताओं तक, सभी के नाम मनरो के साथ जुड़े. जब महज़ 36 साल की उम्र में उनकी मौत हुई तो ज़ाहिर है, तब भी उनकी ख़ूबसूरती के दीवाने कम नहीं थे.

आज भी लोग मर्लिन के दीवाने हैं. वेबरली हिल्स में रहनेवाली विधवा एल्सी पांचर इस बात को समझ रही हैं, तभी तो अपने को उनकी कब्र से बेदख़ल कर उस जगह की नीलामी करा रही है. नीलामी की शुरूआत ही हुई है पांच लाख डॉलर से और पिछले हफ्ते तक यह बोली सात लाख डॉलर तक पहुंच चुकी थी.

हालांकि मनरो की कब्र के पास जगह पाने की दीवानगी की यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले मनरो के ठीक बगल में लेटने का अधिकार प्लेब्वॉय मैगज़ीन के मालिक ह्यू हेफ़नर ने 1992 में हासिल कर लिया था. उन्होंने मनरो के कब्र के ठीक बगल की जगह ख़रीद ली थी. अब एल्सी पॉचर हॉलीवुड की इस दिलकश अदाकारा के ठीक ऊपर दफ़्न होने की ख्वाहिश पूरा करवाने का वायदा कर रही हैं. उनका कहना है उस कब्र को खाली करवाकर वह किसी और की ख्वाहिश तो पूरी करेंगी ही, साथ ही पंद्रह लाख डॉलर के अपने मकान का कर्ज़ भी चुका पाएंगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

बलूचिस्तान के विद्रोही

सीमा मुस्तफा

हर्बियार मर्री एक मशहूर बलूच नेता हैं. उनको 2007 में ब्रिटिश सरकार ने गिरफ़्तार किया था और चंद हफ़्ते पहले ही रिहा हुए हैं. उनका बयान क़ाबिल-ए-ग़ौर है. उन्होंने कहा- पाकिस्तान, महज़ हमारी जंग-ए-आज़ादी को बदनाम करने के लिए कह रहा है कि हमें भारत से पैसे दिए जा रहे है. पाकिस्तान ने यह बात साझा बयान में भी लिखी. पाकिस्तान ने हमारे ख़िलाफ़ बंदूक, टैंक और बमों का इस्तेमाल पहले भी किया. जब से साझा बयान जारी हुआ है, एक बार फिर हमारे लोगों की धरपकड़ और अपहरण शुरू हो गया है. इन दिनों मर्री पाकिस्तान और नाटो की सेना को जिम्मेदार ठहराते हैं. जो बलूच नेता आज़ादी के लिए संगठित हो रहे हैं, उनमें से अधिकांश अपनी सुरक्षा और ज़िंदगी के लिए भाग रहे हैं. इनमें से अधिकांश- जिनसे इस संवाददाता ने बात करने की कोशिश की- वे क्वेटा में न रह कर दुनिया के अगल-अलग हिस्सों में शरण लिए हुए हैं. उन्हें डर है कि पाकिस्तान सरकार उन्हें किसी भी वक़्त गिरफ्तार करा सकती है. बलूच नेशनल पार्टी के सीनेटर सनाउल्लाह बलूच का कहना है कि बलूचिस्तान का ज़िक्र साझा बयान में महज़ इस लिए किया गया कि पाकिस्तान बलूचियों के ख़िलाफ़ अपनी दमन की नीति को जारी रख सके और बलूची संपदा की लूटपाट होती रहे. पाकिस्तान सरकार 1948 से अब तक इस नीति पर ही चल रही है. सनाउल्लाह ने 2008 में पाकिस्तान सरकार मानवाधिकार के प्रतिनिधि हैं. पाकिस्तान में वह वांछितों की सूची में आते हैं. पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ ने मेहरान और सात अन्य बलूचियों की ब्रिटिश सरकार से मांग की थी जिनके बदले में ब्रिटेन को आतंकवाद मामले में वांछित राशिद रऊफ देने का वादा मुशर्रफ ने किया था. बलूच आज़ादी के लिए दर-दर भटक रहे बरहमदाग़ बुग्ती, बलूच नेता नवाब अकबर बुग्ती के पोते हैं. अकबर बुग्ती का कुछ दिनों पहले क़त्ल हो गया था. पाकिस्तान सरकार ने आज सभी बलूच नेताओं के ख़िलाफ़ मुक़दमें दर्ज़ कर लिए हैं. लगभग सभी नेता पाकिस्तान की वांछित सूची में शामिल हैं. हर्बियार आज उन्हीं बलूच नेताओं की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जिनका मानना है कि आज़ादी से कम किसी बात पर समझौता नहीं होगा. वह यह भी बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन अपने चरम पर है. हवाई हमले, क़त्लेआम और अपहरण जैसी वारदातें यहां रोज़मर्रा ही होती है.बलूच आंदोलन शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है. उसने पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के कट्टरपंथी और अतिवादी संगठनो से हमेशा दूरी बनाकर रखी. बलूच नेता इस बात को बहुत गर्व से कहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद वे अपने आंदोलन को राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष बनाने में सफल रहे हैं. मेहरान का मानना है कि यह इतना आसान काम नहीं था. वह कहते हैं- पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान से बीस लाख शरणार्थियों को सोवियत आक्रमण के बाद यहां लाकर बसाया. उनकी कोशिश थी कि बलूचियों की राष्ट्रीय पहचान को धूमिल कर दिया जाए. इसके लिए यहां मदरसे भी बनाए गए.

हालांकि, बलूचियों ने अपने अस्तित्व और आंदोलन के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बचाने में कई कुर्बानियां दी. पाकिस्तान का दावा है कि बलूचिस्तान में तालिबानी ताक़तें घर कर चुकी हैं. इसमें कोई सच्चाई नहीं हैं और पाकिस्तान यह इल्ज़ाम महज़ बलूचिस्तान में सैनिक कार्रवाई का तर्क गढ़ने के लिए लगा रहा है. वे तालिबान को निशाना नहीं बनाएंगे, वे बलूचियों का क़त्ल करेंगे. जब हम बलूच अपनी राष्ट्रीय पहचान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान कहता है कि हम सभी मुसलमान हैं. अगर ऐसा है, तो वे क्यों बलूचियों का कत्ल और बलात्कार कर रहे हैं? सीनेटर सनाउल्लाह बलूच इस बात पर जोर देते हैं कि बलूच आंदोलन एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय आंदोलन है. वह कहते हैं- *पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि बलूच आज़ादी की इस लड़ाई को अतिवादियों के साथ जोड़ दिया जाए*, लेकिन उन्हें हमेशा शिक़स्त मिली है. ख़ास बात यह है कि 1929 में ब्रिटिश हुकूमत की बलूचिस्तान के बारे में बनाई गई सैन्य रपट में भी इस बात को माना गया है. इसमें कहा गया है कि कोई भी बलूच अपने अफ़ग़ान पड़ोसी का तगड़ा विरोधाभास पेश करता है. वह निर्भीक, उदार, मुक्त व्यवहार वाला और कठोर ढंग से सत्यवादी होता है. वह साहस को सबसे बड़ी नेमत और मेहमाननवाजी को अपना पवित्र कर्तव्य मानता है. वह बेहद क़ाबिल घुड़सवार होता है. अफ़ग़ानियों के उलट वह धार्मिक तौर पर कट्टर नहीं होता. जैसा कि इब्टसन ने इसे बेहद रोचक ढंग से कहा है- *उसके दिमाग में ईश्वर कम होता है और हृदय में शैतान ग़ैर-मौजूद.* बलूच नेताओं ने पाक सरकार के इस आरोप को नकारने की भी जहमत नहीं उठाई कि भारत बलूच आंदोलन को शह दे रहा है. इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सीनेटर सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान को बलूचियों के दमन को जायज़ ठहराने के लिए भारत का नाम लेने की ज़रूरत पड़ती है. इस तरह से वह बलूचियों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की मांग को नकार रहा है. बलूचिस्तान में अपनी ग़लतियों और राजनीतिक कुप्रशासन का अहसास करने के बजाय पाकिस्तान यह सब कर रहा है. सनाउल्लाह का मानना है कि बलूचिस्तान मामले को भारत के साथ साझा बयान में जारी करने से बलूच और इस्लामाबाद के तनावग्रस्त रिश्तों पर और भी बुरा असर डालेगा. इससे दोनों के बीच महज़ अविश्वास और बढ़ेगा. उनका कहना है कि ग़लती आतंरिक स्तर पर है. सीनेटर ने यह भी कहा कि बलूचियों को अपनी आज़ादी की लड़ाई में न ही नई दिल्ली से किसी मदद की दरकार है और न ही उन्हें इस्लामाबाद से अपनी राष्ट्रीयता का प्रमाणपत्र चाहिए. उनके मुताबिक बलूचिस्तान अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए एकजुट है. हर्बियार ज़ाहिर तौर पर भारत-पाकिस्तान साझा बयान में बलूचिस्तान को मुद्दा बनाने पर नाराज़ हैं. वह कहते हैं कि अब भारत को भी पाकिस्तान की तर्ज़ पर ही बलूच आंदोलन की मदद करने के सवाल से मुकरना नहीं चाहिए. उन्होंने पाकिस्तानी सेना के हाथों बलूची आंदोलन में मारे गए हज़ारों बलूचियों की तरफ़ इशारा करते हुए कहा कि अब भारत की भी यह नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि वह पाकिस्तान से सवाल करे कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में क्या कर रहा है. आज हज़ारों बलूच लापता हैं. आए दिन हो रही अपहरण की घटनाओं की कोई तफ़्तीश नहीं की जाती है. हैरत की बात है कि 1901 में ब्रिटिश साम्राज्य का बनाया हुआ फ्रंटियर क्राइम रेग्युलेशन क़ानून आज भी पाकिस्तान के दो सूबों में इस्तेमाल किया जा रहा है, बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (गुलाम कश्मीर) में. इस क़ानून के तहत पाकिस्तान सरकार को किसी को भी बिना वजह गिरफ़्तार करने और बंदी बनाकर रखने की छूट है. बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस और खनिज संपदा का अथाह भंडार है. बलूचियों को हमेशा से यह शिकायत रही है कि पंजाब (बलूचियों की बोली में पंजाब पूरे पाकिस्तान का प्रतीक है) उनकी संपदा को लूट रहा है और बदले में उनको कुछ नहीं मिलता. बलूचिस्तान में महज़ 16 प्रतिशत साक्षरता है और यह अति-पिछड़ा की श्रेणी में आता है. बलूच नेताओं से यह पूछे जाने पर कि अगर पाकिस्तान बलूचियों को पूर्ण स्वायत्ता के साथ अधिकार देने को तैयार हो जाए तो क्या वे आज़ादी की मांग छोड़ सकते हैं, पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया मिली. ज़्यादातर नेताओं का मानना है कि उन्हें आज़ादी की मांग से कोई दूर नहीं कर सकता है. और यही उनकी आम राय भी है. बलूचिस्तान में पाकिस्तान के तीन सैन्य ठिकाने हैं. फ़िलहाल, वहां की तीन हवाई पट्टियों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में ड्रोन हमले करने के लिए कर रही है. एक ख़ास बात यह है कि इस संवाददाता से बातचीत के दौरान हर्बियार ने इशारा किया कि वह लगातार अमेरिका और इंग्लैंड के संपर्क में हैं और स्वतंत्र बलूचिस्तान की संभावनाओं पर लगातार बातचीत हो रही है. हर्बियार का कहना है, *वे हमसे बातचीत कर रहे हैं और हमें उम्मीद की रोशनी नज़र आ रही है.* उन्होंने यह संकेत भी दिया कि ईरान भी उनकी बातचीत में मुद्दा हो सकता है, क्योंकि बलूच- ईरान संबंध कभी भी सहज नहीं रहा है. अभी कुछ दिनों पहले ही ईरान सरकार ने चौदह बलूचियों को मौत की सज़ा दी थी जिसे लेकर बलूचियों में ईरान के ख़िलाफ़ काफी आक्रोश है. हर्बियार से हाल ही में पाकिस्तान के एक दैनिक अख़बार ने सवाल किया था कि क्या वह अमेरिका के गुलाम बनना चाहते हैं? इसपर हर्बियार ने कहा था कि फ़िलहाल तो वह एक गुलाम के गुलाम हैं. पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है और बलूच पाकिस्तान के गुलाम, लिहाजा एक गुलाम के गुलाम से बेहतर होगा कि वह सीधे अमेरिका के ही गुलाम बन जाए. इस बयान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बलूचियों का गुस्सा साफ ज़ाहिर होता है. बलूचिस्तान का यह युवा नेतृत्व अपने गुस्से पर क़ाबू रखना जानता है. वे कम बोलते हैं और कम शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात कहते हैं. वे अन्यथा किसी से वाद-विवाद नहीं करते और आज़ाद राष्ट्र की अपनी मांग को लेकर वे कभी दुविधा में नहीं रहते. वे अपने निजी नुक़सानों की बात नहीं करते, बल्कि बलूचों के भविष्य की चिंता ही उन्हें रहती है. उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि बलूचियों को आपसी एकता में पिरोया जा सके.

feedback@chauthiduniya.com

क्या कर रहा है पाकिस्तान?

पाकिस्तान, भारत के साथ दिए गए साझे बयान का भरपूर फायदा उठाने की फ़िराक में है. हालांकि यह हक़ीक़त है कि प्रधानमंत्री यूसुफ रज़ा गिलानी ने मनमोहन सिंह को शर्म-अल-शेख़ वार्ता के दौरान बलूचिस्तान पर कोई डॉज़ियर नहीं दिया. इसके बावज़ूद आंतरिक मंत्री रेहमान मलिक ने पाकिस्तानी सीनेट में कहा कि पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान सरकार को बलूचिस्तान में उनकी आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिशों के सबूत दिए हैं. रहमान मलिक ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि उन्होंने ख़ुद काबुल में हामिद करज़ई के साथ मुलाकात में अफगानिस्तान में चल रहे उन तीन प्रशिक्षण शिविरों का ब्योरा दिया, जहां बलूचियों को आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है. उन्होंने सीनेट में यह भी कहा कि करज़ई ने उनसे वादा किया कि ऐसे शिविरों को फौरन बंद किया जाएगा. अहमान मलिक ने साफ कहा कि पाकिस्तान बलूचियों से बात करने के लिए तैयार है लेकिन केवल उन्हीं लोगों से बात करेगा जिन्हें संविधान पर भरोसा है और जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करते हैं. बुलंद आवाज़ में हर्बियार उत्तर देते हैं, पाकिस्तान ने हमें कम्युनिस्ट बना कर हमारा कत्ल किया, हमे गैर-इस्लामी और पाकिस्तान का विरोधी बताकर कत्ल किया. हम पाकिस्तान के विरोधी नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी नहीं है. हम देशभक्त बलूची हैं. पाकिस्तान की सीनेट में लगातार हर्बियार और अन्य बलूची नेताओं के ख़िलाफ़ सख़्त कदम उठाए जाने की मांग उठती रही है. सीनेटर जमाल लेघारी ने सदन में मांग की थी कि पाकिस्तान को ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर हर्बियार मर्री जैसे बलूची नेताओं को पाकिस्तान बुला लेना चाहिए. लेघारी का कहना है कि बलूचिस्तान में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मकरान में पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया जाता है, स्कूलों में पाकिस्तान के राष्ट्रगान पर पाबंदी लगी है.

क्या है भारत का रुख़?

भारत सरकार की नीति बलूचिस्तान पर अभी साफ नहीं है. बलूचिस्तान मामले में भारत की भूमिका पर सवाल उठाने का काम पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान में अपने कांसुलेट के जरिए कर रहा है. लगभग हर पाकिस्तानी और भारतीय कांसुलेट की मुलाकात में यह मामला पाकिस्तान उठाता है. भारत ने हमेशा इस बात को नकारते हुए यही कहा कि यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है और उसे आपसी बातचीत के ज़रिए इसे सुलझाना चाहिए. आधिकारिक स्तर पर भारत ने कभी भी पाकिस्तान सरकार के सामने बलूचियों के दमन के ख़िलाफ आवाज़ नहीं उठाई, और यह पहला मौका है जब पाकिस्तान के दावों को साझा समझौते में जगह दी गई है. भारत के अवकाशप्राप्त राजदूतों और खुफिया अधिकारियों का मानना है कि साझा बयान में पाकिस्तान को दी गई इस छूट ने पहली बार पाकिस्तानी दावों को स्थापित करने का काम किया है. इसके साथ ही जहां भारत की छवि धूमिल हुई है और वह दरकिनार कर दिया गया है, वहीं इस बात को भी मान्यता मिल गई है कि बलूच आंदोलन को सरहद पार से मदद दी जा रही है. एक भूतपूर्व राजदूत का कहना है कि मनमोहन सिंह को इस मामले को साझा बयान में शामिल नहीं करना था, और अगर करना ज़रूरी था तो उनको यह भी आगे के बयान से साफ करना चाहिए था कि भारत सरकार पाकिस्तान के इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखना. हर्बियार थोड़ी व्यंग्य की मुस्कान से कहते हैं- आप (भारत) अफगानिस्तान की बात करते हैं, लेकिन काबुल जाने के लिए बलूचिस्तान के ऊपर का हवाई रास्ता ही लेना पड़ ता है. कभी नज़र नीची कर देखिए, तो पता चल जाएगा कि हमारे (बलूचिस्तान) के साथ क्या हो रहा है. तब शायद आप बलूचिस्तान की अनदेखी नहीं कर पाओगे. अकबर बुग्ती के क़त्ल के बाद बलूचिस्तान आंदोलन बिखरने के कगार पर आ गया था, लेकिन एक बार फिर उनके बेटों और पोतों के नेतृत्व में बलूच आंदोलन सशक्त होने लगा है. बलूच मामले में पाकिस्तान की चिंता लाज़िमी है, जहां एक तरफ मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान बातचीत कर रहे हैं, वहीं यह भी साफ है कि बलूची आज़ादी और आज़ादी के अलावा और कुछ नहीं चाहते. ऐसा लगता है कि अकबर बुग्ती बलूच आंदोलन का रास्ता पहले से ही तय कर चुके है और आज का नेतृत्व भी उसी रास्ते पर चलने के लिए दृढ़संकल्पित है. वह रास्ता कहात है- आपको कोई भी बराबरी और अधिकार दे नहीं सकता. वह आपको अपने पौरुष से ही लेना होगा.

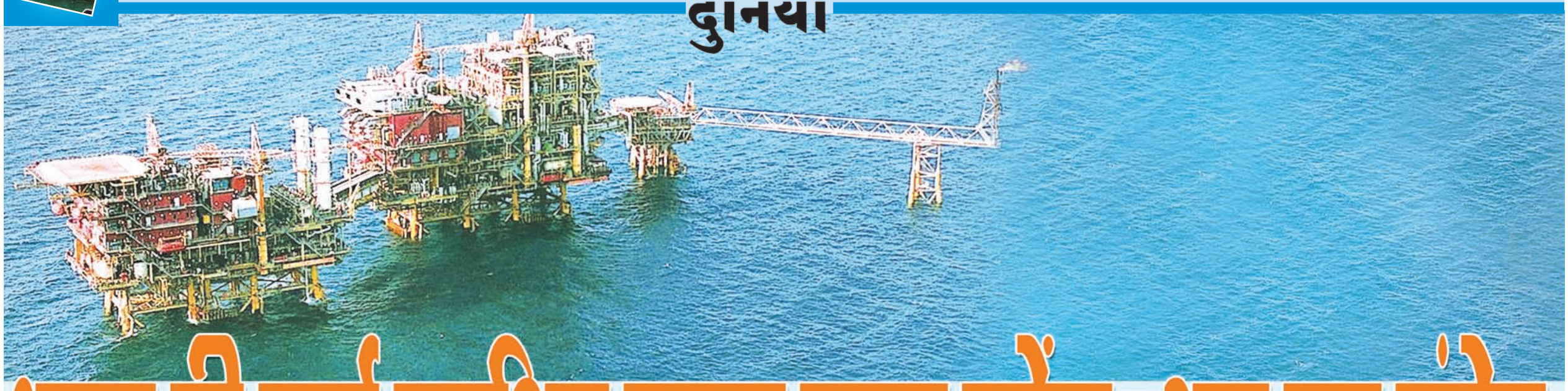

भारत की ऊर्जा सुरक्षित करना मुख्य एजेंडा : आर एस पांडेय

राघव शरण पांडेय फ़िलहाल प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव हैं. उन्होंने जीवन में कई बदलाव देखे, पर एक चीज़ हमेशा उनके साथ बनी रही. महात्मा गांधी, आंइस्टाइन और रवींद्रनाथ टैगोर की तस्वीर वह वस्तु थी. यह तस्वीर पांडेय की नज़र में सत्यम शिवम और सुंदरम का प्रतिनिधित्व करती है.

इसी प्रेरणा ने उनको इतना गतिशील बनाया कि जिस किसी विभाग में वह रहे, उसकी छोटी से छोटी चीज़ पर उन्हें महारत हासिल हो गई. जैसे, 2007 में वह इस्पात सचिव थे, तो स्टील कॉन्क्लेव के दौरान सरकारी नीति की आलोचना करने वालों को उन्होंने तमाम आंकड़े गिना कर चुप करा दिया. कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के साथ ही उन्हें प्रशासनिक सेवा में प्रधानमंत्री की तरफ़ से विशेष पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक पुरस्कार भी मिल चुका है. वह भौतिक विज्ञान और गणित से स्नातक हैं. वह 1972 (नगालैंड काडर) में प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए.

नगालैंड के मुख्य सचिव के तौर पर उन्होंने कई सुधार किए. जैसे, क़ानून व्यवस्था में सुधार, वित्तीय क्षेत्र में सुधार और सरकारी कार्यक्रमों के समुचित रूप से लागू होने के लिए नगालैंड कम्युनिटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड सर्विस एक्ट 2002 लाना. अगस्त 2008 में उनका तबादला पेट्रोलियम मंत्रालय में सचिव के पद पर हो गया.

वह देश की ऊर्जा सुरक्षा को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र का लाभ ज़मीनी स्तर पर गांवों में बांटना चाहते हैं. पांडेय ने मंत्रालय के विजन को **अंजुम ए ज़ैदी** और **सैय्यद रिज़वी** से बातचीत के दौरान रखा.

दो भाइयों के बीच प्राकृतिक गैस को लेकर हो रही लड़ाई के कारण पेट्रोलियम मंत्रालय इन दिनों सुर्खियों में है?

मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. मामला न्यायालय के सामने विचाराधीन है.

यह मामला संसद में भी उठा, उसके बाद यह लड़ाई मीडिया में लड़ी जा रही है, असली तस्वीर क्या है?

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जब तक मसला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है, तब तक मैं कुछ भी नहीं कहूंगा.

ठीक है सर, मुंबई में एनईएलपी (न्यू ईक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी) के रोड शो की प्रतिक्रिया क्या रही और मुंबई के बाद कहां जाएंगे?

एनईएलपी के आठवें दौर का रोड शो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण था. आर्थिक मंदी की शंका के बावजूद रोड शो में हमें अच्छा रिस्पोंस मिला. इसमें 100 से ज़्यादा कंपनियों ने भाग लिया. लगभग 500 लोगों ने पंजीकरण करवाया. इसमें विदेशी कंपनियों ने गज़ब का प्रस्तुतीकरण दिया. ब्रिटिश गैस और केंर्स ऊर्जा जैसी कंपनियों ने प्रस्तुति के दौरान कहा कि तेल और गैस क्षेत्र में निवेश करने के लिए भारत अच्छी जगह है. ब्रिटिश गैस ने पब्लिक प्रस्तुतीकरण में अपने भारतीय अनुभवों के बारे में बताया.

कोई नई खोज ?

पिछले दस वर्षों में 100 से अधिक नई खोज हुई है. जिसमें से 72 एनईएलपी और बैलेंस अंडर प्री एनईएलपी या नोमीनेशन ब्लॉक्स के अतंर्गत है. सिर्फ़ खोज से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे व्यावसयिक ईकाइ के तौर पर बदलना होगा. उसके बाद उत्पादन पर. हालांकि ब्लॉक काफी कम है. केजी बेसिन पहला ब्लॉक है, जहां बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ. इस साल केजी बेसिन के उत्पादन ने भारत के इस क्षेत्र में नई संभावना की पुष्टि की है. केजी बेसिन गैस की खोज के अलावा, भारत के पश्चिमी भाग के बारमेर ज़िले, केंर्स ऊर्जा की खोज भी है. वास्तव में इन दोनों ब्लॉक की सफलता ने ही रोड शो की सफलता को सुनिश्चित किया. इसका लंबे समय तक विदेशी निवेशकों पर प्रभाव पड़ेगा. हम जानते हैं कि गुजरात, राजस्थान, बॉम्बे हाई, कोंकण तट और बंगाल की खाड़ी में काफी मात्रा में पेट्रोलियम भंडार हैं, लेकिन इसे स्थापित करना बाक़ी है. अभी हमने अंडमान के समुद्री इलाक़े में एक ब्लॉकस्थापित किया है. इस तथ्य से तो यही ज़ाहिर होता है कि इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए भारत निवेशकों को आकर्षित करेगा. आंकड़ों के मुताबिक पिछले दस वर्षों में सातवें चरण के एनईएलपी ब्लॉक की बोली से देश में 12 बिलियन का निवेश हुआ है.

नेशनल गैस हाईवे के मामले में मंत्रालय ने कितनी प्रगति की है?

नेशनल गैस हाईवे का विचारपत्र (कांसेप्ट पेपर) प्रक्रिया में है. यह मंत्रालय का अहम फ़ैसला है. आख़िरकार, उस जगह पर एक सही योजना होनी चाहिए, जिसे मूर्त रूप लेने में कई वर्ष लेगेंगे. एक बार अगर योजना बन गई, तो अभी तक जो कुछ भी मंत्रालय कर रहा है उसका अंत हो जाएगा.

भारत के संदर्भ में उर्जा सुरक्षा को आप कैसे देख रहे हैं और क्या पहल की है?

तेल और गैस की खोज में ध्यान दिया जा रहा है. पेट्रोलियम पदार्थ के मामले में सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से देखें तो प्रति व्यक्ति उपभोग के हिसाब से भारत विश्व का 1/3 उपभोग करता है, और अमेरिका के उपभोग का 1/7 वां हिस्सा. मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक विश्व में उर्जा की आवश्यकता 16 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है. जबकि भारत में इसकी आवश्यकता 3.2 प्रतिशत वार्षिक की दर से 2030 तक बढ़ेगी. इसलिए विकास को बनाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक उर्जा की जरूरत होगी. वर्तमान में 41 प्रतिशत उर्जा की पूर्ति तेल और गैस से हो रही है और बाक़ी काम कोयला से बनाया जाता है. हालांकि तेल और गैस का अनुपात बढ़ रहा है और भविष्य में भी इसी तरह बढ़ेगा.

तेल के क्षेत्र में इक्विटी होल्डिंग(शेयर का मालिकाना हक़) और विदेशी तेल कंपनियों के बारे में आपकी क्या राय है?

क्रूड आयल(कच्चे तेल) की आपूर्ति के मामले में हम लोग काफी हद तक विदेशों पर निर्भर हैं. इस कारण से हम लोगों ने क्रूड आयल के मामले में विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए बातचीत की है. एनईएलपी की बोली का उद्देश्य यही है. हाल ही में हमने सीबीएम की बिडिंग के लिए भी आमंत्रण भेजा है. यह चौथा चरण होगा. हमने कोल बेड मिथेन गैस के 10 ब्लॉक की नीलामी के लिए सोचा है. उर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में रणनीति का यह दूसरा हिस्सा है. पिछले 8 से 9 वर्षों में अच्छे नतीजे आए हैं, जब से हमने विदेशों में काफी संख्या में ब्लॉक्स अधिगृहीत किए हैं. हाल में हम विश्व के 20 देशों में मौजूद हैं. पिछले वर्ष हमने विदेशों में तेल और गैस के मामले में भारत के घरेलू उत्पादन का 14 प्रतिशत उत्पादित किया. विदेशों में ब्लॉक्स अधिगृहत करने पर हमारा फोकस जारी रहेगा.

आप हाल में तुर्कमेनिस्तान गए थे? वहां इंटरनेशनल गैस ग्रिड की भी कुछ बात हुई?

हम लोग तुर्कमेनिस्तान में भी काम कर रहे हैं. गैस अथॉरिटी तुर्कमेनिस्तान में गैस पाइप लाइन बनाने की कोशिश कर रही है और हमारे उस देश के साथ अच्छे संबंध भी हैं. तुर्कमेनिस्तान में इंटरनेशनल गैस कांफ्रेंस में हमने प्रजेंटेशन दिए, जहां हमने इंटरनेशनल गैस ग्रिड के लिए सुझाव दिए. हमने प्रस्ताव दिया कि अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय इंटरनेशनल ग्रिड बनाने आगे आता है, तो यह उपभोक्ता और उत्पादक को बेहद नज़दीक लाएगा. यह संपत्ति की बर्बादी को कम करेगा, क्योंकि तब किसी व्यक्तिगत देश के बजाय उस संपत्ति पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का अधिकार रहेगा. अब हम राष्ट्रीय गैस ग्रिड बनाने पर काम कर रहे हैं.

एनईएलपी के आठवें दौर का रोड शो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण था. आर्थिक मंदी की शंका के बावजूद रोड शो में हमें अच्छा रिस्पोंस मिला. इसमें 100 से ज़्यादा कंपनियों ने भाग लिया. लगभग 500 लोगों ने पंजीकरण करवाया. इसमें विदेशी कंपनियों ने गज़ब का प्रस्तुतीकरण दिया. ब्रिटिश गैस और केर्न्स ऊर्जा जैसी कंपनियों ने प्रस्तुति के दौरान कहा कि तेल और गैस क्षेत्र में निवेश करने के लिए भारत अच्छी जगह है. ब्रिटिश गैस ने पब्लिक प्रस्तुतीकरण में अपने भारतीय अनुभवों के बारे में बताया.

संरक्षण पर आपके क्या विचार हैं?

हमारी रणनीति संरक्षण–क्षेत्र की क्षमता में सुधार करना है, मतलब यह कि जितनी उर्जा हम ख़र्च करते हैं, उसकी उपभोग क्षमता में इजाफ़ा और अच्छी तकनीक के उपयोग से ख़र्च को कम करना, उपभोक्ता में जागरूकता बढ़ाना और वित्तीय सुधारों को लागू करना. हमारा मिशन और विजन हरेक उपाय और सुधार के द्वारा उत्पादन को उतना ही रखना, लेकिन ऊर्जा खपत को कम करना है.

पहले भी उर्जा संबंधि कूटनीति पर जोर दिया जाता रहा है?

हमने हमेशा ही कच्चे तेल के भंडार की खोज और उत्पादन पर जोर दिया है. वर्तमान में शासन कर रही पार्टी के घोषणापत्र में और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी गैस और ऊर्जा संबंधी कूटनीति की चर्चा है.

ऐसे हालात में जहां, देश अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के 80 फ़ीसदी से अधिक की आपूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भर हैं, तो इस संदर्भ में राजनय की ज़रूरत और अधिक हो जाती है.पेट्रोलियम मंत्रालय में इसके लिए एक अलग से एक विभाग है. इस साल हम अफ्रीकी देशों का एक सम्मेलन करेंगे, जिसके पहले सीआईएस (सोवियत संघ से टूटकर अलग हुए देशों का समूह) देशों का सम्मेलन हुआ था. इन सम्मेलनों में साझा हितों को बढ़ावा देने के रास्ते तलाशे गए.

खाड़ी देश हमारे सबसे बड़े वितरक हैं और हम उनके सबसे बड़े ख़रीदार हैं, इसी वजह से अगर इस तरह का कोई प्रयास उनकी तरफ़ से हो तो दोनों ही पक्षों को फ़ायदा होगा. यह दोनों के लिए जीत की हालत है. हमें ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी और उनको एक बड़ा बाज़ार.

हमारा कहना यह था कि हम एक बड़े उपभोक्ता हैं और हम सुदूर पूर्व के देशों के रास्ते में भी हैं, जो मध्य–पूर्व के देशों के उत्पाद के सबसे बड़े आयातक हैं. इसी वजह से भारत स्टोरेज के लिए एक शानदार विकल्प उपलब्ध कराता है.

मंत्रालय का मुख्य ज़ोर किन बातों और इलाक़ों पर है?

मैं तो आपको यह उंगलियों पर गिन कर बता सकता हूं. फ़िलहाल तो मंत्रालय का ज़ोर इन छह बिंदुओं पर है.

1. खोज और उत्पादन पर फिर से विशेष ज़ोर दिया जा रहा है. अब केवल भंडारों में बढ़ावे पर ज़ोर नहीं दे रहे.
2. विदेशों में अधिक से अधिक तेल और गैस भंडारों में इक्विटी सुरक्षित करना.
3. हम ग्राहकों की संतुष्टि पर अधिक ज़ोर दे रहे हैं. यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां ग्राहकों का मंत्रालय के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि शायद ही कोई उपभोक्ता ऐसा होगा, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में तेल या गैस का इस्तेमाल नहीं करते हों. ग़रीब भले केरोसिन जलाएं और अमीर जेट फ्यूल का इस्तेमाल करें लेकिन सभी कहीं न कहीं इस उत्पाद से बंधे हुए हैं. हमें वितरण व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी. हमने इस दिशा में ज़रूरी क़दम भी उठाए हैं. नई सरकार के आने के बाद हम विजन 2015 लेकर आए हैं. इस योजना (राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना) को जल्द ही पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा. इस बाबत ज़रूरी निर्देश तेल कंपनियों को दिए जाएंगे. वे इसी महीने कम से कम 1000 ग्रामीण वितरकों को नियुक्त करेंगे.
4. हमने संरक्षण पर ज़ोर दिया है. इस संदर्भ में हमारा विचार है कि हम समान उत्पादन के लिए कम उपभोग करें. अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और इसीलिए आउटपुट हमें बढ़ाना होगा. इस वजह से उपभोग बढ़ेगा, लेकिन हमें अपनी प्रभाव–क्षमता बढ़ानी होगी. नई तकनीक और उपकरणों को प्रभावी बनकर यह लक्ष्य पाया जा सकता है. इसके लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है. कुछ दिनों पहले हमने इसके लिए मीडिया कैंपेन भी शुरू किया, क्योंकि मूल्यांकन के नतीजे बेहद उत्साहवर्द्धक थे.
5. शोध और विकास (आर एंड डी)– कोल बेड मिथेन, कोयला खदानों की गैस का वर्गीकरण, शेल गैस हाइड्रेट्स और हाइड्रोजन वगैरह के क्षेत्र में नई तकनीक का प्रयोग भविष्यधर्मी तरीका है. हमने इस मिशन के लिए नया शोध समूह भी बनाया है, जो नए प्रयोगों में हमें निर्देशन देगा. इसके लिए हमें नया संस्थान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम वर्तमान संस्थानों के साथ ही समन्वय करने की कोशिश करेंगे. हमने गैस हाइड्रेट्स पर अमेरिका के साथ करार भी किया है.
6. पुनर्चक्रण के लायक(रीन्यूएबल) ईंधन जैसे एथेनॉल, बायोडीजल पर भी हमारा ध्यान है. एथेनॉल के मामले में हम अब तक केवल पांच फ़ीसदी ब्लेंडिंग का स्तर ही पा सके हैं. यह भी पूरे देश में एक समान नहीं है, क्योंकि वितरण के बंधन हैं. इसकी ज़रूरत रसायन उद्योग को भी है. हम इस दिशा में आवश्यक क़दम उठा रहे हैं. हमने पिछले कुछ सालों में इस पर अपना ध्यान केंद्रित किया है.

अपने ख़ाली वक़्त में आप क्या करते हैं?

मैं ख़ूब किताबें पढ़ता हूं. हरेक तरह की. किसी ख़ास लेखक या विधा से मैं नहीं बंधा हुआ हूं.

आप पहली पीढ़ी के नौकरशाह रहे हैं. आपके बच्चों की पसंद क्या है?

मेरा कोई भी बच्चा नौकरशाही में अपना करियर नहीं बनाना चाहता. मेरे दो बेटे हैं और दोनों विवाहित हैं और खुश हैं.

feedback@chauthiduniya.com

अच्छा खाने से मिलेगी अंदर की ताक़त

इंसानी शरीर की सबसे ख़ूबसूरत बात यह है कि यह अपने-आप में एक कुशल मशीन की तरह काम करता है. हालांकि इस मशीन को भी कभी-कभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसी समस्याओं यानी बीमारियों से लड़ने में हमारी प्रतिरोधी क्षमता काम आती है, लेकिन इस क्षमता को भी बाहर से मदद की बेहद ज़रूरत है. यह मदद उसे मिलती है, अच्छे खाने से. प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने वाला खाना हमारे शरीर में सैनिक का काम करने वाली श्वेत-रक्त कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ाता ही है, साथ में शरीर से ग़ैर-ज़रूरी चीज़ें बाहर करने में भी मदद करता है. आइए खाने की कुछ ऐसी ही चीज़ों के महत्व से आपको परिचित कराएं.

रंगीन सब्ज़ियां और फल

फलों और सब्ज़ियों में रंग कैरोटिनॉयड्स और बायोफ्लेवोनॉयड्स से आता है और यह दोनों एंटी-आक्सीडेंट्स हैं. जहां कैरोटिनॉयड्स उन कोशिकाओं को मज़बूती देता है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, वहीं बायोफ्लेवोनॉयड्स कोशिकाओं को प्रदूषित करने वाले कारकों को दूर करता है. इसके अलावा इन फलों और सब्ज़ियों में कई तरह के विटामिन भी होते हैं.

पटसन(फ्लैक्स) और मछली

पटसन(फ्लैक्स) या सन के तेल और मोटी मछलियों में एक तरह का वसा एसिड होता है जो श्वेत-रक्त कोशिकाओं की गतिविधि बढ़ाता है और कीटाणुओं को मारने में मदद करता है. इसके अलावा मछली में सेलेनियम भी होता है जिससे किलर सेल्स की संख्या बढ़ती है और कैंसर से लड़ने वाले सेल भी मज़बूत होते हैं.

जौ और बार्ली

इनमें बीटा-ग्लूकॉन नाम का घुलनशील फाइबर होता है. यह फाइबर कैंसर, जलन और विषकारी पदार्थों के ख़िलाफ़ काम करने की शक्ति रखता है. घावों के जल्द भरने और एंटी-बॉडीज के साइड-इफेक्ट्स से निपटने में यह काम आता है.

चाय

चाय में एल-थियानीन होता है. एल-थियानीन एक अहम अमीनो एसिड है. यह श्वेत-रक्त कोशिकाएं बनाने और स्वास्थ के लिए हानिकारक विषाणुओं को ख़त्म करने में कारगर है. चाय को एक आराम देने वाला पेय भी माना जाता है. यह ठंड से लड़ने में भी काम आता है.

रंग से पहचानें पोषण

किसी भी फल या सब्ज़ी का रंग सिर्फ़ उसकी ख़ूबसूरती ही नहीं बढ़ाता बल्कि यह भी बताता है कि उसमें कौन-कौन से पोषक तत्व हैं.

कैसे पहचानें असली-नक़ली रंग

बाज़ार में ऐसे फल और सब्ज़ियों की भरमार हैं जिन्हें ग़लत तरीक़े से पकाया जाता है और कृत्रिम रंग दिया जाता है. इन्हें पहचानने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है. पहली, जबरन पकाए गए फल के छिलके ज़्यादा चिकने होते हैं वहीं असली फलों में थोड़ा खुरदुरापन होता है. फल या सब्ज़ी पर अगर धब्बेदार रंग हो तो उसके कृत्रिम ढंग से पकाए जाने की संभावना होती है. किसी भी सब्ज़ी-फल को पकाने-खाने से पहले गर्म पानी से धो लें. अगर कृत्रिम रंग होगा तो वह निकल जाएगा.

चिकेन सूप

चिकेन को जब पकाया जाता है तो उससे एक तरह का अमीनो एसिड निकलता है. यह ब्रोंकाइटिस की दवा एसिटिलसाइटीन की तरह का होता है. यह श्वेत-रक्त कोशिकाओं के पलायन को रोकता है. साथ ही सूप की नमकीन भाप साइनस और फ्लू के ख़िलाफ़ काम करती है. इसमें मिलाए गए मसाले और सब्ज़ियां हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं.

रंग	मौजूदपोषक तत्व	किस पर असर
हरा:	फाइबर, विटामिन-ए, सी, बीटा-कैरोटिन	कम रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, पाचन
लाल:	लाइसोपीन,बीटा कैरोटीन, एंथोसायानिंस	हृदय रोग, कैंसर
पीला-नारंगी:	कैरोटिनॉयड्स, विटामिन-सी, पोटाशियम	हड्डी रोग, आंख, त्वचा
नीला-बैंगनी:	विटामिन-सी, फाइबर, फ्लैवोनॉयड्स	जलन, मस्तिष्क, मूत्र संबंधित रोग.

बादाम और फली

बादाम और फली जिंक के सबसे अच्छे स्रोत हैं. जिंक की मदद से संक्रमण से लड़ने के लिए सबसे तेज़ी से एंटी-बॉडीज बनती हैं. साथ ही इसमें विटामिन-ई जैसा एंटी-टॉक्सीडेंट भी मौजूद होता है.

अदरक

अदरक में जलन के ख़िलाफ़ काम करने वाले जिंजेरोल्स और डायरिल-हेप्टानॉयड्स जैसे तत्व होते हैं. इससे सर्दी और खांसी की हालत में मदद मिलती है. अदरक को शहद के साथ लेना बहुत फ़ायदेमंद होता है.

मशरूम

मशरूम हमारे शरीर में श्वेत-रक्त कोशिकाएं बनाने में मदद करता है और बाहरी कीटाणुओं से बचाव करता है. मशरूम सेलेनियम, पोटेशियम और कॉपर जैसे मिनरल और कई विटामिनों का भी स्रोत है. साईटेक, माइटेक और रेशी मशरूम प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है. ये अपने एंटी-कैंसर गुणों के कारण भी मशहूर हैं.

आंवला और नींबू

यह विटामिन-सी के सबसे अहम स्रोत हैं. विटामिन-सी से श्वेत- रक्त कोशिकाएं और एंटी-बॉडीज़ बनने में मदद मिलती हैं. इसके अलावा इनसे इंटरफेरोन का स्तर भी बढ़ता है, जो कोशिका के कवच पर होता है और वायरस के हमले से बचाता है. इनके रस से घुटन और उल्टी की समस्याओं से भी निज़ात मिलती है.

मसाले

मसाले आपके खाने में स्वाद भी लाते हैं और संक्रमण से भी लड़ते हैं. हल्दी, मिर्च जैसे मसालों की एंटी-इंफ्लैमेट्री (जलन के ख़िलाफ़) और एंटी-बैक्टीरियल (कीटाणुओं के ख़िलाफ़) ख़ूबियां इसे कई तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए कारगर बनाती हैं. हल्दी का इस्तेमाल तो सर्दी, खांसी और साइनस जैसी बीमारियों में किया जाता है. इन मसालों से शरीर को ज़रूरी आत्मरक्षक ताक़त मिलती है.

प्याज और लहसुन

लहसुन और प्याज में एलीसिन होता है जिसमें सल्फर होता है, जिससे यह कीटाणु, जीवाणु और जलन के ख़िलाफ़ असर करते हैं. जिन्हें इनकी गंध से दिक़्क़त है वह इन्हें पका कर ही खाएं लेकिन अगर गंध बर्दाश्त हो सके तो कच्चा लहसुन खाना एक अच्छा विकल्प है.

दही

दही ऐसे बैक्टीरिया का स्रोत है जो हानिकारक कीटाणुओं को बढ़ने से रोकता है. इमोनोग्लोबिन ए, टी-लिंफोसाइट्स और किलर सेल्स की पैदाइश में मदद करता है. पाचन में भी दही का अहम रोल है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

वक़्त है मंदी को पीछे छोड़ने का..

रीतिका सोनाली

वक़्त आ गया है कि मंदी के ग़म से उबर कर थोड़ी ख़ुशियां मना ली जाएं. आंकड़ों के मुताबिक़ जुलाई महीने में आशंका से कम लोगों की नौकरियां गईं. जुलाई में दो लाख 47 हज़ार लोगों की नौकरियां गई. इस मंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित रही अमेरिका में बेरोज़गारी दर, जो पिछले महीने के 9.5 के मुक़ाबले 9.4 फ़ीसदी रही. अमेरिका में अप्रैल के बाद यह पहली गिरावट है. विशेषज्ञों को आशंका थी कि बेरोज़गारी दर बढ़ कर 9.6 प्रतिशत हो जाएगी. आंकड़ों के मुताबिक़ अमेरिका में जुलाई में विभिन्न क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कम लोगों की नौकरियां गईं.

निर्माण के क्षेत्र में 52,000 नौकरियां गई, पिछले साल सितंबर के बाद से पहली बार है जब यह आंकड़ा लाख़ से कम हुआ है. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क़रीब 17 हज़ार लोगों को नौकरी मिली है.

भारत में भी एक ताज़ा सर्वे के परिणाम में यह बात सामने आई है कि इस वर्ष के अंत तक रोज़गार के दस लाख़ नए अवसर सामने आएंगे. रिपोर्ट के मुताबिक़ पिछले साल की तुलना में इस साल रोज़गार के अवसरों में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है. वाकई, इस सर्वे के नतीजे रोज़गार की तलाश में लगे युवाओं के लिए उम्मीद की किरण दिखाते हैं.

रिर्पोट के मुताबिक, देश में आगामी छह महीनों में होटल, स्वास्थ्य और शिक्षा सेक्टर में रोज़गार के सबसे ज़्यादा मौके मिलने की संभावना है. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 4,26,668 नई नौकरियां मिलने की उम्मीद है, हेल्थ सेक्टर में 2,95,829 नए मौके मौजूद होंगे. इसी तरह रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी सेक्टर में भी 1,66,005 नई नौकरियां के अवसर होंगे. साथ ही अच्छी प्रतिभाओं के लिए अवसर कम नहीं है. आगे बढ़ने की होड़ में कंपनियां पेशेवर लोगों की भर्ति कर रही है और उनके प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्राइवेट और पब्लिक संस्थानों के साथ पार्टनरशिप शुरू कर चुकी है. हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म क्षेत्र में भी नौकरियों की भरमार होने वाली है. देश में मौजूदा समय में विभिन्न होटलों में क़रीब एक लाख दस हज़ार कमरे हैं. इनमें से, संगठित क्षेत्र में तक़रीबन 35 हज़ार कमरे हैं. उम्मीद है कि अगले पांच वर्षों में असंगठित क्षेत्र में कमरों की स ंख्या दोगुनी हो जाएगी.

ऐसे में निश्चित रूप से संगठित और असंगठित क्षेत्रों को मिलाकर अगले पांच साल में कर्मचारियों की संख्या दोगुनी से भी ज़्यादा हो जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक आई टी और आईटीईएस (इंफोरमेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन सर्विसेज) सेक्टर में रोज़गार वृद्धि की दर क्रमश: 7.3 और 7.2 प्रतिशत है, जबकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 8.9 फ़ीसदी है. कई क्षेत्र और हैं जहां नए-नए अवसर विकसित हुए हैं. जैसे स्वास्थ,आहार, टूरिज़्म व हॉस्पिटैलिटी, निर्माण आदि.

फूड एंड बिवरेज़ इंडस्ट्री

भारत के फूड एंड बेवरेज़ रिटेल इंडस्ट्री का अनुमानित मूल्य छह बिलियन डॉलर है और पिछले दो वर्षों से प्रति वर्ष 35 प्रतिशत बढ़ता रहा है. आगे भी इसके बढ़ने की संभावना है. कुछ वर्ष पहले फूड इंडस्ट्री में खाना पकाने के अलावा करियर के किसी और विकल्प के बारे में नहीं सोचा जा सकता था. इस इंडस्ट्री में आज के बढ़ते हुए अवसरों की वजह से यह इंडस्ट्री बड़ी मांग वाले क्षेत्रों में से एक है. करियर के इस क्षेत्र में केवल पाक-विद्या ही नहीं, आहार समीक्षा व लेखन, आहार पद्धति, आहार आस्वादन, फूड फोटोग्राफी, आहार तकनीकी, आहार व पोषण की विद्या यानी आहारिकी भी बेहतरीन विकल्प हैं. आहार को अपने प्रोफेशनल करियर से जोड़ने पर स्वास्थ्य और स्वाद पर विशेष टिप्पणी करने की ख़ासियत होनी ज़रूरी है. इसमें किसी विषय में स्नातक, पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट-ग्रेजुएट, सर्टिफिकेट कोर्स, शॉर्ट-टर्म कोर्स सभी उपलब्ध हैं. अपने सामर्थ्य और ज़रूरत के अनुसार इनमें से कोई भी कोर्स चुन सकते हैं. इनके लिए बारहवीं में 50 प्रतिशत से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. देश भर में कई संस्थानों में इन कोर्सेज का प्रशिक्षण दिया जाता है. आप अपने पसंद अनुसार कोर्स का चुनाव कर दाखिला ले सकते हैं .

स्वास्थ्य का क्षेत्र

इस क्षेत्र में डॉक्टर के अलावा और भी कई विकल्प हैं जो पिछले कुछ समय से उभर रहे हैं. इनमें शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के पुनर्सुधार के लिए किए जाने वाले काम का कोर्स प्रोस्थेटिक्स व ऑर्थोटिक्स हो, आंखों की देखभाल, नेत्र जांच में इस्तेमाल हो-नेवाले उपकरणों के रख-रखाव आदि की पढ़ाई ऑप्टोमेट्री हो, फिज़ियोथेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरपी, दंत चिकित्सा व मुंह की सेहत और रख-रखाव से जुड़ी प्रोस्थोडोनटिस्ट, बुज़ुर्गो की ख़ास मेडिकल देखभाल के लिए गेरीयाट्रिक्स, ढलती उम्र की पढ़ाई गेरोनटोलॉजी इत्यादि हो. इनकी मांग काफी ज़्यादा बढ़ी है, यही वजह है कि ऐसे कोर्स करने वाले कम हैं इसलिए इनकी पढ़ाई करने वालों की मांग ज़्यादा है. हमारे देश में इन कोर्स की पढ़ाई कई विश्वविद्यालयों में कराई जाती है. सभी कोर्स के लिए बारहवीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, और गणित के साथ बायोलॉजी में 50 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. इसके बाद ऊपर दिए कोर्सेज में स्नातक, पीजी डिप्लोमा, पोस्ट-ग्रेजुएट कर सकते हैं. ये कोर्सेज करने वाले प्रोफेशनल्स की नियुक्ति अस्पतालों, हेल्थ केयर सेंटर्स, क्लिनीक्स, नर्सिंग होम, ओल्ड ऐज होम इत्यादि जगहों पर होती है.

फोटो- प्रभात पाण्डेय

हॉस्पिटैलिटी/टूरिज़्म का क्षेत्र

इस क्षेत्र का दायरा हाल के वर्षों में बढ़ा है. विशेषज्ञों के मुताबिक प्रत्येक विकसित होते क्षेत्रों की तरह ही ट्रेवल एंड टूरिज़्म व हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी पेशेवर लोगों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. इस कोर्स को करने के बाद कई विकल्प खुलते हैं. इस इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए फुल टाइम कोर्सेज के अलावा शॉर्ट-टर्म कोर्स के विकल्प भी उपलब्ध हैं. बैचलर कोर्स के साथ मास्टर यानी पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स भी कर सकते हैं. फुलटाइम कोर्स में टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज़्म स्टडीज में स्नातक, टूरिज़्म मैनेजमेंट में पोस्ट-ग्रेजुएट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं. शॉर्ट-टर्म कोर्स में गाइडिंग एंड एस्कॉर्टिंग, कार्गो मैनेजमेंट, ग्राउंड सपोर्ट एंड मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी सर्विस व होटल मैनेजमेंट इत्यादि में शॉर्ट-टर्म कोर्स कर सकते हैं. भारत के कई विश्वविद्यालयों में इस कोर्स संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है. इन कोर्स को करने के बाद ट्रेवल एजेंसी, होटल क्षेत्र, एयरलाइंस, टूरिज़्म डिपार्टमेंट में नौकरी पा सकते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक यह ऐसा क्षेत्र है, जहां सुविधाओं और पैसों की कमी नहीं है और इस क्षेत्र में वेतन भी आर्कषक होता है. यह संस्थान, व्यक्ति की योग्यता और नौकरी के स्वरूप पर निर्भर करता है.

ritika@chauthiduniya.com

सूचना मांगने वाले बन रहे अपराधी

शिवदास

अगर आप *जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005* के तहत किसी सरकारी महकमे से जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मांगते हैं तो सावधान हो जाइए. संबंधित महकमा आपके ख़िलाफ़ साज़िश भी रच सकता है. यदि आप प्रशासन की कारगुज़ारियों को उजागर करने वाले पत्रकार अथवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आप पर जानलेवा हमला भी हो सकता है. संगीन अपराधों में आपके ख़िलाफ़ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है. ऐसा ही इन दिनों उत्तर–प्रदेश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र में *जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005* के तहत सूचना मांगने वालों के साथ हो रहा है. ज़िला प्रशासन ऐसे लोगों को जेल की हवा खिलाने और प्रताड़ित करने के लिए संवैधानिक क़ानूनों को ताक पर रख दे रहा है. *जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005*. केंद्र सरकार के शब्दों में कहें तो सरकारी महकमों से सूचना हासिल करने का अचूक हथियार. सोनभद्र में हज़ारों लोगों ने इस अचूक हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन इन्हें सूचना हासिल नहीं हो पाई. कुछ लोगों को आधी–अधूरी सूचना मिली तो कुछ को ग़लत जानकारी देकर अपने दायित्वों की इतिश्री कर ली गई. गरीबों को उनकी आर्थिक स्थिति से अधिक का बिल (बिना पृष्ठों की संख्या दिए) बनाकर पत्र भेज दिया गया. सैकड़ों ऐसे भी हैं, जिन्होंने हज़ारों रुपए ख़र्च कर राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग तक की दौड़ लगाई लेकिन मामला ढाक के तीन पात वाला ही रहा. कई ऐसे लोग हैं, जिन्होंने *जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005* के तहत सूचना मांगी थी और जिला प्रशासन के कोप का शिकार हुए.

किसी एक की कहानी नहीं है यह

चोपन थाना क्षेत्र के बिल्ली निवासी राधेश्याम भारती ने ज़िला खान अधिकारी पदेन जन सूचनाधिकारी, जिला खनिज अनुभाग सोनभद्र से दिनांक 10.12.2008, 27.12.2008, 27.01.2009 एवं 30.05.2009 को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगी. क़ानून के मुताबिक़ तय समयावधि में राधेश्याम भारती को सूचना नहीं दी गई. उन्होंने विभाग के बडे अधिकारियों से भी अपील की लेकिन सूचना नहीं दी गई. इसके बाद राधेश्याम भारती अपने कुछ साथियों के साथ इसी वर्ष 12 जून को ज़िला खान विभाग के सामने धरने पर बैठ गए. फिर, राधेश्याम भारती को खान अधिकारी ए.के. सेन द्वारा उनके पत्र का संज्ञान लेते हुए आधी–अधूरी जानकारी दी गई. पूरी जानकारी नहीं मिलने पर राधेश्याम भारती, हरिप्रसाद, रामनरेश आदि पिछले 13 अगस्त को एक बार फिर खनन अनुभाग के सामने धरने पर बैठे. इसी रात क़रीब 12 बजे कुछ लोगों ने राधेश्याम भारती और उनके साथियों पर हमला कर दिया. मामले की सूचना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस को दी गई. पुलिस एनसीआर (नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट) दर्ज़ कर मामले की विवेचना कर रही है. रॉबर्ट्सगंज के विकास नगर निवासी चौधरी यशवंत सिंह अपना दल के जिलाध्यक्ष हैं. उन्होंने जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005 का इस्तेमाल करते हुए ज़िला प्रशासन के विभिन्न विभागों से सूचना मांगी, लेकिन क़ानून के तहत समय से सूचना नहीं प्राप्त हुई. यशवंत सिंह ने ज़िला खान अधिकारी कार्यालय के सामने सूचना हासिल करने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. जवाबी कार्रवाई में ज़िला प्रशासन के नुमाइंदों ने चालू वर्ष की 16 जनवरी को यशवंत सिंह व उनके सहयोगियों को खदेड़ दिया. साथ ही प्रशासन ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में यशवंत सिंह, नागेन्द्र

पासवान व बबुंदर सिंह के ख़िलाफ़ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में मुक़दमा दर्ज करा दिया. ब्रह्मनगर निवासी पवन कुमार सिंह ने 26 जून 2008 को ज़िला प्रशासन से जनपद के विभिन्न विभागों में नियुक्त जन सूचना अधिकारियों की सूची मांगी. क़रीब 20 दिनों बाद ज़िला प्रशासन द्वारा पवन कुमार सिंह को जन सूचना अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराई गई. सूची में दिए गए नामों में से क़रीब 75 फ़ीसदी जन सूचना अधिकारियों का तबादला हो चुका है. इतना ही नहीं जिलाधिकारी का भी नाम सही नहीं था. जन सूचनाधिकार क़ानून पर काम करने वाले बभनी निवासी प्रमोद कुमार चौबे को भी कई विभागों से सालों बाद भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है. प्रमोद कुमार चौबे सूचना हासिल करने के लिए राज्य सूचना आयोग तक गुहार लगा चुके हैं. बहुअरा निवासी इरफानुल हक़ रब्बानी इन दिनों सूचना नहीं हासिल करने के लिए संबंधित व्यक्तियों की धमकियों से दो चार हो रहे हैं.

पत्रकार भी नहीं अपवाद

बीते वर्ष इस संवाददाता ने 21 अप्रैल को *जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005* के तहत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित जानकारी जन सूचना अधिकारी, ज़िला समाज कल्याण विभाग, सोनभद्र से मांगी. नतीजा यह निकला कि ज़िला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. रश्मि प्रभा शास्त्री व लिपिक चिंतामणि त्रिपाठी ने संवाददाता पर क़दम पीछे लेने का दबाव डाला. इसके बाद ज़िला समाज कल्याण विभाग का एक पत्र मिला जिसमें संवाददाता को स्टेशनरी, फोटो स्टेट तथा पोस्टेज के ख़र्च के लिए 4,950 रुपये जमा करने को कहा गया था, लेकिन पत्र में कहीं भी फोटो कॉपी होने वाले पृष्ठों की संख्या अंकित नहीं थी. संवाददाता ने 14 जुलाई 2008 को मुख्य विकास अधिकारी के डी राम के यहां प्रथम अपील दाखिल की, लेकिन एक साल गुज़र जाने के बाद भी संवाददाता को सूचना प्राप्त नहीं हुई है. इसी साल की एक जुलाई को संवाददाता हरियाली खुशहाली योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सोनभद्र के प्रभारी जन सूचनाधिकारी हाकिम सिंह के पास गया लेकिन इन्होंने सूचना देने से इंकार कर दिया. जब संवाददाता ने जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005 का हवाला दिया तो परियोजना निदेशक, हाकिम सिंह ने संवाददाता से बदतमीजी की और उसे कार्यालय से बाहर कर दिया. संवाददाता ने मामले की सूचना मुख्य विकास अधिकारी के डी राम को दी लेकिन परियोजना निदेशक हाकिम सिंह के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई. संवाददाता ने केंद्र सरकार की इंदिरा आवास योजना और राज्य सरकार की महामाया आवास योजना की हक़ीक़त जानने की कोशिश की. संवाददाता बीती 27 जुलाई को *जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005* के तहत इन योजनाओं से संबंधित सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र की प्राप्ति लेने ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय में गया. संवाददाता ने आवेदन पत्र देकर प्राप्ति प्रतिलिपि मांगी. लिपिक रिज़वाना ख़ातून ने अस्पष्ट हस्ताक्षर कर प्राप्ति प्रतिलिपि संवाददाता को दे दी. संवाददाता ने कार्यालय की मुहर लगाने का अनुरोध किया. लिपिक ने ऐसा करने से इंकार कर दिया. संवाददाता ने इस बात की शिकायत उच्चाधिकारियों से करने की बात कही. इस पर पास की कुर्सी पर बैठे मुख्य विकास अधिकारी के आशुलिपिक अवनीश कुमार और अन्य ने संवाददाता के साथ बदतमीजी की और कहा कि *तुम बार–बार सूचना मांगने आते हो. इसका मज़ा हम तुम्हें चखा देंगे.* संवाददाता ने घटना की सूचना मोबाइल के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी के.डी. राम को दी लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई. प्राप्ति प्रतिलिपि पर कार्यालय की मुहर नहीं लगाने और अस्पष्ट हस्ताक्षर करने के सवाल पर संवाददाता ने जिलाधिकारी पनधारी यादव से बात की. जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश है, यहां हाथोंहाथ दिए जाने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति प्रतिलिपि पर बिना कार्यालय की मुहर के और अस्पष्ट हस्ताक्षर के द्वारा ही प्राप्ति दी जाती है. जिलाधिकारी के इस बयान से संवाददाता हतप्रभ रह गया. संवाददाता को अगले दिन सूचना मिली कि मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में उसके ख़िलाफ़ भारतीय दंड विधान की धारा 353/504 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है. संवाददाता ने एफआईआर की नक़ल निकाली. ज़िला सूचना अधिकारी कार्यालय सोनभद्र में तैनात उर्दू अनुवादक निसार अहमद ने मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को सूचित किया था कि संवाददाता किसी भी मान्यता प्राप्त अख़बार का पत्रकार नहीं है, जबकि संवाददाता संपन्न भारत, अमर उजाला, साप्ताहिक स्पूतनिक, नई दुनिया, चौथी दुनिया, काल चिंतन, अमर भारती आदि समाचार पत्रों में वर्ष 2004 से समाचार, लेख, फीचर आदि लिखता रहा है. इतना ही नहीं संवाददाता पिछले पांच सालों से इंदौर और क़रीब 20 साल से लखनऊ से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र स्पूतनिक का मई 2008 से दिसंबर 2008 तक ज़िला सूचना कार्यालय सोनभद्र में बतौर ज़िला प्रतिनिधि पंजीकृत है. जिस वक़्त की यह बात है, उस समय संवाददाता एक सैटेलाइट न्यूज चैनल में नई दिल्ली में असिस्टेंट रन–डाउन प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत था. वर्तमान में संवाददाता दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का सदस्य भी है. इसके बावजूद ज़िला प्रशासन ने उर्दू अनुवादक निसार अहमद की भ्रामक जानकारी पर संवाददाता के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई.

सवाल यह है कि क्या आरएनआई की मान्यता प्राप्त अख़बार सरकारी नज़रों में मान्यता प्राप्त नहीं है और इन अख़बारों में लिखने वाले पत्रकार नहीं हैं? क्या पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की उपाधि धारक और क़रीब पांच साल तक पत्रकारिता क्षेत्र में लिख रहा व्यक्ति पत्रकार नहीं है? सूचना प्राप्त करने के अधिकार को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद भी सूचना मांगने वालों को प्रताड़ित करना कहां तक उचित है? ज़िला प्रशासन सहित राज्य एवं केन्द्र सरकार को इन प्रश्नों के जवाब आम जनता को देने की ज़रूरत है.

feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

(31 अगस्त से 6 सितंबर तक)

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
किसी संबंधी या मित्र के साथ चली आ रही ग़लतफहमी दूर हो जाएगी. स्थानांतरण के लिए प्रयास कर रहें है तो सफलता मिलेगी. पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. इसलिए खान–पान पर विशेष ध्यान दें.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
समाज के लिए काम करेंगे तो उसमें प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग बने हुए हैं. सत्ता का सहयोग मिलेगा. कोई ऐसा काम पूरा होगा, जिसका आपको एक लंबे समय से इंतज़ार था. कुल मिलाकर सप्ताह सफलता लेकर आएगा.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा. किसी अधिकारी या अधीनस्थ कर्मचारी के साथ अनबन हो सकती है. इस कारण आपको तनाव हो सकता है. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. शिक्षा के क्षेत्र में सावधानी बरतें. आजीविका के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
बिना किसी बात के उलझनें बढ़ेंगीं, जिसके कारण परेशान रहेंगे. परिवार के साथ समय ख़ुशी–ख़ुशी व्यतीत करेंगे. वाणी को मधुर बनाए रखने में ही भलाई है, नहीं तो अधिक बोलना हानिकारक हो सकता है. आर्थिक योजना सफल होगी. रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
पद, प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सचेत रहें. आप अगर घर में किसी मांगलिक काम को पूरा करने में सक्रिय हैं, तो उसमें सफलता मिल सकती है. संतान के करियर के संबंध में ख़ुशी का समाचार मिलने का योग है. जीवनसाथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, चिकित्सक से परामर्श करें. आर्थिक क्षेत्र में किसी प्रकार का जोखिम न उठाएं.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
कोई भी निर्णय सोच समझकर लें तो वह आपके लिए हितकर होगा. जीवनसाथी से आर्थिक सहयोग व प्रोत्साहन मिलेगा, घर में भौतिक सुख–सुविधाओं की वस्तुएं बढ़ेगी. गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है. आय के क्षेत्र में अगर कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
लंबे समय से लटके कार्य की पूर्ति होगी. धन, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की दिशा में चल रहा प्रयास सफल होगा. संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा. जिससे आपको ख़ुशी महसूस होगी. आपके कुछ कार्य सफल होंगे जिनकी वजह से आपको उपहार और सम्मान प्राप्त होंगे. देवदर्शन के योग बने हुए हैं.

वृश्चिक (21 अक्तूबर से 20 नवंबर)
रुके हुए कार्यों की पूर्ति हो जाएगी. अचानक से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें. ससुराल पक्ष से भरपूर सहयोग मिलेगा. आप अगर लेन–देन की योजना बना रहे हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
कोई जोख़िम भरा कार्य करने की न सोचें, क्योंकि कष्टकारी हो सकता है. शासन का सहयोग मिलेगा. विरोधी परास्त हो जाएंगे. आपसी संबंधों में और अधिक सुधार होगा. प्रवास की स्थितियां बन रही हैं, जो लाभदायक भी हो सकती है. उदर विकार या अन्य किसी रोग की संभावना है.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
धन,पद और प्रतिष्ठा की दिशा में चल रहा प्रयास सफल होगा. किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग मिलेगा साथ ही कोई मूल्यवान वस्तु पाने की इच्छा पूरी होगी. नए संबंधों के बनने से लाभ मिलेगा. काम करने की क्षमता बढ़ेगी. आर्थिक क्षेत्र में आय के नए रास्ते खुलेंगे.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
कहीं दूर जाने की सोच रहे हैं तो अवश्य जाएं. सफलता मिलने की संभावना है. किसी निर्णय को लेने से पहले सोच–विचार लें. अहंकार से बचें, नहीं तो संबंधों में तनाव आने की आशंका बनी हुई है. जीविकोपार्जन के उद्देश्य से यात्रा के योग है, बिटिया के विवाह के संबंध में किया जा रहा कार्य सफल होगा.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, नहीं तो दुर्घटना होने की आशंका है. आपको कहीं से अचानक लाभ मिलने की संभावना है. संतान के प्रति दायित्वों की पूर्ति होगी. पेट से संबंधित कोई शिकायत हो सकती है. आय और व्यय दोनों पर नियंत्रण बनाए रखें. परिवार वालों का सहयोग मिलेगा.

ज्योतिषाचार्य पं. सुदर्शन

मेरी दुनिया.... बीजेपी की महाभारत ...धीर

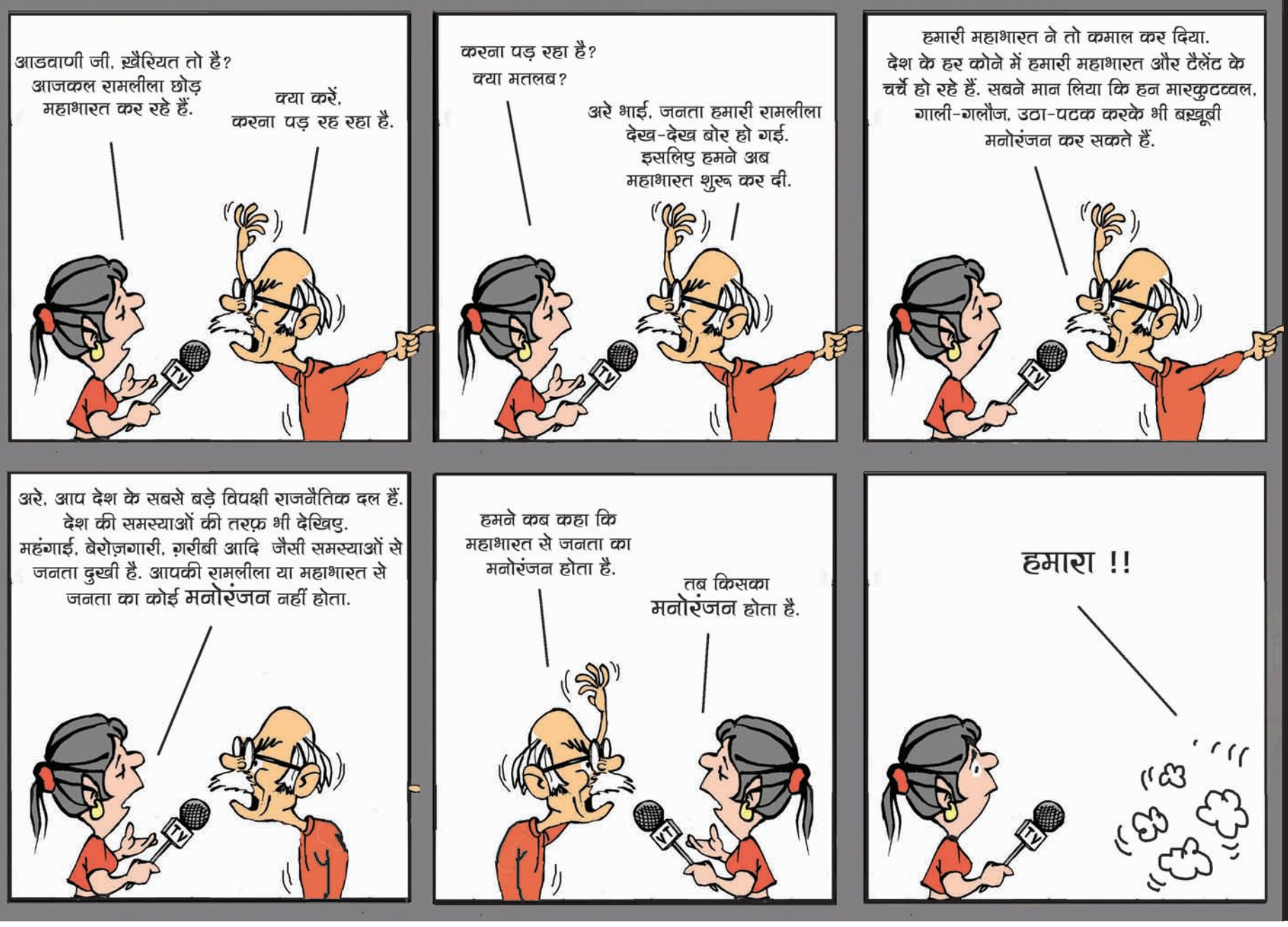

देवानंद की प्रेम कहानियां

अनंत विजय

फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कई किताबें बाज़ार में आई हैं. सबसे पहले फिल्म साप्ताहिक स्क्रीन की संपादक रह चुकी भावना सोमैया ने ड्रीम गर्ल की जीवनी लिखी, जो रोली बुक्स, नई दिल्ली से छपी. इस किताब में भावना सोमैया ने हेमा मालिनी के शुरुआती दिनों का बेहतर चित्रण किया है. हालांकि, जैसे-जैसे हेमा मालिनी सफल होती गई, भावना भी उनके प्रभाव में आती गई और जीवनी गुणगान में बदलती चली गई. इसके बाद शाहरुख ख़ान पर दो किताबें-अनुपमा चोपड़ा की, किंग आफ बॉलीवुड आई, तो रोली बुक्स, नई दिल्ली शाहरुख पर ही दीपा गहलोत की किताब, किंग ख़ान के नाम से आई. इसमें दीपा गहलोत की किताब बेहतर है. इसके अलावा वैजयंती माला ने भी अपनी आत्मकथा लिखी. सुनील दत्त की बेटियों, नम्रता और प्रिया दत्त ने मिलकर सुनील दत्त और नरगिस को केंद्र में रखकर मिस्टर और मिसेज दत्त (रोली बुक्स, नई दिल्ली) लिखी. इस किताब में सन् 1958 में सुनील दत्त और नरगिस की शादी से लेकर 1981 में कैंसर से नरगिस की मौत तक की मार्मिक कहानी है और कुछ दुर्लभ चित्र भी. रोली बुक्स की प्रस्तुति हर बार की तरह इस बार भी बेहतरीन है .

तमाम शोरगुल के बीच हिंदी फिल्मों के सदाबहार हीरो देवानंद की आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ- एन ऑटोबायोग्राफी, (पेंग्विन बुक्स,नई दिल्ली) आई, जो आते ही चर्चित हुई. कहा जा रहा है कि छपने के दो महीने के अंदर ही इस किताब का दूसरा संस्करण प्रकाशित हो गया था. इसमें किताब के कंटेंट से ज़्यादा कई शहरों में जाकर इसके विमोचन के बहाने मार्केटिंग करना ज़्यादा कारगर हो रहा है. अपनी इस आत्मकथा में देवानंद साहब ने अपनी निजी ज़िंदगी और भारतीय फिल्म जगत के कई राज़ खोले हैं .

देवानंद की छवि एक ज़बर्दस्त रोमांटिक हीरो की रही है. अविभाजित भारत के गुरुदासपुर में जन्मे देवानंद ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी(आनर्स) करने के बाद लंदन जाकर उच्च शिक्षा हासिल करने की सोची थी. पिता की मुफ़लिसी की वजह से यह संभव नहीं हो सका. परिवार की कमज़ोर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर जब देवानंद ने रॉयल इंडियन नेवी में शामिल होने की कोशिश की, तो वहां भी असफलता ही हाथ लगी. देवानंद अपने पिता की इच्छा के विपरीत बंबई आ गए. फिर शुरू हुआ संघर्ष. यहां भी बनना चाहते थे गायक, लेकिन बन गए अभिनेता. इसके बाद जो हुआ वह इतिहास है. फिर देवानंद ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा. देवानंद की पहली फिल्म थी- हम एक हैं . इस फिल्म के रिलीज़ होते ही देवानंद के अभिनय की न केवल नोटिस ली गई, बल्कि जमकर तारीफ़ भी हुई. इसके बाद तो देवानंद, उस दौर के दो सबसे सफल हीरो, दिलीप कुमार और राजकपूर के साथ फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बन गए. उन्होंने उस दौर की तमाम चोटी की अभिनेत्रियों के साथ फिल्मों में तो काम किया ही, रोमांस भी कम नहीं किया. देवानंद और सुरैया के बीच के रोमांस और प्रेम की ख़ूब चर्चा हुई और अब अपनी आत्मकथा-रोमांसिंग विद लाइफ -में देवानंद ने अपनी इस प्रेम कहानी का विस्तार से वर्णन किया है. देवानंद लिखते हैं,- हम दोस्त से गहरे दोस्त और फिर प्रेमी प्रेमिका बन गए, हमारी प्रेम कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी. एक भी दिन ऐसा नहीं

होता था जब मैं और सुरैया फोन पर बात नहीं करते थे, मुझे सुरैया से प्यार हो गया था, लेकिन उस वक्त सुरैया के परिवार में उसकी दादी का ज़बरदस्त प्रभाव था और उनकी मर्जी के बिना उस परिवार में पत्ता तक नहीं हिलता था. मुझे लगने लगा कि हमारी इस प्रेम कहानी में सुरैया की दादी बाधा बन रही थी. मेरा सुरैया के घर में अब पहले जैसा स्वागत नहीं होता था. लेकिन प्यार की तड़प बढ़ती ही जा रही थी. मैं सुरैया के लिए बेचैन होने लगा था. सुरैया के परिवार ने हमारे प्यार पर बंदिशें लगा दी थीं. मिलने-जुलने पर रोक लगी थी. एक दिन हम चुपके से एक पानी टंकी के पास मिले और सुरैया ने मुझसे लिपटकर कहा- आई लव यू, आइ लव यू. इसके बाद मेरे पांव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे. मैंने जावेरी बाज़ार से सुरैया के लिए एक मंहगी अंगूठी ख़रीदी और उसे भिजवा दिया. मैं सातवें आसमान पर था, लेकिन अपने परिवार के दबाव में सुरैया ने मेरी दी हुई अंगूठी समंदर में फेंक दी. देवानंद साहब ने इस प्रेम कहानी को बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में अपनी आत्मकथा में कलमबंद किया है. इस पूरी किताब से देवानंद की पर्दे पर की जो एक बेहद रूमानी छवि थी, वह और भी पुष्ट होती है. हालांकि पूरी किताब को फिर से पढ़ने के बाद मुझे लगा कि प्रेम संबंधों की चर्चा करते हुए देव साहब कई जगह फिल्मी हो जाते हैं. सुरैया के अलावा देवानंद ने अपनी इस आत्मकथा में स्कूली दिनों की प्रेमिका से लेकर अबतक की अपनी नायिकाओं और प्रेमिकाओं के बारे में खुलकर लिखा है. चाहे वे *टैक्सी ड्राइवर* फिल्म की नायिका मोना हों, जो बाद में देवसाहब की पत्नी भी बनीं या फिर मुमताज़ हो या फिर ज़ीनत अमान हों या टीना मुनीम. ज़ीनत अमान पर लिखते हुए देव साहब ने ईमानदारी से स्वीकार किया है कि जब भी राज कपूर ज़ीनत अमान से लिपटते-चिपटते थे, तो उनको जलन होती थी. देवानंद को लगता था कि ज़ीनत अमान उनकी खोज है, उनकी नायिका है, इसलिए सिर्फ़ उनकी अमानत है. जब एक पार्टी में राजकपूर ने ज़ीनत अमान को अपने आलिंगन में लिया तो ज़ीनत का रिस्पांस देखकर देवानंद का दिल चकनाचूर हो गया.

देवानंद जब एक नायक के रूप में फिल्मों में कामयाब हो गए तो *नवकेतन* नाम से अपना बैनर बनाकर फिल्म निर्माण में उतरे और कई नई प्रतिभाओं, टीना मुनीम से लेकर तब्बू तक का फिल्मी दुनिया से साक्षात्कार कराया. फिल्म निर्माण के बाद देवानंद फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में उतरे और फिल्म *प्रेम-पुजारी* का निर्देशन किया. देवानंद की फिल्में *गाइड*, *काला पानी*, *हरे रामा हरे कृष्णा*, *काला बाज़ार* और *जब प्यार किसी से होता है* वगैरह हिंदी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में मील का पत्थर हैं. इन फिल्मों के निर्माण के दौरान और विदेशों में शूटिंग के दौरान की कई कहानियां देवानंद ने लिखी है जो ये साबित करने के लिए लिखी गई प्रतीत होती हैं कि लड़कियां देवानंद के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहती थीं. रहती होंगीं, लेकिन कई जगह वर्णन ज़रा काल्पनिक सा प्रतीत होता है.

देवानंद ने अपनी आत्मकथा में फिल्मी हस्तियों के अलावा राजनैतिक हस्तियों का भी ज़िक्र किया है. ख़ासतौर से इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी का. इंदिरा गांधी के बारे में देवानंद ने लिखा है कि वह बहुत ही कम बोलती थीं, जिसकी वजह से उनके विरोधी इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे. देव साहब ने इंदिरा गांधी के साथ कई मुलाक़ातों का ज़िक्र किया है लेकिन हर बार उन्हें लगा कि श्रीमती गांधी, नकारात्मक या सकारात्मक किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया देती ही नहीं है.

अगर हम इसी बहाने हिंदी और अंग्रेजी प्रकाशकों की स्थिति पर विचार करें तो एक चीज़ पाते हैं कि अंग्रेजी के प्रकाशक अवसर और मौक़ा देखकर योजनाबद्ध तरीक़े से काम करते हैं. वहीं हिंदी के प्रकाशकों में योजनाबद्ध तरीक़े से काम करने की न तो आदत होती है और न ही अब तक प्रवृति विकसित हो पाई है. 1857 की क्रांति के डेढ़ सौ साल को ध्यान में रखकर अंग्रेजी के प्रकाशकों ने योजनाबद्ध तरीक़े से काम किया था, नतीजा 1857 की क्रांति के डेढ़ सौ साल के जश्न के मौक़े पर कई बेहतरीन किताबें आईं. वहीं अगर हिंदी पर ग़ौर करें तो बस रस्मअदायगी के तौर पर इक्का-दुक्का किताबें ही छपी. हिंदी का इतना बड़ा बाज़ार है, लेकिन हिंदी के प्रकाशक बजाए इस बाज़ार में संभावनाएं तलाशने के सरकारी ख़रीद में ही तिकड़म भिड़ाने में जुटे हैं.

(लेखक आईबीएन7 से जुड़े हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

जैन दर्शन और सनातन धर्म

व्यालोक

इससे पहले हम सनातन धर्म और उसकी अनेकानेक शाखाओं पर चर्चा कर चुके हैं. कुछ पहले के अंकों में हमने बौद्ध दर्शन और सनातन धर्म के पारस्परिक संबंधों पर चर्चा की. इसके अलावा, वैष्णव मत, शाक्त मत और शैव मत वगैरह की सनातन धर्म की विविध शाखाओं के रूप में हम चर्चा कर ही चुके हैं. इस बार हम जैन दर्शन और सनातन धर्म के परस्पर संबंध और एक-दूसरे पर पड़े उनके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे. विस्तार से तो चर्चा होती रहेगी, लेकिन इस बार बात जैन दर्शन या धर्म की मुख्य मान्यताओं की.

जैन धर्म को भी इसके अनुयायी वैदिक धर्म इतना ही मानते हैं. जैन कथाओं या अनुश्रुतियों के अनुसार चौदह मनु हुए हैं. अंतिम मनु को नाभिराम माना जाता है. उनके ही पुत्र ऋषभदेव थे, जिनको जैन धर्म का आदि तीर्थंकर माना गया है. कई कथाएं तो ऐसी हैं, जिनके मुताबिक तिथियों का क्रम ही गड़बड़ हो जाता है. हमारे देश भारत का नाम जिस राजा भरत के नाम पर पड़ा है, वह दरअसल ऋषभदेव के ही पुत्र थे. कथा तो यह भी है कि ऋषभदेव ने ही शुरुआती तीन वर्ण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना की. जब संसार से वैराग्य लेकर वन की ओर चले गए, उन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया, तो भरत ने इन्हीं तीन वर्णों में से सुशील और ज्ञानी व्यक्तियों को लेकर ब्राह्मण वर्ण का निर्माण किया.

जैन कथाओं के मुताबिक अगर चलें तो श्रीकृष्ण के पूर्व जैनों के 21 तीर्थंकर हो चुके थे. इसके पीछे का तर्क यह है कि जैन ग्रंथों में नेमिनाथ को श्रीकृष्ण का चचेरा भाई बताया गया है. वह 22 वें तीर्थंकर थे. इसका सीधा सा मतलब यह है कि कृष्ण से पहले भी जैनों के 21 तीर्थंकर हो चुके थे. अगर हम इसे सच मान लें, तो यह भी मानना पड़ेगा कि जैन धर्म की परंपरा महाभारत से हज़ारों नहीं तो सैकड़ो वर्षों पुरानी तो हो ही जाएगी. कुछ परंपराओं के मुताबिक तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता को भी जैन धर्म से जोड़ दिया गया है. असल में इस सब पर अगर ध्यान दें, तो इसके पीछे का कारण और कुछ नहीं, हमारी जाति का अपने इतिहास के प्रति अज्ञानता-बोध या असावधानी का भाव ही है. दरअसल, हमारे यहां इतिहास-लेखन का काम किसी परंपरा या व्यवस्थित क्रम से तो किया नहीं गया है. एक तो हमारे यहां लेखन की परंपरा रही नहीं, श्रुति परंपरा ही चलती आ रही. इस तरह हमने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने साहित्य, कला और इतिहास को केवल सुनकर और कंठस्थ कर संरक्षित किया. इसमे सबसे बड़ा गोलमाल यह हुआ कि एक से तीसरी पीढ़ी तक आते-आते मूल पाठ में ख़ासा बदलाव हो गया. वजह यह कि दूसरी पीढ़ी ने अपनी तरफ़ से भी कुछ श्लोक बढ़ा दिए. इसके अलावा इतिहास के नाम पर हमारे यहां जो पुराण मौजूद हैं, वे भी दंतकथाओं और कपोल-कल्पनाओं का अड्डा बन गए हैं. हमारे कहने का मतलब यह नहीं कि हमें अपना इतिहास-बोध नहीं रहा. दरअसल, इसकी वजह तो यह थी कि अहं से रहित होकर काम करने का ही यह नतीजा रहा कि हमारे यहां लेखन का काम व्यवस्थित नहीं हो पाया. वरना, सोचने की बात है कि वेदों और उपनिषदों के अधिकतर मंत्रों के रचयिता खुद को परदे के पीछे क्यों रखते?

हमारे कहने का मतलब बेहद सीधा है कि जैन और सनातन धर्म में कौन पुराना है और कौन नया, इस पर सीधे उंगली रख देना बहुत टेढ़ा काम है. इसके पीछे का तर्क भी देख लें. रामायण के हनुमान महाभारत में भी नज़र आते हैं, तो परशुराम भी सदियों तक पाए जाते हैं. हमारा मत तो यह है कि शायद ये सब उपाधियां थीं. ख़ैर, यह तो विषयांतर हो गया.

जैन धर्म पर हमारी शृंखला आगे लंबी चलेगी. बस कहना यह है कि जैन धर्म की दो मुख्य विशेषताएं अहिंसा और तप हैं. यह प्राग्वैदिक काल में भी थीं और उसी का विकास जैन धर्म में हुआ, जो छठी शताब्दी में भगवान महावीर के नेतृत्व में बेहद संगठित और सशक्त हो गया.

आगे इस पर विस्तार से.

vyalok@chauthiduniya.com

पिछले अंक में आपने पढ़ा कि अख़बार के पहले पेज पर इंस्पेक्टर भेसाड़िया के साहस का क़िस्सा देख कर इकबाल ने अपनी पीठ थपथपाई. अब आगे पढ़िए कि उसके बाद क्या हुआ...

मुसलमान

सब कुछ ठीक-ठाक निपट गया न, बेटे?

इक़बाल ने फुर्ती के साथ एक रुपये का नोट उसके सामने बढ़ाया. भेसाड़िया ने दोनों नंबर पर एक नज़र डालकर मुस्कान फैलाई. फिर अपनी जेब से सौ-सौ रुपये के दस नोट निकालकर उस पर एक रुपये का नोट भी रख दिया.

यह तुम्हारा कमीशन.

नोट जेब में रखकर इक़बाल खड़ा हो गया.

जल्दी है? भेसाड़िया ने पूछा.

उसने हां कहते हुए बताया, दोपहर के बाद कॉलेज में हाज़िरी लगवानी है.

भेसाड़िया ने भी खड़े होकर उसकी पीठ थपथपाई, शाबाश फिर आगे कहा, एक दिन तुम ज़रूर नाम रोशन करोगे.

कार में बैठते हुए इक़बाल सोचने लगा कि भेसाड़िया ने उसे किस बात की शाबाशी दी होगी? उसकी पढ़ाई की लगन देखकर या दोनों जॉकिटों की सफल डिलीवरी के कारण? वह निर्णय नहीं कर पाया.

अलबत्ता, इतना निश्चित था, एक ईमानदार युवक के रूप में इक़बाल का नाम भेसाड़िया की डायरी में दर्ज़ हो गया था. भेसाड़िया की उंगली पकड़कर वह भविष्य में सोने की तस्करी में लाखों की हेराफेरी करने वाला था.

आबिद भाई एकाएक अपनी बात बीच में रोककर उसने वही पुराना प्रश्न दोहराया, तस्करी किसे कहते हैं?

जवाब मैं जानता ता, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होने वाले माल पर अगर ड्यूटी न भरी जाए तो उसे तस्करी कहते हैं.

अब यह बताइए कि आप तस्कर किसे कहेंगे? कहते हुए उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, उस आदमी को जो दुबई से क़ानूनन सोना भारत भेजता है? उन टंडेलों को जो अपने जहाज़ में सोना लेकर भारत आते हैं? उस गैंग को जो रात के अंधेरे में जहाज़ पर सोने की डिलीवरी लेता है? उस जौहरी को जिसके यहां गैंग सोना पहुंचाता है? या उस अदृश्य माफ़िया को, जिसे जौहरी पैसा चुकाता है? और याद रहे, उस अदृश्य इंसान ने स्मगलिंग के काम में कहीं भी सक्रिय भाग नहीं लिया है. बोलिए, इन सबमें तस्कर कौन है? आप किस पर उंगली उठाएंगे?

टाइपाइड में एक महीना हबीब हॉस्पिटल में बिताकर जब मैं बाहर आया तो लगा जैसे मेरा शरीर अतीत में कहीं रह गया था. जो कुछ घर पहुंचा था, वह मेरा अस्थिपंजर था. दूसरे का सहारा लिए बिना घूमना-फिरना तो दर किनार, मेरे लिए खड़ा रहना भी मुश्किल था.

इक़बाल भाग्यशाली था, जो न्यूमोनिया से दो हफ़्ते के भीतर ही चंगा होकर फिर से सक्रिय हो गया था.

और पंद्रह दिन मैंने घर पर बिताए. इन पंद्रह दिनों में मुझे अस्पताल का मेरा कमरा बराबर याद आता रहा. वहां पश्चिम की ओर खुलती अपनी खिड़की में से मैं प्रकाश देखता. डूबते सूरज की लाली अपनी आंखों में लगाता, कभी-कभी एक ही दिशा में पंक्तिबद्ध होकर यात्रा करते पक्षियों को देखता, तकिए के सहारे बैठकर अनाथाश्रम चिल्ड्रेंस होम के बच्चों की दिनचर्या में दिलचस्पी लेता और इस तरह मेरा समय बीत जाता.

यहां सुल्तान मेंशन की पहली मंज़िल की मेरी अंधेरी कोठरी में सिर्फ़ एक खिड़की थी. उसमें जड़ी खड़ी सलाख़ें जेल के प्रतीक समान थीं.

दूसरे, वह खिड़की गटर की ओर खुलती थी. कभी-कभी जब गटर भर जाती तो उसमें से सिर फट जाए, ऐसी दुर्गंध निकलती थी. हालांकि गटर अस्पताल में रह लेने के बाद मेरी कुछ आदतें छूट गई थीं. विशेष में, वहां से कुछ नई आदतें भी ले आया था.

वहां खिड़की में से आती धूप से मेरी यारी हो गई थी. दोपहर के बाद धूप मेरी चारपाई पर किसी अरब के तंबू में प्रवेश करते ऊंट की तरह आती थी. मुझे अच्छी लगती थी. हम दोनों साथ बैठकर खेलते थे.

मैं अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक-दूसरे में डालकर धूप में रखता. मेरी चारपाई पर बिछी उजली चादर पर एक छायाचित्र बनाने में सफलता प्राप्त की.

परंतु यहां, मेरे अंधेरे में, धूप की आमद की गुंजाइश नहीं थी. सूर्य का दर्शन करने के लिए नीचे जाकर फुटपाथ पर खड़ा रह सकूं, मुझमें इतनी शक्ति नहीं थी. कोई उपाय नहीं था. बिना कोई उद्यम किए शांत पड़ा रहना मेरा स्वभाव भी नहीं था.

अब यह बताइए कि आप तस्कर किसे कहेंगे? कहते हुए उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, उस आदमी को जो दुबई से क़ानूनन सोना भारत भेजता है? उन टंडेलों को जो अपने जहाज़ में सोना लेकर भारत आते हैं? उस गैंग को जो रात के अंधेरे में जहाज़ पर सोने की डिलीवरी लेता है? उस जौहरी को जिसके यहां गैंग सोना पहुंचाता है?

मैंने बाल-कहानियों के विषयों पर सोचना शुरू किया. ये कथाएं मैं कार्टून कॉमिक्स को ध्यान में रखकर सोचता था. (रमकडु गुजराती बाल मासिक में लोकप्रिय मेरे तीन शरारती पात्र-सोनू, भगु और लखुड़ी की टोली का जन्म इन्हीं दिनों हुआ था.)

इसके पहले मैंने न कुछ रचनात्मक लिखा था, न लिखने के विषय में सोचा था. अलबत्ता पॉकिट-कार्टून और छोटी चित्रपट्टी के लिए आइडिया ज़रूर खोजता था, पर चार पन्नों की चित्रकथा के लिए अच्छी-खासी बालकथा तैयार करनी पड़ती थी.

मैंने आधा दर्ज़न कहानियां तैयार कीं और स्वस्थ होते ही एक शाम अपनी फाइल लेकर डॉ. आर.जे. चीनवाला के घर पहुंचा. वे घर पर नहीं थे, पर उनके फ्लैट में बसें उर्दू के लेखक मुश्ताक़ जलीली इब्राहीम जलीस की कोई पुस्तक पढ़ते हुए बैठे थे. हक़ीक़त में मैं उन्हीं से मिलने के उद्देश्य से वहां गया था.

उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए मैंने अपनी बाल-कथाओं के आइडिया उन्हें हिंदुस्तानी में कह सुनाए. पलभर वे मेरे सामने देखते रहे. फिर कहा, आबिद, मेरे साथ काम करना पसंद करोगे?

मेरी आंखें स्थिर हो गईं, कौन सा काम?

फिल्मों के लिए जो कहानियां मैं लिख रहा हूं, उनके लिए मुझे एक सहायक की ज़रूरत है.

पर..... मैंने कहा, मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है.

उन्होंने हंसकर पूछा, ये बाल-कहानियां किसने लिखी हैं?

मैंने कहते हुए मुझे अनोखा आनंद हुआ. मेरी कहानियों में ज़रूर कोई ख़ास बात होगी, नहीं तोयह लेखक मुझे अपना सहायक बनाने का प्रस्ताव न रखता. दूसरे, उनके साथ उनकी कहानियों पर काम करते-करते मैं उनकी टेकनीक भी जान सकता था.

हर लेखक की विचार-पद्धति और शैली अलग-अलग होती है. मुश्ताक़ जलीली की भी अपनी विशिष्ट शैली थी. कहानी गढ़ने का उनका अपना गणित था. इस गणित को समझने और सीखने का अवसर मैं गंवा नहीं सकता था. मैंने उनका प्रस्ताव बख़ुशी स्वीकार कर लिया.

डॉ. चीनवाला का घर मुझे फला था. यहां एक साथ मुझे दो-दो गुरु मिले थे-चित्रकाम के लिए यूसुफ धाला और लेखन के लिए मुश्ताक़ जलीली.

कहा जाए तो इंस्पेक्टर भेसाड़िया की छत्रछाया इक़बाल को भी फली थी. दोनों जॉकिटों को डिलीवर करनेका भेसाड़िया का काम उसने सरलता से अंजाम दिया था. इसके बदले उसे एक जॉकिट के 500 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये कमीशन मिला था (शगुन का एक रुपया अलग).

इसमें से लगभग आधे रुपये कर्ज़ चुकाने में निकल गए. बाक़ी के रुपये ख़त्म होने से पहले ही भेसाड़िया ने उसे एक और जॉकिट डिलीवर करने का काम सौंपा. इसके दो महीने तक भेसाड़िया का फोन नहीं आया.

घर की हालत फिर डांवाडोल होने लगी. इक़बाल की सांस अधर में अटक गई. उसे लगा भेसाड़िया का कैरियर (माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला) बनकर जीना कठिन है, क्योंकि इस अनिश्चितता का असर उसकी पढ़ाई पर भी होने लगा था.

कॉलेज के पहले वर्ष की परीक्षाएं क़रीब आ रही थीं. उसकी चिंता यह नहीं थी कि वह पास होगा कि फेल. परीक्षा के एकाध सप्ताह पहले नोट्स पर एक बार सरसरी नज़र डाल ले तो भी वह सफल हो सकता था. पर वह केवल सफल ही नहीं होना चाहता था, बल्कि उसे विशेष योग्यता के साथ फर्स्ट क्लास भी लाना था.

वह ज़बरदस्ती पढ़ाई में अपना ध्यान लगाने का प्रयास कर रहा था कि पड़ोसी ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया. इसके साथ ही बंद दरवाज़े के बाहर से आवाज़ उठी, इक़बाल तुम्हारा फोन है. पुस्तक औंधी रखकर फ़ौरन उठ खड़ा हुआ.

जल्दी से पड़ोसी के घर में दाख़िल हुआ और रिसीवर में कहा, हैलो

फोन भेसाड़िया का था. कल दोपहर को उसे भवंस कॉलेज की गली में एक गैराज के पास मिलने को कहा ता. समय एक तथा दो के बीच निश्चित हुआ था.

आधा दिन कॉलेज में बिताकर वह दोपहर में बाहर निकला और ठीक एक बजकर सात मिनट पर गैराज पहुंच गया. भेसाड़िया वहां पहले से ही हाज़िर था. उसकी जीप में कोई ख़राबी आ गई थी और वह उसी की मरम्मत करवाने यहां आया हुआ था.

(अगले अंक में जारी)

फ्यूजी के साथ सहेजें इस ओणम की यादों को

फ्यूजीफिल्म्स इंडिया लिमिटेड को उम्मीद है कि अपने वादे के मुताबिक वह डिजिटल कैमरे के क्षेत्र में अगले तीन साल तक 15 फ़ीसदी बाज़ार पर क़ब्ज़ा कर लेगी. इसके लिए वह मेहनत भी कर रही है. इसका उदाहरण केरल में देखने को मिला. ओणम त्योहार के मौक़े पर कंपनी ने दो नए कैमरे लांच किए हैं. केरल में ओणम त्योहार पूरे उत्साह के साथ दस दिन तक मनाया जाता है. इस अवसर पर लोग जमकर ख़रीदारी करते हैं. इसी त्योहार को कैश करने की कोशिश में है फ्यूजी. फ्यूजीफिल्म्स फाइनपिक्स एस1500 और फ्यूजीफिल्म्स फाइनपिक्स एफ200 ईएक्सआर को स्पेशल ऑफर के साथ त्योहार के मौके पर लांच किया गया. फ्यूजीफिल्म्स फाइनपिक्स एस1500 को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसमें कम पावर की खपत होती है. एए बैटरी के साथ इससे 300 शॉट आप ले सकते हैं, जबकि एए लिथियम बैटरी के साथ आप 700 तक शॉट ले सकते हैं. इसके दूसरे फीचर्स भी बेहतरीन हैं, जैसे दस मेगापिक्सल,

फ्यूजीफिल्म्स फाइनपिक्स एस1500 और फ्यूजीफिल्म्स फाइनपिक्स एफ200 ईएक्सआर को स्पेशल ऑफर के साथ त्योहार के मौक़े पर लांच किया गया. फ्यूजीफिल्म्स फाइनपिक्स एस1500 को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसमें कम पावर की खपत होती है.

वाइड एंगल के साथ सुपर ज़ूम, फ्यूजन 12*ऑप्टिकल ज़ूम, फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, डुअल इमेज स्टैबिलाइजेशन, न्यू ट्रैकिंग ऑटो फोकस फंक्शन आदि. इस कैमरे की बाज़ार में क़ीमत 13,399 रुपए है.

फ्यूजीफिल्म्स फाइनपिक्स एफ 200ईएक्सआर में सुपर सीसीडी ईएक्सआर सेंसर जोड़ा गया है, जो इमेज क्वालिटी को और भी बेहतर बना देता है. फीचर्स के मामले में यह सामान्य कैमरे से बहुत आगे है. यह विश्व का पहला प्वाइंट एंड प्वाइंट कैमरा है, जिसमें तीन वैकल्पिक सेंसर मोड्स (जैसे फाइन कैप्चर मोड, पिक्सल फ्यूज़न मोड और ड्यूल कैप्चर मोड), ईएक्सआर ऑटो मोड, फ्यूज़न 5.0*वाइड एंगल ऑप्टिकल ज़ूम लेंस, 3.0' रेजोल्यूशन का एलसीडी, डुएल इमेज स्टैबिलाइजेशन फेस डिटेक्शन 3.0 इत्यादि है.बाज़ार में इसकी क़ीमत 18,999 रुपये है.

टू 7 ऑर नॉट टू 7

नए विंडोज पर उलझे हैं यूजर्स

माइक्रोसॉफ्ट (एमएस) के नए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 की पहली झलक अब लोगों के सामने है. अब तक जो दिखा है उसने एमएस के उपभोक्ताओं को परेशानी में डाल दिया है. परेशानी इस बात की नहीं है कि विंडोज 7 उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा क्योंकि इसके ट्रायल वर्ज़न का इस्तेमाल कर चुके लोग यही मान रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 अबतक का सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम(ओएस) है. उनकी परेशानी इस बातसे है कि क्या विंडोज़ 7 के लिए वे अपने पसंदीदा विंडोज़ एक्सपी को अलविदा कह दें.

माइक्रोसॉफ्ट ने अभी पिछले हफ्ते विंडोज7 के ट्रायल वर्ज़न का मुफ़्त डाउनलोड बंद कर दिया है. इस ट्रायल वर्ज़न को लोग 120 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं. विंडोज़ 7 ट्रायल वर्ज़न को मुफ्त में यूजर्स तक पहुंचाकर एमएस ने संकेत दे दिया है कि वह विंडोज विस्टा के साथ हुई भूल दोहराना नहीं चाहता. विस्टा एमएस का पिछला ओएस था, जिसकी खामियों के कारण उसकी बहुत आलोचना हुई थी. अब विंडोज7 को बाज़ार में उतारने से पहले एमएस इस विंडोज7 आरसी के ज़रिए अपने उत्पाद को परख लेना चाहता है.

इस ट्रायल वर्ज़न का इस्तेमाल करने वाले अधिकतर लोगों का मानना है कि यह ओएस बेहतरीन है, लेकिन कितना, इस पर लोगों की राय अलग-अलग है. आइए, इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े कुछ ख़ास पहलुओं पर नज़र डालें, जिससे यह साफ़ हो सके कि किसको कितना फ़ायदा और किसको क्या नुक़सान हो सकता है. किसके लिए यह नया ओएस ख़ास है और किसे यह लुभा नहीं पाएगा.

1. पुराने पीसी वाले : जो लोग पुराने कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और उसे नई तकनीक के लिए समय-समय पर अपग्रेड करते हैं, उनके लिए अभी तक लीनक्स सबसे सही ऑप्शन रहा है. इसके तीन कारण हैं - लीनक्स लाइट (कम स्पेस वाला) ओएस है, यह वायरस रहित ओएस है और सबसे अच्छा यह है कि यह एक मुफ़्त ओएस है. इसके मुक़ाबले विंडोज 7 को देखकर लगता है कि पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ने पुराने कंप्यूटर्स को ध्यान में रखते हुए ओएस बनाया है.

विंडोज़ 7 का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यह बहुत कम स्पेस लेता है, हालांकि कागज पर इसका वर्क स्पेस विस्टा से ज़्यादा है लेकिन यह उससे कम परेशान करता है. इसके अलावा विंडोज 7 एक अपग्रेड फैमिली पैक के साथ आता है जो इसकी क़ीमत को काफी कम कर देता है. इसके साथ ही कई यूजर्स ने विंडोज 7 आरसी को एमएस के दावे से भी नीचे की मेमोरी वाले सिस्टम पर चलाने में सफलता हासिल की है. इसे आसानी से 512 और 256 एमबी रैम पर भी चलाया जा सकता है, और तो और इसके साथ किसी भी पुराने वर्ज़न के प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को भी चलाया जा सकता है.

2. विंडोज विस्टा वाले : विंडोज 7 के आने से सबसे ज़्यादा ख़ुशी विस्टा इस्तेमाल करने वालों को हो रही है. विंडोज विस्टा को विंडोज के सभी ओएस में सबसे ज़्यादा आलोचना झेलनी पड़ी है. इसमें कई तकनीकी समस्याएं हैं. अब उम्मीद जताई जा रही है कि विंडोज 7 में इन समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा. ऐसे में उम्मीद है कि विंडोज विस्टा का इस्तेमाल कर रहे लोग विंडोज 7 को हाथों हाथ अपनाएंगे.

3. विंडोज एक्सपी वाले : यही ग्रुप है जो विंडोज विस्टा को लेकर सबसे ज़्यादा दुविधा में है. कुछ लोगों का कहना है कि वे विंडोज 7 के फीचर्स से प्रभावित हैं और उसे अपनाने वाले हैं. वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि विंडोज 7 अच्छा तो है लेकिन इतना नहीं कि उसके लिए एक्सपी को छोड़ दिया जाए.

हालांकि विंडोज 7 सस्ता ओएस है और इसके लिए एमएस ने नया एक्सचेंज कार्यक्रम शुरू किया है, फिर भी एक नया ओएस अपनाना एक लंबा और जटिल काम है. ऐसे में कई लोग हैं जो विंडोज 7 की जगह पुराने एक्सपी प्रोफेशनल से ही ख़ुश हैं. बहरहाल, विंडोज 7 के कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो उन लोगों की सोच बदल सकता हैं. जहां एक्सपी अब नए हार्डवेयर के लिए उपयुक्त नहीं है, वहीं विंडोज 7 को नवीनतम तकनीक पर डिज़ाइन किया गया है. विंडोज7 में सिक्योरिटी फीचर्स भी अपग्रेड किए गए हैं. साथ ही इसकी एक बड़ी ख़ूबी इसका नया एयरो इंटरफेस है. इसके अलावा इंस्टालेशन और ड्राइवर अवेलिबिलटी में भी आठ साल पुराना एक्सपी अपने नए जेनरेशन के प्रतिद्वंद्वी से पीछे ही है.

विंडोज 7 को बाज़ार में उतारने का वक़्त नज़दीक है. 22 अक्टूबर से यह अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में आ रहा है. वैसे अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में नयापन चाहते हैं तो विंडोज 7 एक अच्छा विकल्प है और अगर आप अपने ओएस से पूरी तरह है ख़ुश हैं तो भी विंडोज 7 के लिए एक खिड़की खुली रखिएगा.

भुवन ने किया निराश

इसरो का गूगल अर्थ को हराने का दावा असल में फिसड्डी साबित हुआ है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (इसरो) की 3-डी मैपिंग सेवा भुवन, गूगल अर्थ से टक्कर में कमज़ोर साबित हो रहा है. मल्टी-रेजोल्यूशन, मल्टी-सेंसर और मल्टी टेंपोरल इमेज, ग्राफिक-व्यू में सूचनाएं, यूजर की पसंद के हिसाब से मौसम और प्रशासनिक सीमाओं की जानकारी और किसी भी जगह जाने की सुविधाओं का दावा करने वाला भुवन उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है.

इस सेवा के लांच के पहले ही दिन से इसकी परेशानियों की शुरुआत हो गई. पहले हफ़्ते ही इसकी वेबसाइट की हालत ख़राब रही और वह बार-बार हैंग होती रही. जो वेबसाइट तक पहुंच कर इसके लिए रजिस्टर कर पाए उन्हें इसके प्लग-इन के डाउनलोड होने के लिए भी घंटों इंतज़ार करना पड़ा. आख़िरकार इतनी परेशानियों के बाद जब भुवन खुला तो इससे बेहतर दृश्यों की आस लगाए यूजर्स को भारी निराशा ही हाथ लगी. इसरो ने भुवन के ज़रिए महज़ 10 मीटर ऊपर से दृश्य दिखाने की बात की थी (गूगल अर्थ में यह 200 मीटर है) लेकिन अभी तक यूजर्स को ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिले हैं जो इस तरह के किसी दावे को सच बनाते हों. नेविगेशन पैनल आसानी से लोड नहीं होता, यहां तक की लोगों को इसे इस्तेमाल करने में भी परेशानी होती है. इसके साथ ही यह गूगल अर्थ जितना यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है. लोगों को पहले एक अकाउंट बनाकर भुवन के लिए एक प्लग-इन डाउनलोड करना पड़ता है. हालांकि यूजर इसमें कोई टैग या जानकारी नहीं जोड़ सकता. साथ ही एक ही नाम की दो जगहों को सर्च करने पर भी यह ठीक से काम नहीं करता. इसके बीटा वर्ज़न में इसका सबसे महत्वपूर्ण फीचर यानी मौसम की जानकारी नहीं मिल पाती. हालांकि भुवन में मौसम के डाटा, जनसंख्या के बारे में जानकारी और इसरो के सैटेलाइट्स की मदद से दी गई दूसरी जानकारियों शोध करने वालों और विशेषज्ञों के लिए मददगार हो सकती हैं. साथ ही सूखे और बाढ़ से जुड़े मानचित्र भी काम के हैं.

यह सारे फीचर्स तो अच्छे हैं लेकिन बड़े यूजर नेटवर्क को आकर्षित करने और वर्तनाम मैपिंग सेवाओं को टक्कर देने के लिए नाकाफी हैं. इसके लिए भुवन को हाई-रेसोल्यूशन इमेज दिखाने होंगे. आम लोगों को उनका घर या स्कूल साफ-साफ नज़र आना चाहिए. अगर भुवन के पीछे काम कर रहे लोग इन बातों को तेज़ी से समझकर ज़रूरी बदलाव नहीं ला पाए तो गूगल को पछाड़ने का इसका दावा पानी पर खींची लकीर ही साबित होगा.

वाकमैन हैंडसेट्स धूम मचाने को तैयार

यदि आप किफ़ायती और अच्छी क्वॉलिटी के वाकमैन हैंडसेट्स ख़रीदने का मन बना रहे हैं तो अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है. सोनी एरिक्सन ने संगीत प्रेमियों के लिए कम क़ीमत पर दो नए वॉकमैन हैंडसेट्स डब्ल्यू-395 और डब्ल्यू-205 लांच करने की घोषणा की है. ये दोनों सेट्स लुक्स के मामले में तो काफी आकर्षक हैं ही, साथ ही किफ़ायती भी हैं. डब्ल्यू-205 हैंडसेट्स से- डब्ल्यू-205 फेमस हैंडसेट डब्ल्यू-200 आई का ही नया वर्ज़न है. अंतर सिर्फ़ इतना है कि यह स्लाइडर फॉर्मेट में है. वॉकमैन डिवाइस लगे होने के कारण, इसमें वो सभी फीचर्स मौजूद हैं, जिसकी ज़रूरत संगीत प्रेमियों को होती है. जैसे-वाकमैन प्लेयर स्टार्ट-अप, एफएम रेडियो के साथ रिकॉर्डिंग और ट्रैक आईडी म्यूजिक की पहचान. इसके अलावा दूसरे ज़रूरी फीचर्स जैसे 1.3 मेगापिक्सल कैमरा, जीपीआरएस और ईडीजीई को सपोर्ट करने वाला ब्लूटूथ, 128*160 रेजोल्यूशन, एक जीबी के साथ एम-2 कार्ड सपोर्ट भी शामिल है. यह हैंडसेट आपका हो सकता है, इसके लिए आपको अपनी जेब से महज़ 5,795 रुपये ख़र्च करने होंगे.

वहीं डब्ल्यू-395 वॉकमैन हैंडसेट, फीचर्स के मामले में डब्ल्यू-205 से आगे है. इसमें स्पेशल स्टीरियो स्पीकर्स लगे हुए हैं. म्यूज़िक स्टोर करने के लिए एक जीबी का मैमोरी कार्ड और एफएम रेडियो को नियंत्रित करने के लिए एक ख़ास की लगा है. यह उसे सबसे नए गानों से अप-टू-डेट रखता है. इसमें सोनी एरिक्सन का बेहतरीन फीचर्स ट्रैक आईडी भी लगा हुआ है, जो गानों को ढूंढने में मदद करता है. यहां तक कि अगर आपको गाने का नाम याद नहीं या फिर उसके गायक का पता नहीं, तो भी आप ऐसे गानों को ढूंढ सकते है. इसका दो इंच का स्क्रीन भले ही छोटा लगे लेकिन इसमें तस्वीरें साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं. इसमें दो मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ, जो कैजुअल फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन है. बाज़ार में इसकी क़ीमत 8,395 रुपये तय की गई है.

आईटी के मंदिर : गैरेज हॉस्टल और बेकार कमरे

367, एडीशन एव, पालो अल्टो, कैलिफोर्निया

साल 1939, प्रसिद्ध स्टैंफोर्ड विश्वविद्यालय के क़रीब स्थित एक12 गुना18 फीट के गैरेज में कॉलेज के दो दोस्तों ने एक कंपनी की शुरुआत की. बिव ह्यूलेट और डेव पैकार्ड के लिए यह गैरेज एक रिसर्च लैब के तौर पर थी. किसे पता था कि इस रिसर्च लैब से शुरु हुई उनकी कंपनी एक दिन ह्यूलेट-पैकार्ड यानी एचपी दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर उत्पादक बन

2066 क्रिस्ट डीआर, लॉस एल्टोस, कैलिफोर्निया

एप्पल कंप्यूटर्स की शुरुआत स्टीव जॉब्स के घर के एक बेकार पड़े बेडरूम में हुई थी. यह कमरा भी असल में उनके घर से सटा एक गैरेज ही था. यहीं स्टीव जॉब्स ने अपने मित्र स्टीव वॉजनैक और राबर्ट जी वेन के साथ मिलकर एप्पल की शुरुआत की. उस दिन मूर्ख दिवस था.

232, सांता मार्गारिटा एवेन्यू, मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया

यह पता शायद इंटरनेट के इतिहास के सबसे अहम पतों में से एक है. यहीं से दो दोस्तों लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन ने एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था-गूगल. यही आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ा सर्च ईजनऔर इंटरनेट कंपनी बनने वाली थी. पेज और ब्रिन ने यह गैरेजनुमा कमरा सुसान वोजसिस्की (वह भी बाद में गूगल में काम करने लगीं)से 1700 डॉलर महीने पर किराए पर लिया था.

कर्कलैंड हाउस, हावर्ड विश्वविद्यालय

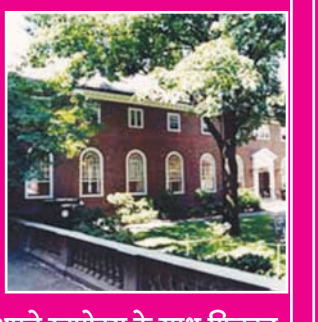

क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे मशहूर नेटवर्किंग साइट फेसबुक की शुरुआत कहां से हुई. हावर्ड के कर्कलैंड हाउस के तीसरे फ्लोर पर मार्क ज़ुकरबर्ग ने अपने रूममेट्स के साथ मिलकर फेसबुक गढ़ा. आज यह 250 मिलियन लोगों की पसंद है.

वाशिंगटन स्टेट विश्वविद्यालय

इस विश्वविद्यालय के ही एक कमरे में कंप्यूटर के दीवाने दो दोस्तों ने एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की रचना की. किसे पता था कि आगे चलकर वह दुनिया का सबसे लोकप्रिय सिस्टम बन जाएगा. यह कमरा पॉल एलेन का था और उससे दो साल छोटा उसका दोस्त था-बिल गेट्स. उस कंपनी का नाम रखा गया ट्रैफ-ओ-डाटा, जिसे बाद में बदलकर माइक्रोसॉफ्ट कर दिया गया.

किसकी लापरवाही की सज़ा चुकाएगी सायना?

सभी फोटो– पीटीआई

भारतीय बैडमिंटन में एक ही सितारा है. यह सितारा पिछले साल की चाइना मास्टर्स सुपर सीरीज़ में उभरा था. सायना नेहवाल नाम की एक लड़की इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक पहुंची थी. क्वार्टरफाइनल के रोमांचक मुक़ाबले में सायना ने विश्व–चैंपियन चीनी खिलाड़ी झू लीन को शिकस्त दी थी. इस साल वह इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगी. क्यों? जवाब सुनकर कोई भी हैरान रह जाए.

यह अजीब बात है कि जिस चाइना मास्टर्स सुपर सीरीज़ से सायना नेहवाल ने पहली बार विश्व बैडमिंटन में अपनी उपस्थिति दर्ज़ की थी, इस साल उसमें नहीं खेलने की वजह कोई चोट या मजबूरी नहीं है. वजह भारतीय बैडमिंटन संघ का ग़ैर–पेशेवर रवैया है. जी हां, भारतीय बैडमिंटन संघ के काम करने के तरीक़े की वजह से ही वह चाइना मास्टर्स सुपर सीरीज़ में नहीं खेल सकती. जो साइना विश्व चैंपियनशिप में खेलने के लिए चिकेन पॉक्स को हराकर मैदान में उतरी थी, वही बस एक काग़ज़ से हार गई हैं. सीरीज़ में भाग लेने का आ–वेदन ही एक दिन देर से भेजने की वजह से यह सारा क़िस्सा सामने आया है. अब बैडमिंटन संघ और खिलाड़ियों के बीच इसे लेकर आरोप–प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है. संघ अपनी ग़लती मानने को तैयार नहीं है. जहां संघ इसके लिए खिलाड़ियों को ही क़सूरवार ठहरा रहा है, वहीं वी. दीजू जैसे सीनियर खिलाड़ी इसके लिए पूरी तरह संघ को ज़िम्मेदार मान रहे हैं. उनका कहना है कि उन्होंने सुपर सीरीज़ में भाग लेने की सूचना संघ को तीन–चार महीने पहले ही दे दी थी, लेकिन बैडमिंटन संघ प्रविष्टि भेजना ही भूल गया.

संघ के अध्यक्ष वी के वर्मा के मुताबिक़ खिलाड़ियों की यह ज़िम्मेदारी होती है कि प्रतियोगिता में भाग लेने की सूचना वे संघ को दें और खिलाड़ियों को किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रविष्टि ई–मेल के ज़रिए गिरीश नाटू को भेजनी होती है. नाटू का कहना है कि खिलाड़ियों ने ही प्रविष्टि एक दिन बाद भेजी थी और संघ अपनी मर्ज़ी से प्रविष्टि नहीं भेज सकता. किसी खिलाड़ी के मना करने पर संघ को 250 अमेरिकी डॉलर जुर्माने के तौर पर देना पड़ता है. इन बातों से तो यही लगता है कि बैडमिंटन संघ और खिलाड़ियों में तालमेल कम और घालमेल ज़्यादा है.

यह अजीब बात है कि जिस चाइना मास्टर्स सुपर सीरीज़ से सायना ने–हवाल ने पहली बार विश्व बैडमिंटन में अपनी उपस्थिति दर्ज की थी, इस साल उसमें नहीं खेलने की वजह कोई चोट या मजबूरी नहीं है.

दरअसल चाइना मास्टर्स सुपर सीरीज़ के लिए प्रविष्टि भेजने की अंतिम तारीख़ 11 अगस्त थी, और संघ ने 12 अगस्त को आवेदन भेजा. इसका ख़ामियाजा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता से दूर रहकर चुकाना पड़ेगा. खिलाड़ियों की चिंता इस बात से अधिक है कि न खेल पाने की वजह से उनकी रैंकिंग नीचे चली जाएगी, नतीजतन उनका विश्व सीरीज़ मास्टर्स के लिए क्वालीफाई करना मुश्किल हो जाएगा. सायना यह कहकर– कि ग़लतियां दोनों तरफ़ से हुई हैं और अब अफ़सोस करने के अलावा कोई उपाय नहीं– शायद मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रही हों, लेकिन कुल मिलाकर यही बात सामने आती है कि पूरे मसले में कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही हुई है, जिसकी ज़िम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है. सोचने वाली बात यह भी है कि आख़िर ऐसी घटना अगर क्रिकेट में होती तो क्या होता. क्या इसी तरह मामला रफ़ा–दफ़ा कर दिया जाता. सारा मामला ही लापरवाही का है. अब जब काग़ज़ के खेल पर ही हम इतने ढीले–ढाले हों तो ऐसे में हम मैदान पर अपने खिलाड़ियों से अच्छे खेल की उम्मीद कैसे करें. जहां तक बात रही दुनिया में खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बनने की तो–हमें जन्नत की हक़ीक़त मालूम हैं, आप चाहे दिल को बहलाने के लिए कितने भी मुगालते पाल लें.

और कितना तेज़?

उसैन, आप और कितना तेज़ दौड़ सकते हैं? यह सवाल तब पूछा गया था जब उसैन बोल्ट ने पिछले साल ओलंपिक में 100 मीटर की दौड़ में अपना ही विश्व रिकार्ड तोड़ा था. बोल्ट का जवाब था– इससे बहुत तेज़. उस वक़्त उन्होंने समय निकाला था–9.69 सेकेंड. अब ठीक एक साल बाद उसैन बोल्ट ने अपने उस जवाब को सही साबित किया है, इस बार उनका समय है–महज़ 9.58 सेकेंड. सवाल फिर वही है क्या बोल्ट और तेज़ दौड़ सकते हैं? लगता तो है.

उसैन बोल्ट ने बर्लिन में 100 मीटर का विश्व रिकार्ड तोड़ने के बाद 200 मीटर की दौड़ में भी विश्व कीर्तिमान बनाया. 19.19 सेकेंड में 200 मीटर की दौड़ के आख़िरी 100 मीटर का सफर बोल्ट ने महज़ 9.27 सेकेंड में तय किया. हालांकि 100 मीटर में इतना तेज़ दौड़ना अभी संभव नहीं लगता लेकिन जिस तरह से बोल्ट दौड़ रहे हैं, वह यह सोचने पर मजबूर तो करता ही है कि इंसानी गति की सीमा क्या है?

पुराने ज़माने में एक मील का सफर चार मिनट में तय करने की बात असंभव मानी जाती थी. फिर एक दौर आया जब 100 मीटर की दौड़ में 10 सेकेंड से कम का वक़्त निकालना एक चुनौती बन गया. अब बात साढ़े नौ सेकेंड की हो रही है. आख़िर हम कहां तक जा सकते हैं? अगर दुनिया में इंसानों की तुलना की जाए तो सबसे तेज़ इंसान बोल्ट की गति (29 मील प्रति घंटे) अभी किसी हाथी(20–25 मील) या बिल्ली (25 मील) से ज़्यादा और रेस में दौड़ने वाले कुत्ते(35 मील) या घोड़े से (40–45 मील) से बहुत कम है. दुनिया में सबसे तेज़ जीव चीता (80 मील हर घंटे) है. तो क्या इंसान कभी चीते की रफ़्तार से दौड़ पाएगा? नहीं, इंसानी शरीर इस लायक़ नहीं. सबसे तेज़ एथलीट 30 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से दौड़ रहे हैं और हमारे शरीर की बनावट हमें इससे 10 मील और तेज़ होने की इजाज़त देती है. साथ ही पिछले कुछ सालों में 100 मीटर का रिकार्ड तोड़ने वाले सभी लोग पश्चिम अफ़्रीकी या पश्चिम अफ़्रीकी मूल के रहे हैं. बोल्ट ख़ुद इस बात पर मज़ाकिया लहज़े में कहते हैं कि वह सबसे स्वस्थ और फिट रहे गुलामों के वंशज हैं. ताज्जुब कि बात है कि कोई भी श्वेत धावक आजतक 10 सेकेंड से कम में 100 मीटर नहीं दौड़ पाया है. पिछले छह वर्षों में 100 मीटर का यह रिकार्ड नौ बार टूट चुका है, लेकिन बोल्ट ने इसे सबसे ज़्यादा अंतर से तोड़ा है. एथलीट और कभी 100 मीटर के विश्व रिकार्ड धारी रहे मौरिस ग्रीन कहते हैं–बोल्ट 9.4 सेकेंड तक जा सकते हैं, वह तो अभी दौड़ना सीख रहे हैं.

हालांकि अधिकतर विशेषज्ञ कहते हैं कि साढ़े नौ सेकेंड में 100 मीटर संभव नहीं है, लेकिन ऐसा तो वह चार मिनट में एक मील और 10 सेकेंड से कम में 100 मीटर दौड़ने की बात पर कहते रह चुके हैं. जहां तक बोल्ट की बात है तो वह अपने विश्व रिकार्ड के बाद कह चुके हैं कि वह थकान के कारण थोड़े धीमे रहे. अगर यह धीमा था तो फिर सबसे तेज़ कैसा होगा? सवाल फिर वही है आख़िर कितना तेज़? वे कभी चीते को पछाड़ नहीं सकते या पांच सेकेंड में 100 मीटर नहीं दौड़ सकते लेकिन यह खिलाड़ी हमें और भी रोमांचित ज़रूर करता रहेगा.

अलविदा आस्ट्रेलिया!

आस्ट्रेलिया का मज़बूत क़िला आख़िकार ढह ही गया. ऐशेज हारकर आस्ट्रेलिया ने आख़िरी जंग भी गंवा दी है. अब उसकी बाद–शाहत का आख़िरी खंभा भी भरभराकर गिर गया. जिस टीम ने कभी हारना सीखा ही नहीं था, एक ऐसी टीम जिसने कभी जीतने के कई विश्व कीर्तिमान कायम किए, आज अपनी हार पर मातम मनाने के सिवा उसके पास कोई विकल्प नहीं है. वह अब एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी है. हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रही है. आस्ट्रेलिया ऐसी कभी नहीं थी, लेकिन इस बार इंग्लैंड ने ऐशेज में ऐसी पटखनी दी कि वर्षों से चले आ रहे कंगारुओं के प्रभुत्व को ही नेस्तनाबूद कर दिया. टेस्ट क्रिकेट के सिरमौर का ख़िताब भी दक्षिण अफ़्रीका ने क़ब्ज़ा लिया, वहीं सालों तक क्रिकेट का सरताज़ रहने के बाद अब आस्ट्रेलिया सीधे नंबर चार पर पहुंच चुका है. आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग ने उसे दक्षिण अफ़्रीका, श्रीलंका और भारत के बाद चौथे पायदान पर ला दिया है. अब वह दौर ख़त्म हो चुका, जब क्रिकेट के हर प्रारूप में चाहे वह एकदिवसीय हो या टेस्ट, कंगारुओं ने अपनी श्रेष्ठता साबित की थी. लेकिन कहते हैं न, शीर्ष पर पहुंचना तो आसान है, लेकिन वहां बने रहना बेहद मुश्किल. ऊंचाई के बाद ढलान तो आना ही है. ठीक यही हाल कंगारुओं का हुआ. हाल में शीर्ष की पांच टीमों में ऐसी कोई टीम नहीं, जिसने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त न दी हो. जब ऐशेज शुरू हुआ तो आस्ट्रेलिया की रैंकिंग 124 थी और इसकी समाप्ति के बाद वह 116 पर लुढ़क गई. आईसीसी टेस्ट कैलेंडर के मुताबिक आने वाले समय में इसमें सुधार की गुंजाइश भी बहुत कम ही है. मशहूर ऑस्ट्रेलियाई खेल पत्रकार पीटर रोबक की मानें तो क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई दबदबा तभी से ख़त्म होने लगा जब भारतीय टीम ने अनिल कुंबले के नेतृत्व में 2007–08 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और कुख्यात सिडनी टेस्ट में हार के बाद भारतीयों ने पर्थ की उछाल भरी तेज़ पिच पर जीत के साथ जबरदस्त वापसी की थी. हालांकि भारत शृंखला हार गया, लेकिन उसके बाद ही ऑस्ट्रेलिया के पतन की कहानी शुरू होती है. फिर तो दक्षिण अफ़्रीका और भारत ने कंगारुओं को ऐसी शिकस्त दी जिससे उबरना अभी भी उसके लिए संभव नहीं हो पाया है. अब इंग्लैंड के हाथों ऐशेज गंवाना उसके इसी पतन की कहानी का अंतिम एपीसोड है.

इन सबके बीच सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि बिली मर्डोक के बाद रिकी पोंटिंग ऐशेज सीरीज़ दो बार गंवाने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान भी बन गए हैं. बेचारे बड़बोले पोटिंग इस सम्मान(?) से ख़ुश तो नहीं ही होंगे. हालांकि एक बात यह भी ग़ौर करने वाली है कि जहां एक–एक कर जस्टिन लैंगर, ग्लेन मैक्ग्रा, शेन वार्न, एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडेन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के संन्यास के बाद इनका विकल्प न मिल पाना भी ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ, वहीं इसके कई दिग्गज खिलाड़ियों का दूसरी सांस्कृतिक (पढ़ें मछली मारने, नाइट क्लब में शराब पीने आदि) गतिविधियों में व्यस्त रहना भी उस पर भारी पड़ा.

फ़िदा कर गए फ्रेडी...

अपने आख़िरी टेस्ट मैच में भी शानदार खेल दिखाकर एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने जीत के साथ विदाई ली.

फिर से शुरू हुई कोच की किचकिच

लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली और मालिक शाहरुख ख़ान से एक बात ज़रूर सीखी है, हार न मानना. भले ही किंग ख़ान की केकेआर पर पिछले साल के लचर प्रदर्शन के बाद आईपीएल की सबसे फिसड्डी टीम का दाग़ लग गया हो, लेकिन टीम एक बार फिर पूरी तैयारी से इस दाग़ को मिटाने में जुट गई है. तैयारियों की इस फ़ेहरिस्त में सबसे ऊपर एक कोच की कमी ख़त्म करने का ज़िम्मा है. जॉन बुकानन की विदाई के बाद से ही कोच का पद ख़ाली है. अब केकेआर के कोच की पद पर नई नियुक्ति की कवायद शुरू हो गई है. दूर–दूर से उम्मीदवार आ रहे हैं, अपनी दा–वेदारी पेश कर रहे हैं.

इंग्लैंड को बतौर कोच ऐशेज जिता चुके डंकन फ्लेचर केकेआर (कोलकाता नाइट राइडर्स) के कोच पद के लिए आश्चर्यजनक तरीक़े से सबसे प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं. उन्होंने केकेआर के मालिक बादशाह ख़ान के घर जाकर मुलाक़ात की. दावेदारी पेश करने वालों में फ्लेचर के अलावा इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर डरमट रीव, दक्षिण अफ़्रीका के पूर्व कोच एरिक सिमेंस और पूर्व भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी डब्ल्यू रमन भी हैं. मज़े की बात यह कि दक्षिण अफ़्रीका के पूर्व खिलाड़ी और पाकिस्तान के कोच रहे रिचर्ड पायबस ने भी केकेआर के अधिकारियों से मुलाक़ात की. उन्हें अगले दौर की बातचीत के लिए रोका गया है. इससे यह क़यास भी लगाया जा रहा है कि उन्हें दूसरे प्रतियोगियों की अपेक्षा ज़्यादा तवज्जो मिल सकती है. आईपीएल के शुरुआती सीजन में केकेआर के कप्तान रहे सौरभ गांगुली पहले हुए इंटरव्यू के पैनल में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद हुए इंटरव्यू में गांगुली के साथ–साथ शाहरुख की पार्टनर जूही चावला भी मौजूद रहीं. उधर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी माइकल बेवन ने भी पूर्व भारतीय सहायक कोच लालचंद राजपूत और अशोक मल्होत्रा के समक्ष साक्षात्कार दिए. न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और जॉन राइट भी इस सप्ताह के अंत तक केकेआर प्रबंधन से मिल सकते हैं.

ज़ाहिर है, केकेआर के कोच की रेस गर्म हो रही है. शाहरुख सबको ठोक–बजा कर चुनना चाहते हैं. सही भी है, पिछली बार कोच और कप्तान के चक्कर में जो गति हुई, वह शाहरुख भूले नहीं होंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

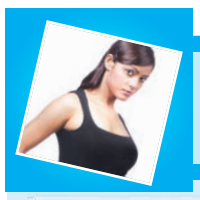

कुश्ती के लिए टाली शादी

अभिनेत्रियों का छोटे पर्दे पर आना आज की बात नहीं यह ट्रेंड तो बहुत पुराना हो चुका है. अब टीवी पर नज़र आने वाले सितारों की फ़ेहरिस्त में ईशा कोप्पिकर को भी देखेंगे. वह एक रियलिटी शो होस्ट करेंगी. शो का नाम *सौ प्रतिशत दे दना दन* है. ईशा के लिए यह पहला मौक़ा है जब उन्हें कोई रियलिटी शो होस्ट करने को मिल रहा है, इसलिए वह इसे खोना नहीं चाहती है. वैसे ईशा फिल्मों में तो ख़ास धमाल नहीं मचा पाई हैं, अब वह सोच रही हैं कि छोटे पर्दे पर जादू बिखेर दें. वैसे यह शो कोई संगीत या हंसी से जुड़ा शो नहीं है. यह रियलिटी शो कुश्ती पर आधारित है. डब्ल्यूडब्ल्यूई की तर्ज पर होने वाली इस कुश्ती में भारतीय पहलवान दुनिया भर के चुन हुऐ पहलवानों से टक्कर लेंगे. इस शो में कुश्ती चैंपियन दारा सिंह भी मेंटर के रुप में दिखेंगे जो प्रतियोगियों को टिप्स देते हुए दिखाई देंगे. ईशा, शरत सक्सेना के साथ इन मुक़ाबलों का हाल सुनाती नज़र आएंगी. कुश्ती पर आधारित इस रियलिटी शो के लिए ईशा इतनी उत्साहित हैं कि उन्होंने अपनी शादी तक टाल दी है. पहले ख़बर आई थी कि उनकी शादी अक्टूबर में होने वाली थी. यह शो अगले चार महीने तक चलेगा, इससे तो लगता है अब शादी इसके बाद ही होगी. वैसे पहले तो ईशा यह समझ नहीं पा रही थी कि वह करें क्या– शादी या रियलिटी शो. वैसे ईशा, शादी भी किसी रियलिटी शो से कम थोड़े ही है. ख़ैर, अब देखते हैं कि आपकी कुश्ती कहां तक सफल हो पाती है.

कच्ची उम्र के साथ खिलवाड़

बचपन अब मासूम नहीं रहा. तेज़ी से आगे बढ़ने की होड़ और दुनिया पर छा जाने की ख्वाहिशें बच्चों पर हावी हैं. वह भी इस कदर कि कच्ची उम्र में ही वह डिप्रेशन के शिकार होने लगे हैं. टीवी सीरियल और रियलिटी शो में शामिल होने वाले बच्चों में यह ज़्यादा देखने को मिलता है. हालिया वाकया सीरियल झांसी की रानी से जुड़ा है. इसमें झांसी की रानी के बचपन की भूमिका निभाने वाली आयशा भी इसी होड़ का शिकार बनी है. हुआ यूं कि झांसी की रानी की मुख्य भूमिका निभा रही आयशा को बीच में ही ड्रॉप कर उसकी जगह उल्का गुप्ता को ले लिया गया. हालांकि –आयशा ख़ास इस रोल के लिए चार महीनों से घुड़सवारी और तलवारबाज़ी सीख रही थी. यहां तक कि आयशा ने अपना स्कूल तक बदल दिया था क्योंकि पहले स्कूल से छुट्टी नहीं मिल रही थी. इतनी मेहनत के बावज़ूद बीच में ड्रॉप किए जाने से वह तनाव में आ गई और डिप्रेशन में भी चली गई, जिसके चलते उसे विशेषज्ञ के पास परामर्श के लिए ले जाना पड़ा. सबसे अजीब बात यह है कि आयशा को उसकी एक्टिंग की कमी की वज़ह से नहीं निकाला गया बल्कि बीच सीरियल में प्रोडक्शन हाउस बदल जाने की वज़ह से उसे बाहर का रास्ता देखना पड़ा. इस सीरियल के पुराने प्रोडक्शन हाउस को किसी कारण से यह सीरियल छोड़ना पड़ा.

जब यह सीरियल नए प्रोडक्शन हाउस कोन्टीलो फिल्म के पास गया तो उन्होंने आयशा की जगह उल्का को प्रमुख रोल में ले लिया.

शुरूआत में *झांसी की रानी* के प्रोमो में आयशा ही दिखती थी. अब उल्का के दिखने से वह काफी तनाव में आ गई थी. वैसे आयशा तीन फिल्मों और कुछ सीरियल में काम कर चुकी हैं और उनका कहना हैं कि एक सीरियल से निकाले जाने पर उनका करियर ख़त्म नहीं होगा. उनकी मां लीना का कहना है कि आगे कभी किसी बच्चे को बीच में से न निकाले, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे को बहुत ठेस पहुंचती है. अच्छी बात है कि आयशा अब इससे उबर रही हैं. आयशा शुरू में तो काफी परेशान थी लेकिन अब अपने को काफी मज़बूत महसूस कर रही है.

पुरानी पहचान से परेशान

कहते हैं पुरानी यादें कभी भी पीछा नहीं छोड़ती. वह तो इंसान को चारों तरफ़ से घेरे रखती है. पुरानी यादें मिटाना इतना आसान नहीं होता. ऐसी ही परेशानी प्राची देसाई की भी है. प्राची को लगता है कि दर्शक अभी भी उन्हें बड़े पर्दे पर काम कर रही अभिनेत्री के रूप में नहीं जानते, बल्कि छोटे पर्दे पर निभाए किरदार बानी के नाम से ज़्यादा जानते हैं. बानी के किरदार की यादें और असर प्राची का पीछा नहीं छोड़ रहे है. ख़ैर, प्राची तो बड़े पर्दे पर नाम कमाना चाहती है. नाम कमाने की चाह में उन्होंने छोटे पर्दे को अलविदा कहा और बड़े पर्दे का रुख़ किया. *रॉक ऑन* जैसी धमाकेदार फिल्म से शुरुआत की. उनकी बहुत प्रशंसा भी हुई. हाल ही में उनकी दूसरी फिल्म लाइफ पार्टनर भी रिलीज़ हो चुकी है. अब बड़े पर्दे पर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती प्राची की इच्छा है कि लोग उन्हें *कसम से* की बानी के नाम से नहीं प्राची देसाई के नाम से जाने. लोगों के दिल में उन्हें अभी भी एक युवा लड़की की इमेज बनानी बाक़ी है. वह अब अपनी उम्र के मुताबिक किरदार निभाना चाहती हैं. अब देखना बाक़ी है कि प्राची कब पुरानी पहचान मिटाने

नीतू का दीवाना शराबी

नीतू चंद्रा बॉलीवुड में तेज़ी से नाम कमाने वाली हीरोइनों में से हैं. ज़ाहिर है उनके दीवाने भी बढ़ते जा रहे हैं. हालांकि कुछ दीवाने ऐसे भी हैं जिनसे वह दूर ही रहना चाहेंगी. नीतू के दीवानों में अब शराबियों का नाम भी शुमार हो गया है. नशे में भी उनके चाहने वाले उन्हें पहचान ही लेते हैं. नीतू न सही उनकी गाड़ी से लिपट कर ही तसल्ली मिल जा रही है. दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में फिल्म *नो प्रोब्लम* की शूटिंग चल रही है. वहीं शराब के नशे में धुत एक फैन से नीतू की मुलाक़ात हो गई. वह भी पूरे फिल्मी तरीक़े से, दरअसल शूटिंग के बाद जब रात को नीतू कार से अपने होटल लौट रही थीं, तभी अचानक एक शराबी उनकी गाड़ी पर आ गिरा. जिस कारण उनकी कार सड़क से भटक गई और टकरा गई. इस हादसे में नीतू को चोट भी लग गई. नीतू और उनका ड्राइवर बिल्कुल हैरत में थे कि आख़िर यह कैसे हुआ. फिल्म के अभिनेता सुनील शेट्टी और संजय दत्त को यह बात पता चली तो वे भी वहां पहुंच गए. उन्होंने ही नीतू को अस्पताल पहुंचाया. लगता है नीतू का वक़्त सही नहीं चल रहा है. कोई–न–कोई विवाद उन्हें घेर ही लेता है. अभी कुछ दिनों पहले नीतू अपने हॉट फोटो–शूट को लेकर चर्चा का विषय बनी थी. वह शूट ऐसा था कि इसपर जमकर बवाल हुआ. उनपर अश्लीलता का आरोप भी लग गया था. यहां तक कि एमएनएस वाले भी उनके पीछे हाथ धो कर पड़ गए थे. वैसे नीतू को भी अब समझ में आ गया होगा कि सफलता अच्छी तो होती है लेकिन उसकी क़ीमत भी चुकानी पड़ती है. अब चाहे शराबी फैंस से निपटना पड़े या हंगामा करने वालों से, यहां सब जायज़ है. क्या करें नीतू जी इस मायानगरी का उसूल ही ऐसा है. तभी तो कहते हैं कि –इ है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ...

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

जब रणबीर मेट इम्तियाज़

पहले *जब वी मेट* और अब *लव आजकल*, निर्देशक इम्तियाज़ अली की तो धूम है. उनकी कामयाबी को देखते हुए हर अभिनेता उनके साथ काम करने को उत्सुक है. हो भी क्यों न, उनकी फिल्में जो इतनी सुपरहिट होती जा रही हैं और ख़ूब तारीफ़ें भी बटोर रही हैं. सुनने में आ रहा है कि रणबीर कपूर भी जल्द ही इम्तियाज़ अली के साथ काम करते हुए नज़र आएंगे. ऐसा रणबीर के पिता ऋषि कपूर का कहना है. उनका कहना है कि 2010 में रणबीर और इम्तियाज़ अली साथ–साथ होंगे. अभी एक फिल्म को लेकर बात तो चल रही हैं लेकिन कुछ अंतिम रूप लेना बाक़ी है. काम पूरा होते ही फिल्म की घोषणा कर दी जाएगी. ऋषि, अली की पिछली फिल्म लव आजकल में काम कर चुके हैं. उन्होंने इम्तियाज़ के निर्देशन की बहुत प्रशंसा की. अब वह भी चाहते हैं कि बेटे रणबीर इतने अच्छे निर्देशक के साथ काम करें. वैसे रणबीर के पिता का कहना है कि वह रणबीर के कामकाज में या फ़ैसलों में वह ज़रा भी हस्तक्षेप नहीं करते है. रणबीर ख़ुद ही निर्णय लेते हैं कि उन्हें किस फिल्म में काम करना है और किस में नहीं. रणबीर का इम्तियाज़ के साथ फिल्म करने का निर्णय उन्हें बहुत ही अच्छा लगा. जिससे ऋषि कपूर बेहद ख़ुश है. देखना यह है कि रणबीर–इम्तियाज़ की यह जोड़ी क्या गुल खिलाती है?

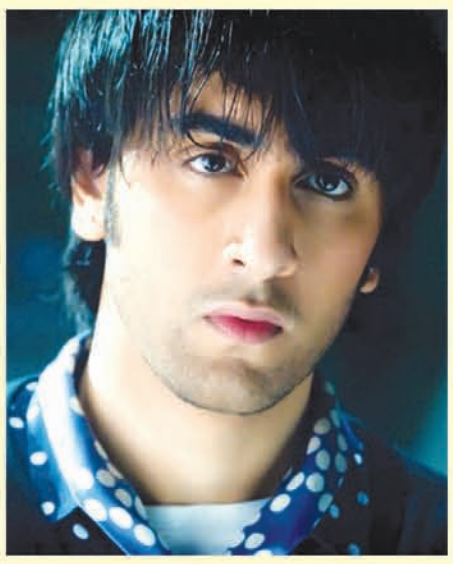

इतिहास रचा मल्लिका ने

जब बुरा समय आता है तो कोई साथ नहीं देता और जब अच्छा वक़्त आता है तो सभी तारीफ़ें करते नहीं थकते. ऐसा ही कुछ मल्लिका शेरावत के साथ हुआ है. काफी समय से तो वह बॉलीवुड से दूर थीं क्योंकि उनके पास फिल्में ही नहीं थी. अब लगता है कि उनका वक़्त बदल रहा है. हाल ही में वह बॉलीवुड की ऐसी पहली स्टार बन गई हैं जिन्हें अमेरिका की मानद नागरिकता मिली है. यह बॉलीवुड के लिए ऐतिहासिक बात है. ऐसा बॉलीवुड में पहली बार हुआ है कि उसके किसी सदस्य को ऐसे सम्मान से नवाज़ा गया हो. वैसे भी मल्लिका बड़ी ही बिंदास और सेक्सी हैं, उनकी फिल्म चले या न चले, उनके दीवानों की कमी नहीं है. मल्लिका भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय है. मल्लिका की तुलना बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों एंजलीना जॉली, जेनिफर लोपेज और एलिजाबेथ हर्ले से हो रही है. इधर विदेश में सम्मान मिला है और उधर मल्लिका की बॉलीवुड में भी वापसी हो रही है. उनकी नई फिल्म *हिस्स* तैयार है और जल्द ही दर्शकों के सामने होगी. यानी मल्लिका सच में राज कर रही हैं.

कृपया अपने सबस्क्रिप्शन चेक अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अपने नाम और पूरे पते के साथ यहां भेजें : (गैनन) के–2, दूसरी मंज़िल, चौधरी बिल्डिंग, मिडिल सर्किल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली –110001

वार्षिक शुल्क :1000 रु.